लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. XXXIX contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 15—मंगलवार 9 मार्च, 1965/19 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
332	सिंचाई के लिए भूमिगत जल	1307—09
333	अयस्क उतारने-चढ़ाने तथा जांचने का यन्त्र	1309—11
334	चीनी उद्योग को रियायत	1312—15
335	चावल मिलें	1316—19
336	केरल में राशन व्यवस्था	1319
338	केरल में खाद्य स्थिति	1320—22
337	केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद	1322—26
339	दिल्ली में आयात किये गये गेहूं का दिया जाना	1327—29
340	उड़ीसा में चावल की वसूली	1329—30
341	अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण	1330—31

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
342	दिल्ली की सहकारी संस्थायें	1331
343	राष्ट्रमंडल चीनी करार	1332
344	एयर इंडिया की सेवायें	1332
345	खाद्य सम्बन्धी अपराधियों का संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल)	1333
346	गन्ने का सम्भरण	1333—34
348	कर्मचारी भविष्य निधि योजना	1334
349	मत्स्य विपणन निगम	1334—35
350	कलकत्ता में राशन-व्यवस्था	1335
351	अनाज का फालतू भंडार	1335—36
352	खाद्यान्नों का आयात	1336

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 15—*Tuesday, March* 9, 1965/*Phalguna* 18, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Question Nos.*	*Subject*	PAGES
332	Ground Water for Irrigation . .	1307—09
333	Ore Handling and Screening Equipment	1309—11
334	Concession to Sugar Industry .	1312—15
335	Rice Mills . .	1316—19
336	Rationing in Kerala .	1319
338	Food Situation in Kerala . . .	1320—22
337	Translation of Central Acts into Hindi .	1322—26
339	Supply of Imported Wheat in Delhi	1327—29
340	Procurement of Rice in Orissa . .	1329-30
341	Distribution of Essential Commodities .	1330-31

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
342	Co-operative Societies of Delhi .	1331
343	Commonwealth Sugar Agreement	1332
344	Air India Services . . .	1332
345	Summary Trial of Food Offenders	1333
346	Supply of Sugar-cane . .	1333-34
348	Employees Provident Fund Schemes	1334
349	Fish Marketing Corporation	1334-35
350	Rationing in Calcutta .	1335
351	Buffer Stock of Foodgrains .	1335-36
352	Import of Foodgrains	1336

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
353	खाद्यान्न प्राप्त करना	1337
354	फ्रांस से गेहूं	1337–38
355	गेहूं के प्राप्ति मूल्य	1338

अतारांकित

प्रश्न संख्या

837	जयपुर में ऊन काटने का स्कूल	1338–39
838	राजस्थान को उर्वरक का सम्भरण	1339–40
839	सहकारी विधियां	1340–41
840	बड़गरा लाइट हाउस	1341
841	मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	1341–42
842	मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी .	1342–43
843	हरिजनों का कल्याण . .	1343
844	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानें	1343
845	हरिजनों की कानूनी सहायता	1344
846	अपाहिज व्यक्तियों का सर्वेक्षण	1344
847	गेहूं के तस्कर व्यापारी	1345
848	होटल विकास निधि	1345
849	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का पुनर्वर्गीकरण .	1345
850	कृषि संबंधी शिक्षा . .	1346
851	नाविकों के लिये भविष्य निधि योजना	1346–47
852	दिल्ली दुग्ध योजना	1347
853	दिल्ली दुग्ध योजना	1347–48
854	दिल्ली दुग्ध योजना	1348
855	गहन ढोर विकास खण्ड .	1349
856	चीनी उद्योग का लागत ढांचा	1349
857	पशुपालन सम्बन्धी कार्यकारी दल	1350
858	सहकारी परिवहन समितियां	1350
859	पक्षियों का परिरक्षण	1350
860	सहकारी भ-बन्धक बैंक .	1351
861	दिल्ली में चावल मूल्य नियंत्रण	1351
862	राजधानी में दूध सम्भरण	1352
863	चुकन्दर से चीनी	1352–53

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
353	Procurement of Foodgrains	1337
354	Wheat from France .	1337–38
355	Procurement Prices of Wheat	1338

Unstarred Questions Nos.		
837	Wool Shearing School at Jaipur .	1338–39
838	Supply of Fertilizer to Rajasthan .	1339–40
839	Co-operative Laws	1340–41
840	Lighthouse at Badagara . . .	1341
841	Welfare of S.Cs and S.Ts in Mysore State . .	1341–42
842	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students in Mysore State	1342–43
843	Harijan Welfare	1343
844	I.A.C. Flights . .	1343
845	Legal Aid to Harijans .	1344
846	Survey of the Handicapped	1344
847	Wheat Smugglers .	1345
848	Hotel Development Fund . . .	1345
849	Regrouping of Scheduled Castes and Tribes .	1345
850	Agricultural Education . . .	1346
851	Provident Fund Scheme for Seafarers .	1346–47
2	Delhi Milk Scheme	1347
853	Delhi Milk Scheme	1347–48
854	Delhi Milk Scheme . . .	1348
855	Intensive Cattle Development Blocks	1349
856	Cost-Structure of Sugar Industry	1349
857	Working group on Animal Husbandry .	1350
858	Co-operative Transport Societies .	1350
859	Preservation of Birds . . .	1350
860	Co-operative land Mortgage Banks	1351
861	Price control on rice in Delhi	1351
862	Milk Supply in Capital	1352
863	Sugar from Beet-root .	1352–53

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
864	आदिवासियों की समस्यायें	1353–54
865	बर्मा से बीजी आलुओं का आयात	1354
866	पंजाब को गेहूं का सम्भरण	1354–55
867	न्ने का भाव	1355
868	भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता	1355–56
869	दूध की कमी	1356
870	पर्यटन सम्बन्धी प्रशिक्षण	1356
871	राज्यों को अनाज का भेजा जाना	1356–57
872	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे .	1357
873	बम्बई बन्दरगाह के क्रेनमैनों द्वारा हड़ताल	1357–58
874	राजस्थान का रेगिस्तान	1358
875	तिमाही अंशदान कार्ड प्रणाली	1358–59
876	नेपाल से अनाज का लाया जाना	1359
877	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	1359–60
878	पत्रकारों की शिक्षा सम्बन्धी यात्रायें	1360
879	पर्यटन केन्द्रों के लिए वृहद् योजना	1360–61
880	नारियल उत्पादन .	1361–62
881	उर्वरकों के स्टाक का जमा होना	1362
882	सहकारी खेती . .	1362–63
883	उड़ीसा में अनधिसूचित जातियों का कल्याण	1363–64
884	उड़ीसा में आदिवाही खंड	1364–65
885	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रावास . .	1365
886	भारत का भूमि सर्वेक्षण मानचित्र	1365–66
887	विश्व बैंक के परिवहन विशेषज्ञ	1366
888	नेशनल शुगर मिल्स लिमिटेड	1366
889	बीज के फार्म .	1367
890	गेहूं और चावल के दाम	1367
891	डेयरी विकास परिषद्	1367–68
892	भारतीय नौवहन टन भार	1368
893	राजस्थान के कमी वाले क्षेत्र	1369
894	अगरतला-कलकत्ता विमान किराया	1369
895	कृषि वर्ग की संग्रह क्षमता	1370

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
864	Tribal problems.	1353—54
865	Potato Seeds from Burma .	1354
866	Supply of Wheat to Punjab	1354—55
867	Prices of Sugarcane	1355
868	Legal aid to Landless poor	1355—56
869	Shortage of Milk	1356
870	Training in Tourism .	1356
871	Food Supplies to States	1356—57
872	International Airports . .	1357
873	Strike by Cranemen of Bombay Port	1357—58
874	Rajasthan Desert . . .	1358
875	Quarterly System of Contribution Cards	1358—59
876	Movement of Foodgrains from Nepal .	1359
877	Employees' Provident Fund Act .	1359—60
878	Educational Tours of Journalists .	1360
879	Master Plan for Tourist Centres .	1360—61
880	Coconut Production .	1361—62
881	Accumulation of Fertilizers	1362
882	Co-operative Farming. . .	1362—63
883	Welfare of Denotified Tribes in Orissa	1363—64
884	Tribal Blocks in Orissa . .	1364—65
885	Hostels for S.C. and S.T. in Orissa	1365
886	Soil Survey Map on India .	1365—66
887	World Bank Transport Experts	1366
888	National Sugar Mills Ltd. .	1366
889	Seed Farms .	1367
890	Prices of rice and wheat .	1367
891	Dairy Development Council	1367—68
892	Indian Shipping Tonnage .	1368
893	Scarcity Areas in Rajasthan	1369
894	Agartala-Calcutta Air Fare . . .	1369
895	Hoarding potentiality of Agricultrist Class	1370

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
896	देहाती-जनसंख्या	1370–71
897	उड़ीसा में पैकेज प्रोग्राम	1371
898	गुजरात के वनों में गिर शेर	1371–72
899	धान की खेती	1372
900	उर्वरक की मांग	1372–73
901	कृषि के आधुनिक औजारों को लोकप्रिय बनाना	1374
902	चुकन्दर	1374

निधन सम्बन्धी उल्लेख--

(श्री आर० नारायणस्वामी) 1374–75

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न) 1375

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 1375–77

पाकिस्तान के डाकुओं द्वारा पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित राजस्थान के गांवों में हरिजनों की बड़ी संख्या में हत्या तथा उन पर हमले के समाचार

श्री बूटा सिंह 1375–76

श्री हाथी 1376–77

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1377

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव 1378

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा 1378—1421

श्री गो० ना० दीक्षित 1379

श्री सोनावने 1379–80

श्री राजदेव सिंह 1380–81

श्री ओंकार लाल बेरवा 1381–82

श्री विश्वनाथ पाण्डेय 1382–83

श्री सिंहासन सिंह 1383–84

श्री राजाराम 1384–85

श्री प्रतापसिंह 1385

श्री जो० ना० हजारिका 1386–87

श्री नवल प्रभाकर 1387–88

श्री स० का० पाटिल 1388

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
896	Rural Population .	1370-71
897	Package Programme in Orissa	1371
898	Gir Lions in Gujarat Forest	1371-72
899	Paddy Cultivation . . .	1372
900	Demand of Fertilizers.	1372-73
901	Popularisation of improved Agricultural Implements	1374
902	Beet Roots	1374
Obituary reference—		
	(Shri R. Narayanaswami)	1374-75
Re: Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .		1375
	Detention of Communists in Kerala . .	1375
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .		1375-77
	Reported large-scale killing of and assault on Harijans residing in Rajasthan villages bordering Pakistan by dacoits of Pakistan—	
	Shri Buta Singh .	1375-76
	Shri Hathi .	1376-77
	Papers laid on the Table	1377
	Motion of no-confidence in the Council of Ministers . .	1378
	Railway Budget—General Discussion . .	1378--1421
	Shri G. N. Dixit .	1379
	Shri Sonavane .	1379-80
	Shri Rajdeo Singh . . .	1380-81
	Shri Onkar Lal Berwa . .	1381-82
	Shri Vishwa Nath Pandey .	1382-83
	Shri Sinhasan Singh . .	1383-84
	Shri Rajaram . . .	1384-85
	Shri Pratap Singh . .	1385
	Shri J. N. Hazarika .	1386-87
	Shri Naval Prabhakar .	1387-88
	Shri S. K. Patil . .	1388-1400

अनुदानों की मांगें, (रेलवे), 1965-66

श्री नरेन्द्र सिह महीड़ा . . . 1400--02

श्री य० ल० जाधव 1402-03

श्री राधेलाल व्यास . . . . . 1403—05

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . . . . 1405—07

श्री हेडा 1421

Subject PAGE

Demands for Grants (Railways): 1965-66

Shri Narendra Singh Mahida . . . . . 1400—02

Shri M.L. Jadhav . . . . . 1402—03

Shri Radhelal Vyas . . . . . 1403—05

Shrimati Renu Chakravartty . . . . . 1405—07

Shri Heda 1421

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 9 मार्च, 1965 / 18 फाल्गुन, 1886 (शक)
Tuesday, March 9, 1965 / Phalguna 18, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWARS TO QUESTIONS

सिंचाई के लिए भूमिगत जल

+

*332. **श्री सुरेन्द्रपालसिंह :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विभति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **क्या खाद्य तथा** कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंचाई के लिये अधिक से अधिक मात्रा में भूमिगत जल निकालने के कार्य में सहायता करने के लिये देश में भूमिगत जल के अध्ययन में सहायता करने तथा अध्ययन आरम्भ करने और उस की वैज्ञानिक खोज करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० वव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रस्तावित योजना का अभिप्राय भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा पड़ताल के बारे में एक नियमित कार्यक्रम तैयार करना है जिसे राज्य सरकारें एक निर्धारित आधार पर क्रियान्वित करेंगी जिससे कि भूमिगत जल की क्षमता वाले ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जा सके जिन में

खोदे हुए कुओं, खोदे एवं बोर किए हुए कुओं तथा कम गहरे कुओं से भूमिगत जल के निकास की क्षमता हो । यह कार्यक्रम निम्नलिखित के लिये पर्याप्त तकनीकी दित्ता इक्ट्ठा करने में सहायता देगा :—

(क) कृषकों का निम्न विषयों में तकनीकी मार्गदर्शन करना : —

(1) खोदे हुए कुओं / नलकूपों के साइज़, टाइप ' अन्तरण तथा उनकी सघनता ।

(2) खोदे हुए कुओं के कार्य क्षेत्र, टाइप तथा बोरिंग की विधि तथा उन्हें गहरा करना ताकि जल निकास की क्षमता बढ़ सके ।

(3) कुओं पर लगाने के लिये उपयुक्त जल-उठाव उपकरणों का चुनाव ।

(ख) कुओं/नलकूपों के निर्माण को नियमित करना ताकि कुओं के अधिकर्ष तथा फेल होने का खतरा न रहे ।

वैज्ञानिक आधार पर योजनाओं की तैयारी के लिये कुछ "गाईड लाइनें" तैयार करके उन्हें राज्य को भेज दिया गया है । इन गाईड लाइनों के आधार पर राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही वित्तीय सहायता की मात्रा तथा प्रतिमान तय किये जायेंगे ।

श्री सुरेन्द्र पालसिंह : वार्षिक वर्षा और अन्य पहलुओं के आधार पर किए गए मोटे अनुमानों के अनुसार देश में भूमिगत जल की मात्रा लगभग कितनी है और अब तक उसमें से कितनी प्रतिशत जल सिंचाई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): अनुमान यह है कि अभी इस्तेमाल योग्य कुल भूमिगत जल का 30 प्रतिशत इस्तेमाल किया जा रहा है और 70 प्रतिशत के लिए अभी साधन जुटाने हैं ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या देश में जलग्रस्त भूमि और खारेपन की समस्या हल करने में भूमिगत जल के विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन से लाभ होगा और यदि हां, तो किस रूप में और किस हद तक ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस में जलग्रस्त भूमि भी शामिल होगी क्योंकि एक बार भूमिगत जल की उपलब्धता के बारे में पता लगाने पर, फालतू पानी की बजाय, जिस से जलग्रस्तता बढ़ती है, यह भूमिगत जल सिंचाई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या कोई फ्रांसीसी सार्थ वैमानिक सर्वेक्षण के जरिए भूमिगत जल का पता लगाने में सहायता देने को राजी है और क्या दक्षिणी पठार में, जहां परम्परागत नलकूप नहीं लगाए जा सकते, कोई नये प्रकार के नलकूप लगाए जाऐंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : किसी फ्रांसीसी प्रस्ताव के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है । कुछ कहने से पहले मुझे इस बारे में पता लगाना पड़ेगा ।

श्री विभूति मिश्र : फव्वारा-कुएं किन क्षेत्रों में खोदे जा सकते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं एकदम इस बारे में नहीं बतला सकता ।

श्री क० ना० तिवारी : पानी बर्बाद बहुत होता है । अतः क्या सरकार भूमि की सिंचाई के लिए छिड़काव पद्धति पर विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न तो भूमिगत पानी की उपलब्धता के सर्वेक्षण के बारे में है । परन्तु छिड़काव पद्धति पर भी विचार किया जा रहा है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the total amount spent on this scheme ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अभी अनुमान नहीं लगाया गया है । हम विभिन्न राज्यों से आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या सरकार जल-अनुमाताओं की सेवाओं का उपयोग करेगी जैसा कि गुजरात सरकार और अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि पानी के बारे में अनुमान लगाना भी उतना ही वैज्ञानिक है जैसा कि इसका दावा किया जाता है । हम भूमिगत जल के सर्वेक्षण के लिए जल-शास्त्रियों, विभिन्न इंजीनियरों और उपलब्ध वैज्ञानि आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जल-अनुमाता, पानीवाला महाराज की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार करेगी जो कि, जब वह भारत सरकार की नौकरी में था, बड़ा सफल रहा ?

अध्यक्ष महोदय : यह जल-अनुमाताओं में शामिल है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जहां पर पानी की सतह नीची है, क्या सरकार उन स्थानों में जल की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक पृथक संगठन स्थापित करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां ; सर्वेक्षण से पता चलेगा कि पानी की सतह कहां है । इस से गहरे पानी के बारे में भी पता लगेगा ।

अयस्क उतारने-चढ़ाने तथा जांचने का यंत्र

*333. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल पश्चिम अफ्रीकी देशों में वहां के चार बन्दरगाहों पर लगे हुए अयस्क उतारने-चढ़ाने तथा जांचने के यंत्रों का अध्ययन करने गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने देशों की यात्रा की ;

(ग) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है ; और

(घ) रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

पत्तन और माइनिंग इंजीनियरों का एक शिष्ट मण्डल जनवरी, 1965 में इटली, मोरेतानियां, गायना और लाइबेरिया की यात्रा करने के लिये भेजा गया था । इस यात्रा का उद्देश्य इटली के तरांटो पत्तन, मौरैतानियां के इटीने पत्तन, गायना के कौलाकी पत्तन और लाइबेरिया के मानरोविया और बुकानन पर स्थित लौह धातुक के खनन, छानने और चढ़ाने-उतारने के संस्थानों के काम का अध्ययन करने और शिष्ट मंडल को आधुनिक पूर्णरूप से चालू और परिचालित धातुक के खनन और चढ़ाने-उतारने के संस्थानों से परिचित कराने का था । इस दल ने जिन विभिन्न धातुक के संस्थानों को देखा, उन के तकनीकी तथ्यों पर टिप्पणियां तैयार की हैं, जिस से भारतीय पत्तनों पर के धातुक संबंधी परियोजनाओं का विकास करने में उन से निर्देशन प्राप्त हो सके। इस दल ने विभिन्न पत्तनों से निर्यातित मात्रा, धातुक के संयंत्रों के विभिन्न भागों की वास्तविक क्षमता, स्टाक यार्ड की क्षमता, प्रयोग में लाई गयी वैगनों की किस्म और अन्य संबंधित तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि अयस्क उतारने-चढ़ाने में जापान में कुछ पत्तनों पर बड़े यंत्र लगे हैं और यदि हां, तो हमारे दल को जापान के पत्तनों पर न भेज कर अन्य देशों के पत्तनों पर भजने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : जापान एक अयस्क आयात करने वाला देश है और वहां पर यंत्र लगे हुए हैं । हमें लौह-अयस्क के निर्यात के लिए यंत्र लगाने हैं। अतः यह बड़ा आवश्यक है कि हम अपने तकनीशन उन देशों को भजें जो बड़ी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात करते हैं, यदि हम अयस्क-निर्यात करने वाले देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहें ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि उन पत्तनों पर, जिनका दौरा किया गया है, अयस्क उतारने चढ़ाने का काम हमारी अपेक्षा कम खर्चीला और यंत्रीकृत है और यदि हां, तो क्या हम अपनी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की पत्तनों को उनकी तरह आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : हम लौह-अयस्क व्यापार को बढ़ा रहे हैं और लौह-अयस्क के निर्यात के लिए मशीनी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । हम विशाखापत्तनम में एक संयंत्र लगा रहे हैं जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 60 लाख टन से 80 लाख टन तक होगी । अतः हम इस समय उन देशों की तुलना नहीं कर सकते जिनका लौह-अयस्क निर्यात व्यापार पहले ही विकसित है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस दल ने जो रिपोर्ट पेश की है, सरकार उस पर कब तक फैसला करेगी और जहां तक इस दल द्वारा पड़ताल का सम्बन्ध है, क्रियान्विति के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे ?

श्री राज बहादुर : निरन्तर विदेशी सलाहकारों, विदेशी तकनीशनों और विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने पर निर्भर करने की बजाय हम ने यह उचित समझा कि हमारे विशेषज्ञ वहां जाएं और यंत्रीकृत उपकरणों और सुविधाओं और जांच के तरीकों और अन्य सम्बन्धित बातों का अध्ययन करें।

Shri Bhagwat Jha Azad : Before the Government take action on the Report, has a study of the conditions prevailing in our country and abroad been made so as to provide here the facilities which are available there ?

Shri Raj Bahadur : The object was to study the facilities available and then to attempt to provide those facilities here.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन विदेशी पत्तनों पर हमारे विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन के फलस्वरूप क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इस आधुनिक संयंत्र को लगाने पर कितना रुपया खर्च होगा और यह संयंत्र आयात करना पड़ेगा या यह देश में बनाया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया कि हम विशाखापत्तनम में एक संयंत्र लगा रहे हैं। हम अपने वित्तीय साधनों और विदेशी मुद्रा के साधनों के भीतर इसको यथा संभव क्रियाकारी बनाना चाहते हैं। इस योजना पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मैं समझता हूं कि यह संयंत्र अप्रैल अथवा मई में चालू हो जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता था कि इस संयंत्र का आयात करना पड़ेगा या यह देश में ही बनेगा ?

श्री राज बहादुर : अधिकांश मशीनी उपकरणों का आयात करना होगा

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विभिन्न पत्तनों के सर्वेक्षण के फलस्वरूप किस पत्तन का और किस प्रकार का यंत्रीकरण सरकार को पसन्द आता है जो हमको स्वीकार्य हो ?

श्री राज बहादुर : उन्होंने तकनीकी टिप्पणियां तैयार की हैं। टाइप वगैरह के बारे में मेरे लिए कुछ भी कहना संभव नहीं है। उचित रूप से अध्ययन करने के बाद, यह तो उन्होंने देखना है कि जो उपकरण लगाया जा रहा है उसमें क्या सुधार अथवा परिवर्तन किये जा सकते हैं।

चीनी उद्योग को रियायत

+

*334. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री हेडा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ और खांडसारी एककों के मुकाबले में चीनी उद्योग की स्पर्धा क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से चीनी उद्योग को कुछ नयी रियायतें देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये रियायतें ठीक-ठीक क्या और कितनी हैं; और

(ग) इससे चालू वर्ष में चीनी उत्पादन का लक्ष्य कहां तक प्राप्त होने की सम्भावना है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार ने शर्करा उद्योग को निम्न प्रोत्साहन दिये हैं :—

1. शर्करा कारखाने अक्तूबर-नवम्बर, 1964 में 1962 की उसी अवधि से जितना अधिक शर्करा का उत्पादन करेंगे उस पर मूल उत्पादन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ;
2. शर्करा कारखाने जनवरी-जून, 1965 में 1964 की उसी अवधि से जितना अधिक शर्करा का उत्पादन करेंगे उस पर निम्न प्रकार से मूल उत्पादन शुल्क में छूट दी जाएगी :—
   (1) पहले 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन पर 20 प्रतिशत की दर से छूट ;
   (2) अगले 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन पर 40 प्रतिशत की दर से छूट; और
   (3) शेष अधिक उत्पादन पर 50 प्रतिशत की दर से छूट ।

(ग) चालू वर्ष के लिए शर्करा उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन के आस-पास होने की आशा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मिलों को अधिकतम कितनी रियायत मिलेगी और मिलें किस अधिकतम मूल्य पर गन्ना खरीद सकेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जो रियायत मिलेगी, वह अधिक उत्पादन पर निर्भर करेगी । इस बारे में अब हिसाब नहीं लगाया जा सकता । मुझे विश्वास है कि हर मिल अपनी क्षमता का हिसाब लगायेगी और उसके आधार पर वे गन्ने के लिए अधिक मूल्य देंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गुड़ और खंडसारी पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जा रहा है ताकि खंडसारी के लिए गन्ना दिए जाने से अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न हो और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस समय गुड़ के उत्पादन, विक्रय अथवा वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री रा० गि० दुबे: क्या इन रियायतों का चीनी की अपेक्षा खंडसारी और गुड़ के चालू बाजार भाव पर कोई प्रभाव हुआ है ?

श्री चि0 सुब्रह्मण्यम : सामान्यत: इस समय गुड़ और खंडसारी के मूल्य गिर रहे हैं । अत: चीनी मिलों को अधिक गन्ना मिल रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have the Government made an assessment about the total production of *gur* and *Khandsari* ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गुड़ और खंडसारी के उत्पादन आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that there were losses by two ways after the concessions offered by the Government in November last, on the one side there was loss of recovery and on the other the cane producer could not get the desired benefit ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह कारखानों को प्रोत्साहन देने के बारे में हैं । हमने गन्ना उत्पादकों को इस सीज़न में अधिक मूल्य देकर प्रोत्साहन दिया है ।

Shri Bibhuti Mishra : The producers get price on the basis of recovery. As the recovery then was less, so they got less price. The loss to Government was in respect that they had to give concession while the production of sugar was less. Is it a fact ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पहले 9·4 प्रतिशत रिकवरी पर मूल्य 1·86 रुपये था । अब 10·4 प्रतिशत पर 2 रुपये है । विभिन्न राज्य सरकारों ने इसी मूल्य का सुझाव दिया था । हमने इसे स्वीकार कर लिया और मूल्य निर्धारित कर दिये ।

Shri Rameshwar Tantia : The Government gives protection to khadi and Handloom industries but here do they not put in trouble the small producers of *gur* and *khandsari* by giving concession to big sugar mills ? Are the Government not going back of their policy of giving protection to small industries ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में कारखाने में बनी चीनी पर उत्पादन-शुल्क बहुत लगता है। इस से गुड़ और खंडसारी को प्रतिस्पर्धा शक्ति मिलती है। यही कारण है कि उनको चीनी कारखानों की अपेक्षा अधिक गन्ना मिल रहा है। वास्तव में यह संरक्षण कुटीर उद्योगों को दिया गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : पीली चीनी अथवा खण्डसारी का उत्पादन बढ़ाने और इसे निर्यात के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे देश के बाहर खंडसारी की अच्छी मंडी नहीं है। लेकिन कारखानों में उत्पादित कच्ची चीनी की अच्छी मांग है। अतः इसके लिए निर्यात बाजार ढूंढने का कोई लाभ नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Do the Government know that *khandsari* producers in villages purchased sugarcane at the rate of Rs. 3·50 paise per maund ? May I know the benefit which is being given to producers out of the concession offered for sugar and *khandsari* ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये हैं। यह तो चीनी मिलों पर है कि वे गन्ने के अन्य खरीदारों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इससे अधिक मूल्य दें। यह निर्णय करना तो हर चीनी मिल पर है कि यह कितना दे और क्या कोई अधिक मूल्य दे। हमने केवल न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये हैं।

श्री सिंहासन सिंह : क्या चीनी उद्योग को दी जाने वाली रियायत उनके अभ्यावेदन करने पर स्वीकार की गई है और क्या चीनी के मूल्य निर्धारित करने में सरकार राब और चेपरा के मूल्यों को भी ध्यान में रखती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चीनी का मूल्य 1955–56 में तैयार किए गये प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित किया गया है। हमने इस मामले को पुनः एक अन्य आयोग को, जिसका नाम सेन आयोग है, सौंपा है, जो कारखानों में चीनी के उत्पादन और मूल्य के समूचे प्रश्न पर विचार करेगा। अतः इस समय वही सिद्धान्त अपना रहे हैं जो उपलब्ध हैं।

श्री सिंहासन सिंह : मैंने यह पूछा था कि क्या चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय राब आदि और अन्य उपोत्पादों के मूल्यों पर भी विचार करती है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा ख्याल है कि प्रशुल्क आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने केवल रिकवरी के पहलू और कार्यविधि पर ही ध्यान दिया है। अब मुझे विश्वास है कि सेन आयोग बिक्री के योग्य अन्य कच्चे माल पर भी विचार करेगा।

श्री सिंहासन सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दो बार प्रश्न पूछा है। श्री शिवनंजप्पा।

श्री सिंहासन सिंह : वे इस राब से धन कमाते हैं।

श्री शिवनंजप्पा : क्या चीनी मिलों के 20 मील की दूरी तक गन्ना अर्जित करने की पद्धति अब भी लागू है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मुझे पता है कोई अर्जन नहीं हो रहा है ।

श्री अ० प्र० जैन : नवम्बर के महीने में बाजदफा गन्ने से रिकवरी घट कर 7.5 प्रतिशत रह जाती है और यदि वही गन्ना दिसम्बर और जनवरी में होता है तो 10 अथवा 10·5 प्रतिशत रिकवरी होती है, अतः समय से पूर्व गन्ना पेरने को प्रोत्साहन देना राष्ट्र-विरोधी है क्योंकि इससे चीनी कम बनती है । यदि ऐसा है तो सरकार ने नवम्बर के महीने में गन्ना पेरने को किन कारणों से प्रोत्साहन दिया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम कुछ पहले उत्पादन करना चाहते थे । हमें पता था कि रिकवरी कम होगी; लेकिन प्रश्न मौजूदा गन्ने को इस्तेमाल करने और चीनी की कमी वाले इन महीनों में चीनी तैयार करने का था । हमारे भंडार में भी चीनी बहुत कम हो गई थी ।

Shri Rameshwaranand : In areas where the cane is produced in abundance, the mills are not taking canes which is resulting in its getting dry and lack of fodder for cattles. Are the Government trying to give licences for *khandsari* to them so that the cane is not dried and there is production of *khandsari* ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस मामले पर तो राज्य सरकार विचार करेगी कि उन क्षेत्रों में लाइसेंस दें, जहां गन्ने की मांग नहीं है ।

Shri Rameshwaranand : Would the Government give them some instructions ?

Mr. Speaker : Certainly.

श्री स० मो० बनर्जी: क्या यह सच है कि चीनी उद्योग को रियायत दिये जाने के बाद न तो उन्होंने उत्पादन लागत में कमी की है और न ही उन्होंने गन्ना उत्पादको को अधिक मूल्य दिये हैं ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है कि वे कम से कम एक बात पर तो राजी हों ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस अवधि में उत्पादन बढ़ा है । वास्तव में, अब कुछ चीनी मिलें अधिक दूरी से चीनी भेज सकती हैं क्योंकि उन्हें यह रियायत मिली है । अतः बहुत से कारखानों में उत्पादन बहुत बढ़ा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने उत्पादन के बारे में प्रश्न नहीं पूछा है । उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैंने तो उत्पादन लागत के बारे में पूछा है कि क्या उत्पादन लागत कम हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसका उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमने तो उत्पादन-शुल्क में रियायत दी है । उत्पादन-लागत हर मिल की कुशलता पर निर्भर करती है ।

*335. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामनाथन् चट्टियार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री कोया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पाराशर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व जर्मनी तथा जापान को, छः आधुनिक चावल मिलों का आयात करने के लिए आर्डर दे दिये हैं ताकि धान से चावल अधिक मात्रा में निकाला जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना पूंजी परिव्यय होने का अनुमान है; और

(ग) क्या ये मिलें हाल में बने भारत के खाद्य निगम द्वारा चलाई जायेंगी अथवा सहकारी क्षेत्र में मिलों की स्थापना करने के लिए मशीनें राज्य सरकारों को दे दी जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) धान से अधिक चावल निकालने के लिए छः आधुनिक चावल मिलों का आयात करने के लिए पश्चिमी जर्मनी और जापान को आर्डर दिये गये हैं ।

(ख) अनुमानित निर्धारित पूंजीगत परिव्यय रु० 137 लाख है। यह राशि उपकरण, भूमि, इमारत, साइलों का निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित मिश्रित खर्चे करने के लिए है ।

(ग) इन छः आधुनिक चावल मिलों में से 5 मिलें सहकारी समितियों द्वारा 5 सघन कृषि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में चलाई जाएंगीं जब कि शेष एक मिल सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में चलाई जाएगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : इन मिलों को स्थापित करने और इनमें उत्पादन प्रारम्भ करने में सरकार को कितना समय लगेगा ? चावल का सीज़न शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : पहली मिल में अगले महीने उत्पादन शुरू हो जाएगा । यह मिल मद्रास में होगी । अन्य मिलों में इसके दो या तीन महीनों बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कुछ सहकारी संगठनों और सहकारी विपणन समितियों ने यह प्रार्थना की है कि इन मिलों की संख्या पर्याप्त नहीं है और इनको बढ़ा कर 12 किया जाए ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह केवल यह पता लगाने के लिए एक बृहत योजना है कि क्या इन एककों की ओर से कही गई बातें सच हैं। यदि ऐसा है तो केवल बारह ही नहीं बल्कि और अधिक मिलें स्थापित की जाएंगी ताकि सारा काम इन कुशल मिलों में कराया जा सके ।

Shri Yashpal Singh : The Government already knows that Rurkee in U.P. is the largest rice producing centre. Will any of these six mills be established in Rurkee ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। निकट भविष्य में जब हम मिलों की संख्या बढ़ाएंगे तो अन्य सभी के दावों पर विचार करेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशेषत: खाद्यान्नों के लिए सहकारी भंडार खोलने से सहकारी समितियों ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने सहकारी समितियों के ये मिलें चलाने के लिए विशेष सुविधाएं देने की कोई योजना बनाई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में, इन 6 मिलों में से 5 सहकारी विपणन समितियों द्वारा स्थापित की जा रही हैं ।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जहां तक चावल मिल उद्योग का सम्बन्ध है वहां पर काफी क्षमता बेकार पड़ी है और चावल मिलों के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उस सब का निर्माण हमारे देश में होता है, फिर सरकार ने इन वस्तुओं को विदेशों से मंगाने पर 137 लाख रुपया खर्च करना क्यों उचित समझा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : 137 लाख रुपया विदेशी लागत नहीं है। इसमें भूमि, इमारत और अन्य वस्तुओं की लागत शामिल है। बाहरी लागत तो बहुत थोड़ी है। यह दावा किया गया है कि ये आधुनिक मिलें 7 से 8 प्रतिशत तक अधिक चावल का उत्पादन कर सकेंगी। यदि यह बात सत्य है तो इससे यह 137 लाख रुपये की समूची रकम वसूल हो जाएगी। इसीलिए हम यह पता लगाने के लिए ये मिलें स्थापित कर रहे हैं कि क्या इसमें 7 से 8 प्रतिशत तक बचत होगी और यदि ऐसा है, तो अधिक मिलें स्थापित की जाएंगी ताकि चावल के उत्पादन में बचत हो सके ।

श्री प्र० चं० बरुआ : बड़े पैमाने पर इन आधुनिक चावल मिलों की स्थापना से हाथ से चावल कूटना उद्योग किस हद तक समाप्त होगा और क्या इसके फलस्वरूप बेरोजगारी होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हाथ से चावल कूटना उद्योग को समाप्त करने में काफी समय लगेगा। वास्तव में यह अब पुराना पड़ता जा रहा है। और अब अन्य रोजगार भी उपलब्ध हैं। अभी भी देश के कुछ भागों में हाथ से चावल कूटने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसको समाप्त करने में काफी समय लगेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इससे बेरोजगारी होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इससे बेरोजगारी नहीं होगी ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has replied in reply to question of Shri Ranga that the production of rice will increase by 6 or 7 per cent. If the existing rice mills in the country are modernised, will it not be beneficial to the Government ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन एककों को स्थापित करने तथा उनके द्वारा किए गए काम को देखने के पश्चात् हम विचार करेंगे कि क्या वर्तमान मिलों को आधुनिक बनाया जा सकता है अथवा नये एककों की ही स्थापना करनी पड़ेगी । पहले तो सिद्ध करना होगा कि नये एकक वर्तमान एककों से अधिक कार्यकुशल हैं ।

Shri Rameshwar Tantia : The hon. Minister has said that the recovery of rice will increase by 6 or 7 per cent. May I know whether this has not come in the notice of the Government before ? The shortage of rice in the country is since long. Whether these machines were not available previously and that they have thought of them now ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस परियोजना पर पिछले दो या तीन वर्षों से विचार हो रहा था । एक तकनीकी रिपोर्ट सरकार को पेश की गयी थी उस पर विचार किया गया और इस वर्ष इस को कार्यान्विति के लिये स्वीकार किया गया है ।

श्री तिरुमल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह एकक मार्किटिंग फेडरेशनों को दी जायेगी । क्या सरकार के पास इन फेडरेशनों की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में पूर्वजानकारी है ? क्या इन के विरुद्ध गबन अथवा अन्य प्रकार के आरोप तो नहीं हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम अपनी ओर से यह काम नहीं कर रहे हैं । हमें राज्य सरकारें सिफारिशें भेजती हैं । वे पहले इस पर विचार करती हैं और इसके बाद इनके आवंटन के बारे में अनुमति देती हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच है कि इंडियन राइसमिलिंग मैनूफैकचरिंग इक्यूपमट एसोसियेशन ने विदेशी निर्माताओं के इस दावे का खण्डन किया है कि भारत में बन रही मशीनों से विदेशों में बनी मशीनें अच्छी हैं ? और यदि यहां बन रही मशीनों में कुछ परिवर्तन कर दिये जायें तो विदेशी मशीनों जैसी कार्यकु शलता प्राप्त की जा सकती है । यदि हां, तो क्या विदेशी निर्माताओं को आर्डर देने से पहले भारतीय निर्माताओं के इस दावे के बारे में जांच की गई थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात तभी सिद्ध की जा सकती है कि जब हमारे यहां नये एकक स्थापित हो जायें और उन का कार्य देख[लिया जाये । इसीलिये 6 एककों का आर्डर दिया है और उन को देश के विभिन्न भागों में स्थापित कर के देखा जायगा कि क्या इन मिलों में देसी मिलों से 7 या 8 प्रतिशत अधिक उत्पादन होता है या नहीं । यह आरंभिक परियोजना के समान है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : एक और अवसर की प्रतीक्षा करें ।

Shri Sheo Narain : I want to know why a mill is not being established in Eastern U.P. which is a rice producing centre. I want to know the difference between the working of German and Japanese machines.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सिद्धांत रूप से जापानी और पश्चिमी जर्मनी की मशीनें एक जैसा ही हैं। परन्तु फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। इसी कारण हम दोनों से मशीनें मंगा रहे हैं। उस के पश्चात यह भली प्रकार पता लगाया जा सकेगा कि दोनों में कौन सी मशीन अच्छी है और देसी मशीनों से यदि वे अच्छी हैं तो कितनी ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister has said that it would be considered whether we should import them on large scale or not. I want to know the basis for this. It is according to his information or an estimate has been made as to how far the demands of the country are being met ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि उनके दावे ठीक हैं तो धान के उतने ही उत्पादन से इस मशीन से 7 से 8 प्रतिशत चावल का उत्पादन बढ़ जायेगा। इसीलिये यह जानने के लिये कि चावल का उत्पादन बढ़ेगा या नहीं, यह परियोजना चालू की जा रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से रायपुर के निकटवर्ती क्षेत्र के चावल मिल मालिकों ने यह कोशिश की है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में सहकारी चावल मिलें स्थापित न करें। यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस प्रधान को उन्होंने 1,11,000 रुपये की थैली दी है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नये एकक लगाने के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न संख्या 336 और प्रश्न संख्या 338 एक साथ लिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

केरल में राशन व्यवस्था

\+

*336. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में परिनियत राशन व्यवस्था लागू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). केरल में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने और चावल की एकाधिकार खरीदारी करने का प्रश्न राज्य खाद्य सलाहकार समिति की बैठकों में उठाया गया था। वर्तमान अनौपचारिक राशन-व्यवस्था से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रख कर बाद में इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

केरल में खाद्य स्थिति

*338. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खाद्य स्थिति में सुधार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यक्ति को कुल कितना अनाज दिया जाता है ; और

(ग) राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से कुल कितने व्यक्तियों को अनाज दिया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) 320 ग्राम ।

(ग) थोड़ी संख्या में कृषकों, जोकि स्वयं चावल पैदा करते हैं और जिनके कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं, को छोड़ कर, सारी लगभग 181.5 लाख जनसंख्या को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न दिया जाता है ।

श्री कपूर सिंह : मैं अपने पहले सुझाव को फिर दोहराता हूं कि मंत्रियों को भाषण देने की कला में प्रशिक्षित करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल में आजकल लागू अनौपचारिक राशन व्यवस्था के अनुसार दिया गया प्रति व्यक्ति 6 औंस का राशन बिल्कुल अपर्याप्त है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि केरल राज्य के अन्दर से तथा अन्य राज्यों से किस प्रकार चावल इकट्ठा किया जाये जिससे वहां पर राशन की मात्रा बढ़ायी जा सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वहां पर राशन 6 औंस प्रति व्यक्ति नहीं दिया जा रहा है बल्कि 12 औंस प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है—6 औंस चावल और 6 औंस गेहूं । मझे विश्वास है कि माननीय सदस्य, विशेष रूप से केरल के सदस्य, यह मानेंगे कि गेहूं वहां पर बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है । अतः अब वहां पर गेहूं की मांग है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है कि केरल में अनौपचारिक राशन के साथ साथ चावल दुगने मूल्य पर खुले बाजार में भी मिल रहा है ? क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिये राशन की मात्रा बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि मूल्य में कमी हो जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मूल्य दुगना नहीं है । यह ठीक है कि राशन के चावल के मूल्य से उस का मूल्य कुछ अधिक है । परन्तु सभी लोगों की आवश्यकतायें 12 औंस अनाज, 6 औंस चावल और 6 औंस गेहूं से पूरी हो जाती है । उन्हें अतिरिक्त आवश्यकतायें खुले बाजार से ही पूरी करनी होंगी । ऐसे लोग जो बढ़िया किस्म का चावल खाना चाहें वह उसको अधिक मूल्य पर खरीद सकते हैं । परन्तु 12 औंस का राशन जो सभी लोगों को दिया जा रहा है वह वहां के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या अब वहां खाद्यपार्थों की स्थिति सुधर नहीं गई है? यदि सुधरी है, तो अब राशन जारी रखने के क्या कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्थिति में सुधार राशन के कारण हुआ है । यदि इसे हटा दिया जायेगा तो स्थिति अधिक बिगड़ जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ ऐसे राज्यों ने जिन के पास फालतू अनाज है, केरल को चावल देने से इन्कार कर दिया है, यदि हां, तो वह कौन कौन से राज्य हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरी जानकारी में कोई ऐसा राज्य नहीं कि जिस ने केरल को चावल देने से इनकार किया हो ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that in Kerala ration cards were distributed liberally in urban areas while in rural areas cards were not distributed in that way ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं । यह पूरे केरल राज्य में बांटे गये हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा है । 181.5 लाख की जनसंख्या को कार्ड दिए गए हैं । यह व्यवस्था शहरों में ही लागू नहीं है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच नहीं कि केरल सरकार 40,000 टन चावल का एक रक्षित भंडार बनाना चाहती थी, यदि हां, तो क्या सरकार ने यह भंडार बनाया है और क्या सरकार इस स्थिति में है कि चावल और गेहूं की सप्लाई को बनाये रखने का आश्वासन दे सकती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, हम ने रक्षित भंडार बनाया है । यदि मुझे ठीक याद है तो एक समय यह 60,000 टन का था । मैं इस समय यह नहीं बता सकता हूं कि हमारा यह भंडार कितना है परन्तु लगभग 40,000 टन होगा । हम इस का प्रयत्न कर रहे हैं कि भंडार में कम से कम एक महीने का स्टाक रहे जो कि 70,000 टन है ।

श्री पें० वैंकटासुब्ब्या : क्या केरल राज्य की पूरी आवश्यकताओं का पता लगाया गया है, यदि हां, तो किन राज्यों से केरल को खाद्य पदार्थ भेजे जा रहे हैं ताकि वहां पर खाद्यान्नों में कमी न आने पाये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केरल में प्रति माह लगभग 70,000 टन या लगभग 8.5 लाख टन प्रति वर्ष चावल की आवश्यकता होती है । साधारणतः आंध्र प्रदेश से, कुछ मद्रास से तथा कभी कभी मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा से वहां पर चावल भेजा जाता है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What was the quantity of rice and wheat demanded by Kerala Government ? How far the centre has met that demand ? Is it not a fact that rice provided for sale under control rates is being sold in black market ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं । यह अब राशन कार्डों से 6 औंस प्रति व्यक्ति बांटा जाता है और उसी आधार पर केरल की मासिक आवश्यकता 70,000 टन है । हम इतना ही वहां भेज रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : चुनाव के परिणामों को देखते हुए प्रत्यक्ष है कि केरल में संविदित राशन व्यवस्था सफल रही है । क्या सरकार भारत के खाद्यान्नों की कमी वाले सब राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : ताकि चुनाव के परिणाम वहां जैसे ही निकल सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केरल एक बहु शिक्षित लोगों वाला राज्य है । मेरे विचार में वहां खाद्य पदार्थ देकर मत नहीं खरीदे जा सकते । वह अपनी राजनैतिक राय बनाते हैं और वोट डालते हैं । अतः राशन व्यवस्था या चावल के वितरण से वोटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

श्री दी० चं० शर्मा : कमी वाले अन्य राज्यों के बारे में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : हम अन्य राज्यों पर फिर कभी विचार करेंगे ।

Shri Sheo Narain : Is it a fact that foodgrains are available in Kerala but this rationing is responsible for this heavoc ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह समाचार मेरे लिये बहुत अजीब है । हम वहां 12 औंस के हिसाब से खाद्यान्न दे रहे हैं । इस के अतिरिक्त जो चावल वहां पैदा होता है वह बाजार में उपलब्ध है ।

Translation of Central Act into Hindi

*337. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri S.C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jadgdev Singh Siddhanti :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister for **Law** be pleased to state :

(a) The progress so far made in publishing a Hindi version of the various Central Acts ; and

(b) whether any action is being taken by Government for getting the Central Acts translated into different regional languages simultaneously and to ensure that there is uniformity in the legal terminology in all State laws?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तीन केन्द्रीय अधिनियमों, अर्थात इंडियन पीनल कोड, इंडियन एवीडेन्स एक्ट और ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट के प्राधिकृत हिन्दी पाठ भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 2, खण्ड 1-क में 27 जनवरी, 1965 को प्रकाशित किये जा चुके हैं ।

(ख) केन्द्रीय विधियों के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के प्रश्न पर सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श करके, तत्परतापूर्वक विचार कर रही है, और राज्य सरकारों को इस बात के लिये राजी करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि, जहां तक हो सके, वे राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा बनाई गई मानक विधि शब्दावली का प्रयोग करें ।

Shri M. L. Dwivdi : How many years have passed when official Language (Legislative) Commission was constituted ? What are the reasons for translating and publishing only three Central acts so far ?

श्री जगन्नाथ राव : लगभग 15 अधिनियमों का अनुवाद किया जा चुका है और 3 अधिनियमों पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और वे छाप दिये गये हैं । आरंभ में हिन्दी के समानार्थक शब्दों के बारे में कठिनाई हुई है । अब कुछ प्रगति हुई है । भविष्य में सुविधा रहेगी और अधिक अधिनियमों का अनुवाद होगा ।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has said that Acts will be translated into different regional languages and State Governments are being consulted in this regard and efforts are being made to use standard terminology. I want to know whether standard terminology has been evolved, if so, what was the advice given by the States and the names of the States which have not given any advice so far ?

श्री जगन्नाथ राव : अस्थायी विधि शब्दावली तैयार कर ली गई है और राज्य सरकारों को भेज दी गई है । तीन अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है । जैसे ही और अधिनियमों का अनुवाद हो जायगा वैसे ही राज्य सरकारों की सलाह से विधि शब्दावली को अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

Shri Yashpal Singh : We are not receiving Hindi Translation of those Bills which are being introduced here now whereas we were told two years before that first place will be given to Hindi. May I know as to when arrangements will we made for the tranaslation of these bills ?

श्री जगन्नाथ राव : राष्ट्रपति ने 1961 में आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 344(6) के अन्तर्गत की थी । 26 जनवरी के पश्चात सभी विधेयक अधिकृत हिन्दी और अंग्रेजी पाठों में पुर:स्थापित किये जायेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के लिये जो विधि शब्दावली तैयार की है क्या राज्य सरकारें प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिये भी उसी का इस्तेमाल करेंगे ?

श्री जगन्नाथ राव : विचार तो यही है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I think the hon. Law Minister very well knows that Mitakshra was translated first of all by East India Company and was enforced as an Act. Have the Government tried to obtain help in translation from these ancient books.

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मिताक्षरा का प्रमाणित अनुवाद एक अंग्रेज महानुभाव जिन का नाम कोल्ब्रुक ने किया था। यही अनुवाद अब भी प्रमाणित है । परन्तु आयोग को अधिनियमों का अनुवाद करना है और प्राचीन हिन्दी कानूनों का नहीं ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या सरकार ने सभी अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने का कोई प्रयत्न किया है और उन के विचार में सर्वोच्च न्यायालय के उन विनिर्णयों तथा

[श्री प्रिय गुप्त]

निर्णयों का हिन्दी में अनुवाद कराने में क्या प्रगति हुई है जिनको विधि-न्यायालयों में काम में लाया जायेगा ? क्या इस संबंध में भी कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध केवल अधिनियमों से है ।

श्री अ० कु० सेन : अनुवाद यथासमय किया जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दें । प्रश्न यह है कि शाब्दिक अनुवाद के अतिरिक्त क्या हिन्दी में विधि संबंधी शब्दों और मुहावरों के तकनीकी और समरूप शब्द और मुहावरे मिलना संभव है ?

श्री अ० कु० सेन : हिन्दी में कानूनी शब्दावली का बनाना सम्भव है ।

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या विधि संबंधी शब्दों और मुहावरों के हिन्दी में समरूप और तकनीकी शब्द और मुहावरे मिलना सम्भव है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह सम्भव है ।

श्री कपूर सिंह : वह कहते हैं कि शब्दावलि का विकास करना सम्भव है । यह एक भिन्न प्रश्न है । वह उत्तर तो जानते हैं परन्तु टाल रहे हैं ।

श्री अ० कु० सेन : मैं श्री कपूर सिंह के प्रश्नों को कभी नहीं टालता । इस में कोई सन्देह नहीं है कि हम उन के प्रश्नों की ओर पूरा ध्यान देते हैं । उन्होंने तीन शर्तें लगाई हैं : विधि संबंधी, तकनीकी और साहित्यिक शब्द क्या यही नहीं हैं ? **(अन्तर्बाधाएं)**

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य स्वयं ही भूल गये ।

श्री अ० कु० सेन : तत्सम शब्दों की तो गारंटी है क्योंकि इसके बिना तो अनुवाद ही नहीं किया जा सकता । मैंने कुछ सिद्धांतों का अनुसरण किया है । अपने देश के विभिन्न विधि न्यायालयों में विधि-शब्दों के, जो लम्बे समय से प्रयोग में आते रहे हैं, सामान्य रूप से जो अर्थ लिये जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, हम ने उन शब्दावलियों का, जो अंग्रेजी की हैं और जिनका आम प्रचलन है अथवा फारसी के शब्द जैसे तहबाजारी को उपयोग में लाने का प्रयत्न किया है। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दी में विधि शब्दों और मुहावरों का विकास कर लिया जायेगा ।

Shri Rameshwaranand : May I know the qualifications of the Members of theOfficial Language Commission which coins Hindi words for legal terms and what books they have studied in Sanskrit and Hindi ?

Shri A.K. Sen : They are well qualified.

Shri Rameshwaranand : My question is : what books they have studied in Sanskrit and Hindi ?

Mr. Speaker : It would not be possible to give details and the list of the books which they have read. They might have read a number of books.

Shri Rameshwaranand : How could we find out their ability without that.

Mr. Speaker : Swamiji, they might have read a large number of books in Hindi and Sanskrit, but it would be very difficult to give their names now.

डा० मा० श्री अणे : क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि संस्कृत शब्द कोष और संस्कृत व्याकरण की सहायता से ऐसे नये शब्द बनाना संभव है, जिनके हिन्दी में समान शब्द नहीं हैं और इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हिन्दी में भी नये पारिभाषिक शब्द बनाये जा सकते हैं ?

श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य अनुवादों को, जिनमें से कुछ तो राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं और अन्य प्रकाशित किये जा रहे हैं, देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हिन्दी में एसे नये शब्द बहुत हैं जो न केवल अच्छे ही हैं अपितु दोषरहित भी हैं ।

Shri Rameshwaranand : On a point of order Sir. My request is this that legal terms in English can be translated into Sanskrit because Sanskrit words were in use in the past for official works and the legislations which you are formulating now were there then.....

Mr. Speaker : The first condition for raising a point of order is that you must quote the rule under which you are raising the point of order.

Shri Rameshwaranand : The point of order is being raised on the incorrect reply which has been given.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether they are satisfied with the work of Law Commission which has translated 15 or 18 Acts, and if not, what new steps have been taken by them to accelerate this work ?

श्री अ० कु० सेन : मेरा विचार है कि आयोग को मिले समय और प्रारंभिक अवस्था में नये तरीकों को निकालने की दृष्टि से काफी अच्छी प्रगति हुई है, क्योंकि 15 अधिनियमों का अनुवाद किया गया है । मुझे बताया गया है कि अब अधिनियमों का अनुवाद तेजी से होगा क्योंकि नये तरीके निकाल लिये गये हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार राष्ट्र की अन्य भाषाओं में साथ साथ अनुवाद कराने की व्यवस्था करने में देर क्यों कर रही है, क्योंकि इससे हिन्दी के अतिरिक्त राष्ट्र की अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, बंगाली, तामिल, आदि से शब्दों को लेकर एक रूप शब्दावलि बनाई जा सकेगी ? हिन्दी के शब्दों से उनके कुछ शब्द अच्छे तत्सम होंगे ।

श्री अ० कु० सेन : जनवरी के प्रथम सप्ताह में राज्य विधान विभागों के प्रतिनिधियों की दिल्ली में बैठक हुई थी । उनके सामने यह प्रश्न रखा गया था । राज्यों के प्रतिनिधियों की यह राय थी कि राज्यों को केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद प्रादेशिक भाषाओं में करना चाहिये और प्रत्येक राज्य की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह उन केन्द्रीय अधिनियमों का, जिनको वे चुने अपनी प्रादेशिक भाषा में अनुवाद करे । मेरे विचार में यह अच्छा होता यदि सभी केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने का काम एक केन्द्रीय एजेंसी को सौंपा जाता । परन्तु यदि इस राज्य जिम्मेदारी

को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो केन्द्रीय सरकार उनके रास्ते में बाधा नहीं डालना चाहती। परन्तु क्योंकि राज्यों ने इस कार्य को शीघ्रता से हाथ में लेने के सम्बन्ध में अपनी वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख किया है, हमने केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद शीघ्रता से करने में होने वाले अनुमानित व्यय के बारे में उनसे पूछा है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : तत्सम शब्दावलि का विकास विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं में से शब्दों को ढूंढने पर निर्भर है। अन्यथा इस का विकास नहीं किया जा सकता। यही हमारे संविधान के निर्देश तत्वों में दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उनकी यह राय थी कि केन्द्र को साथ साथ अनुवाद करना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह प्रश्न कुछ कार्य केन्द्र द्वारा करने औरकुछ राज्यों द्वारा करने का नहीं है। यह संविधान में दिये गये उस निर्देश तत्वों के अनुसार है जिस में यह दिया हुआ है कि हिन्दी का तभी विकास हो सकेगा जब यह राष्ट्र की अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनायेगी। अत: विधि अथवा किसी अन्य विषय के लिये एक तत्सम शब्दावलि बनाने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्र की अन्य भाषाओं में साथ साथ कार्य किया जाये। अन्यथा इस काम का कोई फल नहीं निकलेगा।

श्री अ० कु० सेन : अनुच्छेद 357 में यह दिया गया है कि देश के लिये विधि शब्दावलि का विकास करते समय हमें सभी प्रादेशिक भाषाओं के शब्द उदारता से लेने चाहियें। सभी प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी में भी प्रयोग में आने वाले शब्दों और मुहावरों को ध्यान में रखते हुए विधि शब्दावलि का विकास करना भाषा आयोग का कर्त्तव्य है। अत: उन अधिनियमों का, जिनका अनुवाद किया गया है, को देखने से पता चलेगा कि उनमें विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग बड़ी उदारता से किया गया है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में एक पूर्ण वैधानिक तथा न्यायिक प्रक्रिया थी, क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि न्यायिक और वैधानिक मामलों के लिये पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार करते हुए उन शब्दों को जहां तक सम्भव हो अपनाया जाय जिनका भारत में पहले प्रयोग होता था, बजाय इसके कि नये शब्दों को रखा जाये। इस मामले में उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने वैधानिक पद्धति आरम्भ की थी, उन्होंने भारत में सर्वोच्च न्यायालय के, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, मार्गदर्शन के लिये एक संस्कृत का न्याय-शास्त्र "विवाद-भंगार्णव" निकाला था ।

श्री अ० कु० सेन : यथासम्भव प्राचीन शब्दों को अधिक रखा जाता है। परन्तु माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे ––वह स्वयं वकील हैं––कि हमारे नये कानूनों में जो शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं उनके तत्सम शब्द प्राचीन पुस्तकों में आसानी से नहीं मिलते हैं ।

दिल्ली में आयात किये गये गेहूं का दिया जाना

*339. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय किया है कि आगे से आयात किया गया गेंहूं और आटा केवल उन व्यक्तियों को बेचा जायेगा जिनके पास चीनी के कार्ड हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार्ड वाले को कितनी मात्रा दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) गेहूं की मात्रा किस आधार पर निर्धारित की गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Yashpal Singh : What was the point in it that imported wheat should only be given to those who have sugar cards, when crores of Indians like me go without sugar and carry on with *gur* ? It should have been like this that imported wheat should not be given to those who possess sugar cards. The policy of the Government implies that wheat should be given to only rich people.

Mr. Speaker : The hon. Member should put supplementary question after listening to the answer. The hon. Minister said that no such thing was being done.

Shri Yashpal Singh : If it is correct why the Delhi Administration have acted against the orders of the Government ?

Mr. Speaker : What is correct ?

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister said that it was not correct that those who are in possession of sugar cards should be given wheat cards. Why the Delhi Administration have not acted according to the instructions of the Government ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने भाग (क) के उत्तर में "जी, नहीं" और भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में "प्रश्न ही नहीं उठते" कहा है ।

Shri Yashpal Singh : What is the position of imported wheat in Delhi ? To whom it is given and to whom it is not given ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : श्री माननीय सदस्य की यह धारणा है कि आयात किया गया गेहूं चीनी के कार्डों पर दिया जाता है । इस का उत्तर "नहीं" है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri M. L. Dwivedi : Are the Government aware that the good arrangements which exist for the distribution of imported wheat in Delhi do not exist in other cities ; if so, whether the Government is taking any action to make such arrangements in all the cities ?

Mr. Speaker : Then Delhi would not remain Delhi.

Shri M. L. Dwivedi : That is right but attention should be paid to other cities also.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रत्येक राज्य सरकार अपना प्रबन्ध स्वयं करती है और संभवतया उनका विचार हो कि उन्होंने अपना काम दिल्ली से अधिक कुशलता से किया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Are the Government considering any proposal to bring about any change in the existing distribution system of imported wheat in Delhi with a view to make it more efficient ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । हम विचार कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को दिये गये कार्ड के आधार पर आयात किए गये तथा देसी गेहूं के वितरण के लिये कोई दूसरा प्रबन्ध होना चाहिये ।

Shri Rameshwar Tantia : It is the general opinion of the people that the imported wheat is inferior to Punjab wheat. Have the Government made any inquiry to find out whether it is actually of an inferior quality or of the same quality ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आयात किया हुआ अनाज वास्तव में घटिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह अपनी अपनी राय और अपनी अपनी पसन्द है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : ऐसी कौनसी बाधाएं हैं जो दिल्ली प्रशासन को अपने ग्राहकों को नियमित रूप से गेहूं देने से रोकती है जबकि यह पंजाब के बिल्कुल निकट है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा भी है, हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कठिन स्थिति में भी गेंहू का समान रूप से वितरण हो और इसीलिये तो हम विचार कर रहे हैं कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को कार्ड जारी किये जायें और उसके आधार पर वितरण किया जाये । यह विचाराधीन है ।

श्री प्र० चं० बरूआ : आयात किये गये गेहूं की उपलब्धि पर प्रतिबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता है जबकि गत जनवरी में इससे भावों को कम रखने में सफलता नहीं मिल सकी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आयात किये गये गेहूं को उपलब्धि का भी प्रश्न है । यह हमारे पास बहुत मात्रा में नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार को इससे जानकारी है कि निर्धन लोगों को एक सप्ताह का चीनी का कोटा एक समय में लेने में कठिनाई होती है, यदि हां, तो सरकार ऐसा प्रबन्ध क्यों नहीं करती जिससे कोटा प्रतिदिन खरीदा जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न गेहूं के वितरण के बारे में है। चीनी के बारे में भी, मेरे विचार से, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दुकान पर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

उड़ीसा में चावल की वसूली

*340. **श्री रा० गि० दुबे:**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार तथा केन्द्र ने केन्द्रीय पूल के लिये राज्य का फालतू चावल खरीदने के लिये एक फार्मूला बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो बनाये गये फार्मूला का स्वरूप क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) किये गये प्रबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार रेल-पर्यन्त केन्द्रों पर स्थित मिलों से सीधा ही चावल खरीद रही है। उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सरकार की ओर से रेल-पर्यन्त केन्द्रों से दूरवर्ती अन्य केन्द्रों पर चावल खरीद रही है।

श्री रा० गि० दुबे : उड़ीसा सरकार द्वारा नियत किया गया अनाज वसूल करने का मूल्य क्या रखा है ? यदि केन्द्रीय सरकार समझती है कि यह मूल्य अधिक है, तो क्या वितरण के समय कोई राजकीय सहायता दी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी, नहीं , अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में मूल्य अधिक नहीं हैं।

श्री रा० गि० दुबे : इस मामले में खाद्य निगम का क्या कार्य है। क्या भविष्य में खाद्य निगम अनाज वसूल करेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। भविष्य में सब खरीद खाद्य निगम द्वारा की जायेगी।

श्री रामेश्वर टांटिया : इस वर्ष उड़ीसा में कुल फालतू चावल कितना होगा और गत वर्ष क्या स्थिति थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आशा है कि इस वर्ष हम लगभग 3 लाख टन चावल वसूल करेंगे। गतवर्ष वसूली केवल 1 लाख टन के लगभग थी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से विरोध किया है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में चावल की किस्मों को निश्चित करने में भेदभाव रखा गया है अर्थात् मध्य प्रदेश के चावल को उड़ीसा के मुकाबले घटिया किस्म का ठहराया

गया है जब कि दोनों एक ही किस्म के थे और इसके फलस्वरूप वसूली के मूल्यों में अन्तर है ? यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विरोध का मुझे पता नहीं है। यदि कोई विरोध किया होता तो मुझे बताया जाता।

श्री मुहम्मद इलियास : वसूल किये गये फालतू चावल में से कितना पड़ौसी राज्यों को भेजा जायेगा और किस मूल्य पर ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पड़ौसी राज्यों को उड़ीसा का अथवा कोई अन्य विशिष्ट चावल भेजने का प्रश्न नहीं है। वसूल किया गया सारा स्टॉक केन्द्रीय पूल में आता है जहां से विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाता है।

अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण

*341. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेडा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, चावल तथा दालों जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित ढंग से समान वितरण करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) : गेहूं और चावल के लिए देश को उपयुक्त क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक अधिशेष राज्य के फालतू खाद्यान्न और प्रत्येक कमी वाले राज्य की कमी सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से समय समय पर आंकी जाती है और अधिशेष राज्य का फालतू खाद्यान्न खरीदने के लिए कार्यवाही की जाती है और केन्द्रीय सरकार के पास विदेशों से आयात किये तथा देश में से खरीदे गये स्टाक का कमी वाले राज्यों में समान वितरण किया जाता है।

जहां तक दालों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे दालों के संचलन पर से सभी प्रतिबन्ध उठालें ताकि आवश्यकतानुसार दालों का संचलन अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों में मुक्त रूप से हो सके। केवल चने की दाल अपवाद है। इसके के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि चने की नई फस्ल कट जाने के बाद प्रतिबन्ध उठायें और तब तक अधिशेष राज्यों में रखे चने के स्टाक का 50 प्रतिशत नियंत्र करने की अनुमति दें।

श्री दी० चं० शर्मा : समान वितरण करने के लिए चावल और गेहूं के ज़ोनों में परिवर्तन करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक चावल का सम्बन्ध है, इसके जोनों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आगामी मौसम के आरम्भ में इस का पुनरावलोकन किया जायेगा। जहां तक गेहूं के ज़ोनों का सम्बन्ध है, इस मामले पर मुख्य मंत्रियों से चर्चा की जा रही है और हम शीघ्र ही कोई निर्णय करेंगे।

श्री दी० च० शर्मा : यह देखा गया है कि दालों के भाव बहुत चढ़ गये हैं जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया है। क्या कोई ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिससे दालों के भाव-सामान्य स्तर पर आ जायें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसा लगता है कि गत वर्ष दालों का उत्पादन कम हुआ था। इस वर्ष उत्पादन सामान्य रहा है और आशा है कि भाव भी सामान्य स्तर पर आ जायेंगे।

लिखित प्रश्नों के उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली की सहकारी संस्थायें

*342. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 22 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 622 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अन्य संस्थाओं के गठन कार्य तथा उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या विभिन्न जांच रिपोर्टों के आधार पर सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार ने कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 12 अन्य समितियों के गठन, कार्य और आर्थिक स्थिति के बारे में जांच पूरी हो गई है।

(ख) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3948/65 ।]

राष्ट्रमंडल चीनी करार

*343. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को राष्ट्रमंडल चीनी करार में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस करार से भारत को कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) करार के अधीन निर्यातक सदस्य देशों को बातचीत से तय मूल्य पर ब्रिटेन को निर्यात करने के लिए विशिष्ट कोटे नियत किये जाते हैं और विश्व मूल्य जमा एक अधिमान मूल्य पर ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैण्ड को अतिरिक्त कोटे निर्यात किये जाते हैं।

(ग) ब्रिटेन को 0·25 लाख मीट्रिक टन का कोटा बात-चीत से तय मूल्य पर निर्यात करने से भारत को 45·8 पौण्ड प्रति मीट्रिक टन का भाव जहाज तक निःशुल्क और जगह पर लगाने पर मिलेगा जबकि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय भाव लगभग 23 पौण्ड प्रति मीट्रिक टन लागत बीमा भाड़ा, ब्रिटेन है। ब्रिटेन और कनाडा को 1·02 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त कोटे के निर्यात पर भारत को विश्व भाव जमा एक अधिमान मूल्य मिलेगा।

एयर इंडिया की सेवायें

*344. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री यशपाल सिंह ।
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया अपनी सेवायें और बढ़ाने के लिये बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय ये विभिन्न वार्तायें किस स्थिति में हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एयर इण्डिया की सेवाओं के और आगे बढ़ाने के लिए इस समय कोई बातचीत नहीं चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य सम्बन्धी अपराधियों का संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल)

*345. **श्री त्रिविद कुमार चौधरी :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने अब तक खाद्य सम्बन्धी अपराधियों का संक्षिप्त विचारण (समरीट्रायल) करने और अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध चलाये गये मुकदमों को निबटाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करने के बारे में प्रधान मंत्री के निदेश का पालन किया है; और

(ख) क्या सरकार को इस अध्यादेश के अन्तर्गत दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में राज्यों से कोई रिपोर्टें मिली हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार को छोड़ कर, सभी राज्य सरकारों ने संक्षिप्त विचारण के लिए मशीनरी स्थापित कर दी है ।

(ख) जी, हां । एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3949 / 65]** ।

गन्ने का भरण

*346. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ एवं खांडसारी निर्माताओं और चीनी के कारखानों के लिए गन्ने की उपलब्धि में वर्तमान असन्तुलन को दूर करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप रेखा क्या है और वह चालू वर्ष में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने में कहां तक प्रभावकारी सिद्ध हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) गुड़ और खांडसारी निर्माताओं तथा शर्करा कारखानों को गन्ना प्राप्ति में जो वर्तमान असन्तुलन है उसे गन्ने की उपज में वृद्धि करके और उसका गुण सुधार कर ठीक किया जा सकता है । इसके लिए मुख्यत: गन्ना क्षेत्र में सघन विकास करने की आवश्यकता है ताकि प्रति एकड़ उपज और शर्करा की मात्रा बढ़ जाये । इसके लिए व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना में की जा रही है ।

चालू वर्ष में शर्करा का उत्पादन लगभग 30 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है, जबकि 1963-64 में 25·69 लाख मीट्रिक टन तथा 1962-63 में 21·52 लाख मीट्रिक टन था ।

Employees' Provident Fund Schemes

*348. **Shri Madhu Limaye :**
Dr, Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri D. N. Tiwary :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether Government propose to include such employees in the Employees' Provident Fund Schemes as are drawing more than Rs. 1,000 per month as salary ;

(b) if so, the date by which the scheme would be enforced ; and

(c) the additional expenditure that Government will have to incure in this connection ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen) : (a) The proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

(c) The additional expenditure if any that may have to be incurred as employers' contribution in respect of these workers in public sector undertakings covered under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, has not been estimated.

मत्स्य विपणन निगम

*349. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मछली प्राप्त करने और बेचने के लिए कलकत्ता में केन्द्रीय मत्स्य विपणन निगम की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह निगम कब तक कार्य करने लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) कलकत्ता में मत्स्य विपणन निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसे बनाने तथा अनाज की वसूली के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य किये जाने के बाद निगम का काम आरंभ हो जायेगा।

कलकत्ता में राशन व्यवस्था

*350. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 1 जनवरी, 1965 से चालू की गई परिनियत राशन-व्यवस्था सफल रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इसके असफल होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि केन्द्र अनाज की पर्याप्त मात्रा देने में असफल रहा; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को सफल बनाने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। कलकत्ते में सांविधिक राशन व्यवस्था जो कि 5 जनवरी, 1965 को लागू की गई थी, सफल सिद्ध हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनाज का फालतू भंडार

*351. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मधु लिमये :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री शशि रंजन :
श्री चाण्डक :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री पाराशर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य निगम गेहूं और चावल का फालतू भंडार बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना माल इकट्ठा किया जायेगा और यह कहां पर रखा जायेगा; और

(ग) इसके वितरण के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ?

खाद्य तथ कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : खाद्य निगम सरकार की ओर से समीकरण भण्डार तैयार करेगा। केन्द्रीय सरकार का विचार है कि धीरे धीरे देश में उपयुक्त स्थानों पर 40 लाख मीट्रिक टन गेंहूं और 20 लाख मीट्रिक टन चावल का एक समीकरण भण्डार तैयार किया जाये। सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार निगम समीकरण भण्डार तैयार करेगा, देख-भाल, कुल बिक्री और वितरण सम्बन्धी कार्य करेगा।

खाद्यान्नों का आयात

*352. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती जोहराबेन बावड़ा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी दो वर्षों में पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात में काफी वृद्धि करने का विचार किया है ताकि गेहूं और चावल का काफी फालतू स्टाक जमा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) जून, 1965 के बाद जब चालू करार के अन्तर्गत सप्लाई पूरी हो जाने की आशा है, खाद्यान्नों का आयात करने के लिए पी० एल० 480 के अधीन एक नया करार करने का मामला विचाराधीन है। इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि नये करार के अन्तर्गत कितनी मात्रा मिलेगी।

खाद्यान्न प्राप्त करना

*353. श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेडा
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री चांडक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों द्वारा परस्पर विरोधी कृषि-मूल्य नीतियों का अनुसरण और खाद्यान्न प्राप्त करने की उनकी विभिन्न नीतियां खाद्यान्न प्राप्त करने में रुकावट पैदा कर रही हैं तथा खाद्य निगम के कार्य में ोड़ा अटका रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे इस साल के खाद्यान्न की प्राप्ति के लक्ष्यों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) निर्बाध प्राप्ति के लिए मार्ग साफ करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

फ्रांस से गेहूं

*354. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती मैमूना सुल्तना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस ने भारत सरकार को बताया है कि वह भारत को गेहूं दे सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह कब से लागू होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय दूतावास, पैरिस को संधि पर तुरन्त हस्ताक्षर करने का अधिकार दे दिया गया है ।

(ग) मार्च में ही इस गेहूं का लदान शुरू हो जाने की सम्भावना है ।

गेहूं के प्राप्ति मल्य

*355. **श्री प्र० च० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री चांडक :

क्या खाद्य तथ कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1964-65 की फसल के लिये गेहूं के प्राप्ति मूल्य निश्चित कर दिये हैं और यदि हां, तो क्या ;

(ख) उत्पादकों द्वारा गत वर्ष विभिन्न किस्म का गेहूं औसतन जिन मूल्यों पर बेचा गया था उनकी तुलना में ये मूल्य कैसे हैं; और

(ग) पिछले और उससे पहले वर्ष के मूल्यों की तुलना में विभिन्न किस्म के गेहूं के उपभोक्ता मूल्य इस वर्ष कितने अधिक होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार ने गेहूं का कोई प्राप्ति भाव निर्धारित नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश के कुछ भागों में मण्डियों में अभी अभी 1964-65 की गेहूं की फसल आनी शुरू हुई है । इस वर्ष फसल का बाजार भावों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में अनुमान लगाना और वर्ष के दौरान में भावों का क्या स्तर रहेगा यह बताना बहुत जरूरी होगा ।

जयपुर में ऊन काटने का स्कूल

837. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष की सहायता से ऊन काटने का कोई स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से जयपुर में ऊन की दर्जाबन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है।

(ख) राजस्थान सरकार अपने राज्य में ऊन की दर्जाबन्दी तथा विपणन केन्द्रों की स्थापना कर रही है। इन केन्द्रों के लिए जिन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी उनको ऊन की दर्जा-बन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी। इस समय 75 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि से मिलने वाली सहायता विशेषज्ञों और उस साज़-सामान के रूप में होगी जो कि उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों तथा दर्जाबन्दी केन्द्रों के लिए आवश्यक है।

राजस्थान को उर्वरक का सम्भरण

838. **श्री धूलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 के वर्ष में राजस्थान को किस मात्रा में उर्वरकों का सम्भरण किया गया ;

(ख) क्या यह कोटा 1965–66 के वर्ष में बढ़ा देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राजस्थान सरकार को नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की जितनी मात्रा एलाट की गई और वास्तव में जितनी मात्रा सप्लाई की गई वह नीचे दी गई है :—

उर्वरक	1964–65 के लिये अलाटमेंट	(आंकड़े मीटरी टनों में) 21–2–65 तक सप्लाई
सल्फैट आफ अमोनिया .	17,225	7,505
यूरिया	3,250	1,898
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट . .	1,176	873
कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट .	23,649	23,376
कुल नाइट्रोजन .	10,197	7,438

आगे की सप्लाई चालू है ।

(ख) राज्य सरकार ने 1965–66 के लिए नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों की निम्नलिखित मांग भेजी है :—

	(आंकड़े मीटरी टनों में)
सल्फेट आफ अमोनिया	25,000
यूरिया . .	4,000
अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट .	4,000
कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट	40,000
कुल नाईट्रोजन	16,494

समस्त देश की आवश्यकताओं और प्रत्येक तिमाही के दौरान अनुमानित उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए तीन मास पर अलाटमेंट की जाएगी। चालू वर्ष की अपेक्षा 1965–66 के दौरान कुल उपलब्धि अधिक होने की आशा है, अतः 1965–66 में राजस्थान का कोटा भी बढ़ने की आशा है ।

सहकारी विधियां

839. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कद्वीव के संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी विधियों को सरल तथा उदार बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या कोई नमूना विधि तैयार की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) सरलीकरण और उदारीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लक्कद्वीव, मीनीकाय तथा अमिनदिवी द्वीपसमूह सहकारी समिति विनियम 1960, दिसम्बर, 1961 में प्रख्यापित और लागू किया गया था।

(ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा स्थापित सहकारी विधि से सम्बन्धित समिति ने 1957 में एक माडल सहकारी समिति विधेयक तैयार किया।

बड़गरा लाइट हाउस

840. { **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बडगरा में लाइट-हाउस के डिजाइन और खाके को अब अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर काम कब आरम्भ हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने दीपघर की योजना और डिजाइन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। राज्य सरकार इस वर्ष के उत्तरार्ध में काम शुरू करने की आशा करती है।

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का कल्याण

841. **श्री सिद्धय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1961-62, 1962-63, 1963-64, और 1964-65 में अनुसूचित जादितयों, अनसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये योजनाओं को लागू करने के लिये मैसूर राज्य को कितनी राशि मंजूर की ;

(ख) क्या उपर्युक्त योजना के लिये दी गई सारी राशि का प्रत्येक वर्ष में उपयोग किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक वर्ष म कितनी राशि उपयोग में नहीं लाई गई ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

पिछड़ी जातियों के वर्ग	वर्ष	दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	कमी
I. अनुसूचित जातियां	1961–62	56.48	44.55	11.93
	1962–63	61.05	59.81	1.24
	1963–64	43.31	38.05	5.26
	1964–65	48.84	84.48 (पूर्वानुमानित)	—
	योग	209.68	191.25	18.43
II. अनुसूचित आदिम जातियां	1961–62	6.37	3.60	2.77
	1962–63	6.87	6.07	2.80
	1963–64	8.87	8.65	0.22
	1964–65	11.05	11.05 (पूर्वानुमानित)	—
	योग	35.16	29.37	5.79
III अन्य पिछड़ी हुई जातियां जिनम अनधिसूचित तथा खानाबदोश आदिम जातियां सम्मिलित हैं)	1961–62	13.20	8.56	4.64
	1962–63	17.53	15.85	1.68
	1963–64	17.13	13.58	3.55
	1964–65	19.75	19.75 (पूर्वानुमानित)	—
	योग :	67.61	57.74	9.84

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को विद्यार्थी

842. **श्री सिद्दय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में आई है कि मैसूर राज्य में सातवें स्टैन्डर्ड में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको उपर्युक्त शुल्क से छूट देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). भारत सरकार के पास इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है । इस सम्बन्ध में मैसूर सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है ।

हरिजनों का कल्याण

843. **श्री सिद्धय्या** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 8 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 406 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : केन्द्रीय सरकार मुख्यतः उस सिफारिश से सम्बन्धित है जो अस्पृश्यता के प्रश्न तथा अनुसूचित जातियों के अधिक उत्थान की समस्या पर विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति करने के बारे में है । प्रस्तावित समिति के सदस्यों की सूची अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है । समिति काम शीघ्र आरम्भ कर देगी ।

अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, राज्यों से उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है ।

'इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन' की उड़ानें

844. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की जो उड़ानें शान्ताक्रुज से होती हैं वे 6 जनवरी, 1965 को एक से तीन घंटे तक पीछे हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ; और

(ग) इस देरी को दूर कर देने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन द्वारा यातायात, कैटरिंग और कारगों कर्मचारियों के लिए 'नियम के अनुसार काम करो (वर्क टूरूल)' निदेश जारी किये जाने और कलकत्ते में कोहरे के कारण भी ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रबन्धक वर्ग द्वारा यूनियन एसोसियेशनों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने के लिए उन के द्वारा हर संभव उपाय किये जाते हैं ।

हरिजनों को कानूनी सहायता

845. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65 में विभिन्न राज्यों को हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिए कितनी सहायता दी गयी और उसमें से वास्तव में उन्होंने कितनी राशि खर्च की ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : 1964–65 में विभिन्न राज्यों के हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिए दी गई राशियां इस प्रकार हैं :—

(रुपये–लाखों में)

(1) गुजरात	0.03
(2) मध्य प्रदेश	0.05
(3) मैसूर	0.195
(4) उड़ीसा . . .	0.02
(5) राजस्थान	0.05
(6) हिमाचल प्रदेश	0.10
(7) त्रिपुरा	0.005
	0.45

योजना पर वास्तव में खर्च की गई राशि के बारे में जानकरी केवल वित्तीय वर्ष (1964–65) की समाप्ति के बाद प्राप्त होगी ।

अपाहिज व्यक्तियों का सर्वेक्षण

846. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 8 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उन सब वर्गों के अपाहिज व्यक्तियों के नमूना सर्वेक्षण करने का है जिनके संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जी, हां, ऐसा विचार किया गया है कि शारीरिक रूप से अपाहिजों का सर्वेक्षण भारत के महापंजीकार के द्वारा कराया जाये ।

Wheat Smugglers

847. **Shri Naval Prabhakar :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Food and Agriculture** is pleased to state ;

(a) the number of wheat smugglers caught in Delhi in the month of December, 1964 and January 1965 ; and

(b) the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) and (b) :

No. of Persons

	Arrested	Challaned	Convicted	Pending tiral	Under investigation
December, 1964	672	670	666	4	2
January, 1965 .	691	688	682	6	3

होटल विकास निधि

848. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह:** क्या **परिवहन** मंत्री होटल विकास ऋण निधि की स्थापना सम्बंध 1 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 738 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दिशा में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित होटल विकास ऋण निधि योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है और इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का पुनर्वर्गीकरण

849. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रीय समितियां नियुक्त करने का निर्णय किया है ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का पुनर्वर्गीकरण किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक नियुक्त की गयी समितियों की संख्या क्या है और उनके मार्गदर्शन के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के लिए क्या परिमाप निर्धारित किया गया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) पुनरीक्षण समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । आशा है कि शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा ।

कृषि संबंधी शिक्षा

850. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 8 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 409 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि संबंधी शिक्षा के स्तर का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई पुनर्विलोकन समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं तथा उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) अभी तक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

नाविकों के लिये भविष्य निधि योजना

851. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार नाविकों के लिये भविष्य निधि योजना चालू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब चालू होने की संभावना है ;

(ग) योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यह योजना कहां तक मजदूरों की सहायता करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी हां, नाविकों के लिये 1 जुलाई 1964 से भविष्य निधि योजना चालू कर दी गई है । इस योजना का सांविधिक आधार देने के लिये सरकार शीघ्र ही एक विधान लागू करने का विचार कर रही है ।

(ग) योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

1. जहाज़ मालिकों और नाविकों दोनों से मूल मजदूरी और छुट्टी वेतन के 6 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि में अंशदान । अंशदान की दर 1 अप्रैल 1968 से 8 प्रतिशत कर दी जायेगी ।

2. प्रस्तावित विधान के अधिनियमित होने तक फिलहाल ऐच्छिक आधार पर धन जमा किया जा रहा है ।

(घ) ऐसा अनुमान है कि इस योजना से लगभग 50,000 नाविकों को लाभ पहुंचेगा । 31 मार्च, 1960 तक मालिकों का अंशदान 41,76,000 रुपया हो जाने की आशा है और उसके बाद वह बढ़कर 55,60,000 रुपया हो जायेगा । इस राशि के बराबर नाविक स्वयं अंशदान करेंगे ।

Delhi Milk Scheme

852. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme have appointed some police guards ;

(b) if so, how many and since when ; and

(c) the monthly expenditure incurred on them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawza Khan) : (a) Yes.

(b) One Head Constable and four foot constables were appointed with effect from 16-8-1961 to guard the strong room in which cash is being kept and also for a escorting cash remittances from the Central Dairy to the Reserve Bank of India and Treasury.

One Head Constable, one Lance Naik Constable and 12 Constables were appointed with effect from 7-8-1964 to guard the Central Dairy and the main gates. The Lance Naik Constable has been replaced by an A.S.I. with effect from 2-1-1965.

(c) Rs. 3,470 p.m.

Delhi Milk Scheme

853. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of members of specialists team who have come to suggest measures for the successful working of the Delhi Milk Scheme, the qualifications of the members and the monthly expenditure to be incurred upon them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : A team consisting of the following seven experts were appointed on 27-7-1964 to suggest measures for successful working of the Delhi Milk Scheme.

Non-official members

1. Shri V. Kurien, General Manager,
Kaira District Cooperative Milk Producers Union Ltd., Anand.

2. Shri H, M, Dalaya, Assistant General Manager, Kaira District Cooperative Milk Producers Union Ltd., Anand.

3. Shri V.H. Shah, Manager,
Industrial Engineering Division,
Vulcan Trading Company (P) Ltd., Bombay.

4. Shri M. Halse, Consultant in Management of Agriculture and co-operative Enterprises, Indian Institute of Management, Ahmedabad.

Official Members.'

5. Dr. K.K. Iya, Director of Dairy Research,
National Dairy Research Institute, Karnal.

6. Shri Ranjit Singh, Chief Dairy Development Officer,
U.P. Cooperative Department, Lucknow.

7. Shri N.S. Dave, General Manager, Aarey and Worli Dairies,
Greater Bombay Milk Scheme, Bombay.

The Team worked from 27-7-1964 to 5-9-1964. The total expenditure incurred on the team is Rs. 13000 approximately.

Delhi Milk Scheme

854 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of machines lying idle in the Delhi Milk Scheme ;

(b) whether it is a fact that some machines have also stopped working recently due to the discontinuance of manufacture of butter ;

(c) if so, the cost of those machines ; and

(d) how these machines are proposed to be utilised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) : hree machines at the Central Dairy and the equipment at three Milk Collection and Chilling Centres are lying idle.

(b) : No ; manufacture of butter has not been discontinued.

(c) The cost of the equipment referred to in (a) above is Rs. 9,94,108.65 paise.

(d) Machines are idle primarily because of shortage of milk. Active measures are being taken for improving procurement of milk and these machines will be utilised as soon as this is possible.

Intensive Cattle Development Blocks

855 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have sanctioned the establishment of sixteen intensive cattle development blocks in the eight States ;

(b) if so, he names of these States ;

(c) whether it is proposed to open such blocks in other States also ; and

(d) if so, the estimated expenditure involved and when the work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Madras, Madhya Pradesh, Mysore, Punjab and Uttar Pradesh.

(c) Proposal for the establishment of such blocks under the Special Development Programme has been received from the Governments of Gujarat, Maharashtra, Orissa and West Bengal. It has not been possible to sanction these schemes as the ceiling fixed for the Special Development Programme has since been exhausted.

(d) The establishment of 16 blocks mentioned in part (a) above has been sanctioned at an estimated cost of Rs. 646·61 lakhs during 1964-65 and 1965-66. It is one of the conditions of the sanction that the schemes should be completed in all respects by the end of 1965-66. The estimated cost of the schemes received from Gujarat, Maharashtra, Orissa and West Bengal is Rs. 383·co lakhs.

चीनी उद्योग का लागत ढ़ांचा

856. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लागत ढांचे के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पशुपालन सम्बन्धी कार्यकारी दल

857. **श्री शपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पशुपालन और डेरी सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर उनके मंत्रालय द्वारा दिये गये टिप्पणों और सुझावों की इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

सहकारी परिवहन समितियां

858. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री सहकारी परिवहन संस्थाओं के लिये सुविधाओं सम्बंधी 24 नवम्बर 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशें इस बीच स्वीकार कर ली हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो वे कब स्वीकार की जायेंगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख): परिवहन सहकारिता पर अध्ययन दल की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है। चूंकि इन सिफारिशों पर अभी कई राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिये यह बतलाना संभव नहीं है कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा । राज्य सरकारों को निरन्तर याद दिलाई जा रही है ।

पक्षियों का परिरक्षण

859. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पक्षी परिरक्षण परिषद द्वारा समय समय पर की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न जातियों के पक्षियों के परिरक्षण के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उप मत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों ने पक्षियों को अन्धाधुन्ध ढंग से मारने तथा पकड़ने से बचाने के लिए कानून बनाये हैं । अनेक राज्यों ने वन्य प्राणियों के आश्रम-स्थलों तथा रक्षित पक्षियों की सूचियां घोषित की हैं । भारतीय वन्य प्राणि मण्डल भी समय समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन करके पक्षियों के परिरक्षण के बारे में सिफारिशे करता रहना है ।

सहकारी भू-बधक बैंक

860. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि भूमि के विकास के लिये देश के सहकारी भू-बन्धक बैंकों द्वारा लगभग कितनी राशि के ऋण दिये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या कृषि-भूमि के विकास के लिये ऋण देने के लिये दीर्घ-कालीन निधि तैयार करने के बारे में सहकारी भू-बन्धक बैंकों ने जीवन बीमा निगम से कोई बातचीत की है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि इस कार्य के लिये वित्त निगम से उपलब्ध बड़ी निधि का उपयोग करने के लिये वे विशेष योजनायें तैयार करें ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) चौथी योजना के लिए मोटे-मोटे कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्थापित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि यदि द्रव्य बाजार की स्थिति संतोषजनक रही और साधन उपलब्ध रहे तो भूमि बन्धक बैंक चौथी योजना में कृषि-भूमि का विकास करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए दे सकेंगे। अन्तिम आंकड़े तब प्राप्त होंगे जब भूमि बन्धक बैंक और सम्बन्धित राज्य सरकारें अपनी अपनी योजनाएं बना लेंगी और प्रत्येक बैंक को ऋण देने की क्षमता के बारे में बताएंगी।

(ख) जीवन बीमा निगम के साथ अभी तक चौथी योजना के कार्यक्रम के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है।

(ग) जी हां।

दिल्ली में चावल मूल्य नियंत्रण

861. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली प्रशासन ने चावल की सभी किस्मों पर बासमती चावल सहित मूल्य नियंत्रण कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार बढ़िया किस्म के चावलों पर से नियंत्रण हटा लेने की दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय किसी भी किस्म के चावल पर से मूल्य नियंत्रण हटाने का विचार नहीं है।

राजधानी में दूध सम्भरण

862. श्री भागवत झा आजाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषिमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूध संभरण की स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास किये गये हैं उन से दिल्ली में सम्भरण की कुल मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को दूध देने के लिए स्थापित की जाने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हाल ही में विशेषज्ञों के एक दल ने दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूध के एकत्रिकरण का निरीक्षण किया । दल ने दूध की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाने की सिफारिश की थी । इन सिफारिशों में दिल्ली से 300 मील के अर्धव्यास के अन्तर्गत दूरस्थ स्थानों से दूध उपलब्धि करना तथा इन क्षेत्रों में पांच "वैलेन्सिग स्टेशन्स " की स्थापना करना भी शामिल था । इन क्षेत्रों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है । इन कदमों के परिणाम दूरगामी होंगे और इसलिए तुरन्त ही उन के परिणाम ज्ञात नहीं हो सकेंगे ।

इस समय दूध उपलब्धि के मौजूदा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं । इन के अतिरिक्त हाल ही में योजना ने दूध सम्भरणकर्त्ताओं के साथ "फर्म कन्ट्रैक्ट " किये हैं ताकि सारा वर्ष दुग्ध सम्भरण सुचारू रूप से चलता रहे ।

पंजाब के जीन्द क्षेत्र से भी दुग्ध उपलब्धि शुरू कर दी गई है और इस समय इस क्षेत्र से दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन 800 लिटर दूध इकट्ठा कर रही है ।

(ख) किथोर स्थित दुग्ध एकत्रिकरण तथा प्रशीतण केन्द्र से सहकारी आधार पर दुग्ध की उपलब्धि शुरू कर दी गई है । यह केन्द्र इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी डेरी संघ को सौंप दिया गया है । विशेषज्ञों के दल की सिफारिशों के आधार पर विकसित होने वाले नये क्षेत्रों से दुग्ध प्राप्ति भी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होगी ।

चुकन्दर से चीनी

863. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुकन्दर से चीनी निकालने के सम्बन्ध में प्रस्थापना अन्तिम रूप में स्वीकार कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी क्षमता तथा आर्थिकता का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) इस के परिणाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, अभी नहीं, बुआई और विधायन दोनों के परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग) जी नहीं, किन्तु चुकन्दर से शर्करा बनाने की क्षमता का पता लगाने के लिए एक पाइलट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

आदिवासियों की समस्यायें

864. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामान्त :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी राज्यों में ऐसे अधिकारियों की कमी है, जो कि आदिम जाति समस्याओं को सुलझा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). कुछ राज्य सरकारों और संघीय राज्य-क्षेत्रों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है । तथापि उन उत्तरों से, जो अब तक प्राप्त हुये हैं, विदित होता है कि बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मनीपुर और त्रिपुरा में अनुभवी पदाधिकारियों की कोई कमी नहीं है ।

आसम, उड़ीसा, पंजाब और लक्कदीव, मिनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूहों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

1. **आसाम** : अनुभवी पदाधिकारियों की कमी के कारण आदिम जाति के लोगों के लिए चालू की गई योजनाओं को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है । सम्पूर्ण राज्य को दृष्टि में रखते हुए यद्यपि कुछ मामलों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है किन्तु इस से आदिम जाति के लोगों के लिए चालू की गई योजनाओं को कार्यान्वित करने पर असर नहीं पड़ता है । तकनीकी कर्मचारियों की इस कमी को पूरा किया जा रहा है क्योंकि विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से सफल अभ्यर्थी मिलते रहते हैं ।

2. **उड़ीसा** : आदिम जातियों के लोगों की भाषा, उनकी संस्कृति और उन के जीवन के ढंग से परिचित पदाधिकारियों की कमी है । राज्य सरकार आदिम जातियों की प्रमुख भाषाओं को सिखाने के लिए एक संस्था खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है । पदाधिकारियों को सामाजिक विज्ञान टाटा संस्था, बम्बई में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त आदिम जाति स्थितिज्ञान एवं अध्ययन केन्द्र, भुवनेश्वर में भी ओरिएंटेशन प्रशिक्षण दिया जाता है ।

3. **पंजाब** : राज्य में लाहौल और स्पीति घाटी के पहाड़ी क्षेत्र ही केवल आदिम जाति के क्षेत्र हैं जहां अनुभवी पदाधिकारी नहीं जाना चाहते हैं । इस के अतिरिक्त वहां और कोई भी आदिमजाति समस्या नहीं है । राज्य सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रतिकरात्मक भत्ता/ प्रेक्टिस न करने का भत्ता (डाक्टरों के मामले में) देकर वेतन क्रम संबंधी उचित प्रोत्साहन दे रही है ।

4. **लक्कादीव मीनीकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह** : वहां केवल चिकित्सा पदाधिकारियों की कमी है । प्रशासन, केरल सरकार अथवा भारत सरकार के द्वारा योग्य पदाधिकारियों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है ।

Potato seeds from Burma

865. Shri Onkar Lal Barwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to satate :

(a) Whether it is a fact that India is importing potato seeds from Burma;

(b) if so, the value of seeds imported last year; and

(c) the steps Government propose to take to increase its production in the country and reduce the imports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) Rs. 8·88 lakhs C.I.F. in 1964.

(c) A scheme for the production of disease free certified seed-potatoes was formulated by the Government of India for inclusion in the Special Development Programme(Crush Programme)and circulated to State Governments and Union Territory Administrations for formulating schemes for implementation in the respectiveareas during 1964-65 and 1965-66. The scheme has sofar been sanctioned in Assam, Bihar, Orissa, Madras, Maharashtra, Mysore, Punjab, Kerala and Andhra Pradesh at a total cost of Rs. 16·86 lakhs. Proposals received from Gujarat, Rajasthan and Himachal Pradesh are under consideration.

Model Programmes for Potato Seed Development in the country have been circulated to State Governments and Union Territory Administrations for thier adoption.

Supply of Wheat to Punjab

**866. { Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P. H. Bheel**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Punjab Government have asked the Central Government to send wheat only by rail and not by road;

(b) if so, the action taken by Government; and

(c) the safeguards taken by Government to prevent the theft of wheat enroture ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No special measures have been taken. The usual security arrangements existing on railways take care of the wheat despatched to Punjab also.

गन्ने का भाव

867. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार और राज्यों के लिये गन्ने के बढ़े हुए भावों की घोषणा कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां बढ़े हुए भावों की पहले घोषणा की जा चुकी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में चीनी के कारखानों से कितनी राशि वसूल किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार ने गन्ने के चालू भाव में कोई सामान्य वृद्धि नहीं की है । गन्ना नियन्त्रण आदेश, 1955 की धारा 3ए (4) के अनुसार स्थापित गन्ना (अतिरिक्त) मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, पजाब, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित शर्करा कारखानों द्वारा 1958–59 और 1959–60 की फसलों में खरीदे गये गन्ने के बारे में अतिरिक्त भावों की घोषणा की है ।

(ग) इस घोषणा के अनुसार अब तक कुल देय राशि 6.51 करोड़ रुपये है । इस में शर्करा कारखानों द्वारा अपने फार्मों से खरीदे गये गन्ने के बारे में गन्ने के जो राशि देनी है, वह भी शामिल है ।

भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता

868. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). भूमिहीन निर्धनों सहित निर्धन व्यक्तियों के लिये कानूनी सहायता का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जहां तक सरकार को विदित है, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल भूमिहीन निर्धनों के लिये किसी राज्य सरकार ने कोई स्कीम नहीं बनाई है।

दूध की कमी

869. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 8 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना ने अन्य साधनों से दूध की कमी को दूर करने में अब तक क्या प्रगति की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध उपलब्धि के विषय में कुछ सुधार हुआ है। 1-3-1965 को इसने 1648 क्विंटल दूध प्राप्त किया जबकि 1-12-64 को केवल 989 क्विंटल दूध प्राप्त हुआ था।

पर्यटन सम्बन्धी प्रशिक्षण

870. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग ने विदेशी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध किया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने देशों के नागरिकों को लाभ हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादर) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना से जिन देशों को लाभ हुआ, उनकी संख्या 9 है। वे देश ये हैं :—

1. अफगानिस्तान
2. कम्बोदिया
3. इन्डोनेशिया
4. ईरान
5. ईराक
6. मलएशिया
7. नेपाल
8. फिलिपाइन्स
9. थाईलैंड

राज्यों को अनाज का भेजा जाना

871. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाये हैं जिनसे राज्य सरकारें यह महसूस करें कि अनाज के मामले में उन्हें अनाज के अपने संसाधनों पर ही निर्भर करना है केन्द्रीय सरकार पर नहीं ; और

(ख) इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये किन राज्यों ने उचित कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। तथापि, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं हो सकता है। राज्य सरकारों को इस बात का परामर्श दिया जा रहा है कि वे अपने अपने राज्यों में उपलब्ध खाद्यान्नों का अधिक से अधिक सम्भव उपभोग करें और केन्द्रीय स्टाक की सप्लाई पर कम से कम निर्भर करें।

(ख) सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं और केन्द्रीय स्टाक से दिये गये या राज्य के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों का वितरण नियमित रूप से कर रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

72. **श्रीमती रेणुका राय :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अल्पकालीन सुधार के लिये तदर्थ समिति की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ख) गत वर्ष प्रति दिन औसतन कितने हवाई जहाज डमडम, पालम और सान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर आये और कितने वहां से उड़े ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) समिति की रिपोर्ट का पहला भाग प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के दूसरे और अन्तिम भाग की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) पहली जुलाई, 1963 से 30 जून, 1964 तक की अवधि के दौरान, डमडम, पालम और सान्ताक्रुज पर रोजाना पहुंचने वाले और वहां से रवाना होने वाले विमानों की औसत संख्या निम्न प्रकार है :—

	पहुंच	छूट
सान्ताक्रुज	38	38
डमडम	54	54
पालम	16	16

Strike by Cranemen of Bombay Port

873. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some workmen including the crane drivers of Bombay Port went on strike on the 20th January, 1965 as a result of which loading and unloading of ships was held up; and

(b) if so, the reasons for the strike and the duration thereof ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). On January 20, 1965, about 380 workmen including crane drivers, majdoors and Lok Gate Staff of the Hydraulic Establishment, Alexan dra Dock in the Port of Bombay, stopped work at 8·10 A.M. as a protest against an alleged assault on a shifting-gang majdoor by a Head Foreman of a Stevedore Company. The strike was called off at 1·30 P.M. on the same day on an assurance given by the Bombay Port Administration that suitable action would be taken in the matter.

राजस्थान का रेगिस्तान

874. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेगिस्तान के आगे विस्तार को रोकने के लिये किये गये उपाय किस हद तक सफल हुए हैं ; और

(ख) क्या सरकार निश्चित समय-सीमा में उद्देश्य पूर्ति के लिये क्रम-बद्ध कार्यक्रम के रूप में बड़े पैमाने पर इन उपायों को अपनाने की स्थिति में है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेगिस्तान के और आगे विस्तार को रोकने के लिए अपनाई गई सफल तकनीकें ये हैं :—

(1) स्थान परिवर्तन करने वाले रेत के टीलों पर वनारोपण ।

(2) समुप युक्तरूप से तेज़ी से बढ़ने वाले विदेशी वृक्षों की किस्मों के साथ उष्मसह स्थानों पर वनारोपण ।

(3) वृक्षावलि तथा रक्षा पट्टियों को बढ़ाना ।

(4) प्राकृतिक चरागाह भूमि का दोबारा बोना और रेंज मैनेजमेंट पद्धतियां ।

(5) उन्नत संरक्षण खेती पद्धतियां ।

वातज भूरक्षण द्वारा आगे भूमि के खराब होने और रेगिस्तान के और आगे फैलने को रोकने में ये उपाय काफी सफल सिद्ध हुए हैं ।

(ख) जी हां, क्योंकि इसमें भारी धन-राशि लगनी है इसलिए समय की कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती ।

तिमाही अंशदान कार्ड प्रणाली

875. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि योजना में शामिल कोयला खानों में तिमाही अंशदान कार्ड प्रणाली आरम्भ करने की प्रस्तावित तारीख क्या है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के कोयला खान भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय के लिये इस बीच अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) 31 जनवरी, 1965 को कितने पद रिक्त थे और उन को नहीं भरने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1 अप्रैल, 1965 ।

(ख) इस समय किसी भी अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) अपर डिवीजन क्लर्कों के तीन पद । इन पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर शीघ्र भर दिया जायेगा ।

नेपाल से अनाज का लाया जाना

876. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार द्वारा नेपाल तराई से भारतीय सीमा को खाद्यान्नों के आने पर रोक लगाये जाने के कारण, बिहार के बैरागनियां एवं अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी हो गई है और इन स्थानों में चावल मिलें बेकार हो गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल तराई और भारतीय सीमा के बीच खाद्यान्नों के आने जाने में यथापूर्व स्थिति पुनः स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) नेपाल सरकार ने अपने कुछ जिलों से चावल और धान के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । इससे नेपाल तराई क्षेत्र से भारत में चावल और धान आना बन्द हो गया है और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में चावल उपलब्धि कुछ हद तक कम हो गयी है । बिहार की सीमा पर कुछ चावल मिलों के अस्थायी रूप से बन्द होने का यह भी एक कारण है ।

(ख) दोनों नेपाल तथा भारत द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्यात पर ऐसे अस्थायी प्रतिबन्ध जहां खाद्यान्नों की कमी है, कभी कभी लगाए जाते हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

877. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्ध सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी क्षेत्र में भविष्य निधि योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): जी, हां ; निम्न अपवादों सहित :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि, अधिनियम, 1952 की धारा 16(1) (क) के अन्तर्गत ऐसे किसी भी संस्थान पर लागू नहीं होता है जो सहकारी समिति 1912 के अन्तर्गत अथवा सहकारी समितियों से सम्बन्धित, तत्समय में लागू विधि के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया हो, जिसमें 50 से कम करते हों और जहां बिजली की सहायता के बिना काम किया जा रहा हो ।

(दो) औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित किये गये हथकरघा कारखानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पत्रकारों की शिक्षा सम्बन्धी यात्रायें

878. श्री जो० ना० हजारिका : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष में पत्रकारों की शिक्षा सम्बन्धी कितनी यात्राओं का आयोजन किया गया ;

(ख) इन यात्राओं पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या ये यात्राएं विदेशों में की गई थीं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). इस प्रश्न के भाग (ग) से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या इस संपूर्ण प्रश्न में माननीय सदस्य का तात्पर्य उन विदेशी पत्रकारों, फोटोग्राफरों जिन्हें शैक्षिक यात्राओं पर ले जाया गया था, या उन भारतीय पत्रकारों, फोटोग्राफरों से है जिनके लिये भारत तथा विदेशों में शैक्षिक यात्राओं की व्यवस्था की गयी थी ।

पर्यटन विभाग ने 1 अप्रल, 1964 से 31 जनवरी, 1965 तक विदेशी पत्रकारों, फोटोग्राफरों के लिये 28 और भारतीय पत्रकारों के लिये भारत में 9 शैक्षिक यात्राओं का प्रबन्ध किया । इन यात्राओं पर 38,462 रुपये 41 पैसे खर्च हुये ।

भारतीय पत्रकारों, फोटोग्राफरों के लिये किसी भी विदेशी यात्रा का प्रबन्ध नहीं किया गया है

पर्यटन केन्द्रों के लिए बृहद् योजना

879. श्री जो० ना० हजारिका : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुने हुए पर्यटन केन्द्रों/क्षेत्रों के सामन्वित विकास की बृहद् योजनाओं (मास्टर प्लान) को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) क्या इस बीच बृहद् योजना के अन्तर्गत आसाम-मनीपुर-नागालैंड-त्रिपुरा-नेफा में किसी पर्यटन केन्द्र/क्षेत्र का विकास किया गया है ; और

(ग) 1964–65 के बजट के आवंटन में से कितनी राशि केवल इस कार्य के लिये उपयोग की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पर्यटक विभाग द्वारा गठित किये गये कार्यकारी दल ने अभी तक निम्न केन्द्रों पर प्राथमिक रिपोर्टें दे दी हैं :—

1. कोवलम्
2. अजन्ता-ऐलोरा, औरंगाबाद संश्लिष्ट
3. कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी संश्लिष्ट
4. गोआ
5. खुजराहो
6. आगरा, फतेहपुर सीकरी, घाना पक्षिशरण स्थान संश्लिष्ट

विस्तृत योजना तैयार करने का प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है ।

(ख) आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, नेफा में समाकलित आधार पर कोई केन्द्र/क्षेत्र अभी तक विकसित नहीं किया गया है । विदेशी पर्यटकों के जाने के बारे में नियंत्रण होने के कारण कार्यकारी दल ने इन क्षेत्रों का अभी तक परीक्षण नहीं किया है ।

(ग) आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, नेफा में चुने हुये पर्यटक केन्द्रों की मास्टर योजना बनाने के लिये 1964–65 के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन में कोई बजट संबंधी व्यवस्था नहीं की गई है ।

नारियल उत्पादन

880. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के हेतु संकर (हाइब्रिड) नारियल के पौधे उगाने के प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार एक समिति स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कब स्थापित होने की संभावना है ; और

(ग) इसके सदस्य कौन होंगे और यह अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ने सके लिए जनवरी, 1965 में एक उप-समिति की स्थापना की है ।

(ग) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

(1) डा० एस० एम० सिक्का, कृषि आयुक्त, भारत सरकार ।

(2) श्री सी० एम० जोन, सदस्य, भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ।

(3) डा० एम० एस० स्वामीनाथन, प्रमुख, वनस्पति विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।

आशा है कि उपसमिति 3-4 मास तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

उर्वरकों के स्टाक का जमा होना

881. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वा नांगल और रूरकेला के उर्वरक कारखानों में उर्वरक का कुछ स्टाक जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टाक को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

सहकारी खेती

882. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में राज्यवार सहकारी खेती सम्बन्धी कितनी अग्रिम परियोजनायें वास्तव में आरम्भ की गई हैं ; और

(ख) 1965-66 में राज्यवार सहकारी खेती के कितने विंग स्थापित किये जायेंगे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण, जिसमें राज्यवार संख्या दी गई है, संलग्न है ।

(ख) 1965-66 में फुलिया, पश्चिमी बंगाल में एक सहकारी खेती प्रशिक्षण विंग स्थापित किया जाएगा । जम्मू तथा काश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में एक-एक सहकारी खेती प्रशिक्षण विंग पहले ही स्थापित कर दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	1964-65 में अब तक स्थापित की गई अग्रिम परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	—
2	असम	—
3	गुजरात	1
4	बिहार	—
5	जम्मू तथा काश्मीर	—
6	केरल	—
7	मध्य प्रदेश	5
8	मद्रास	—
9	महाराष्ट्र	2
10	मैसूर	4
11	उड़ीसा	2
12	पंजाब	3
13	राजस्थान	1
14	उत्तर प्रदेश	—
15	पश्चिमी बंगाल	—
16	संघ क्षेत्र	2
		20

उड़ीसा में अनधिसूचित जातियों का कल्याण

883. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में अनधिसूचित जातियों के कल्याण की योजनायें आरम्भ करने के लिए उड़ीसा राज्य को कोई राशि मंजूर की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

(क) जी, हां :

(ख)

I—शिक्षा (रुपये लाखों में)

1. पूर्व-मेट्रिक वृत्तिकायें . . .	0.10
2. रिहायशी स्कूल . . .	1.50

II—अन्य योजनायें

1. उपनिवेशन योजना (गृह निर्माण) .	0.63
2. कृषिगत तथा औद्योगिक सहायता के लिए वित्तीय सहायता . .	0.25
3. कुओं का खोदा जाना .	0.15
योग	2.63

(ग) वर्ष 1964-65 अभी समाप्त नहीं हुआ है। वर्ष समाप्त होने के पश्चात् ही मालम हो सकेगा कि राशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है अथवा नहीं।

उड़ीसा में आदिवासी खंड

884. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय आदिवासी खंडों की संख्या क्या है ;

(ख) 1965-66 में कितने ऐसे खंड खोलने का विचार है; और

(ग) 1965-66 में उड़ीसा के कोरापुट और गंजम जिलों में कितने-कितने आदिवासी खंड खोलने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

(क) 41 आदिमजाति विकास खण्ड।

(ख) 21 आदिम जाति विकास खण्ड।

(ग) 1965-66 में कोरापुट जिले में 12 आदिवासी विकास खण्ड खोलने का विचार है और गंजम जिले में एक भी आदिमजाति विकास खंड खोलने का विचार नहीं है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए छात्रावास

885. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास खोलने का विचार है; और

(ख) राज्य में इस अवधि में ऐसे छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

		छात्रावासों की संख्या
(क)	अनुसूचित आदिम जातियां . .	21
	अनुसूचित जातियां . .	25
		(रुपये लाखों में)
(ख)	अनुसूचित आदिम जातियां . .	3.00
	अनुसूचित जातियां . . .	3.00

भारत का भूमि सर्वेक्षण मानचित्र

886. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बाल्मीकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश के लिए भारत का भूमि सर्वेक्षण मानचित्र तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण मानचित्र पूर्णतः तयार कर लिए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उपलब्ध दित्ता के संग्रह तथा मिलान से 1960 में तैयार किया गया भारत का एक अस्थायी भूमि मानचित्र उपलब्ध है । फिर भी भूमि संरक्षण तथा भूमि विकास कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाने और

उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक अधिक विस्तृत मानचित्र की आवश्यकता है । ऐसा एक मानचित्र तैयार करने के लिए अखिल भारतीय भूमि तथा भूमि प्रयोग सर्वेक्षण संगठन ने आवश्यक दिशा संग्रह करना शुरू कर दिया है। इस समय प्रमुख नदी-घाटी परियोजनाओं के जलग्रह क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है ।

(ख) जलग्रह तथा जलग्रह के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में 223 लाख एकड़ भूमि का विस्तृत तथा सूक्ष्म निरुपण सर्वेक्षण हो चुका है ।

विश्व बैंक के परिवहन विशेषज्ञ

887. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक से परिवहन विशेषज्ञों का एक दल अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए परियोजनाओं को चुनने के बारे में चर्चा करने के लिए हाल ही में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायता देने के लिए कौन-सी परियोजनायें चुनी गई हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व बैंक दल ने सड़कों और पत्तनों की कुछ परियोजनाओं के बारे में केवल प्राथमिक विचार विमर्ष किया था । अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् से वित्तीय सहायता देने के लिए कोई भी नई परियोजना अभी तक चुनी नहीं गई है ।

नेशनल शुगर मिल्स लिमिटेड

888. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :
डा० सारादीश राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या नेशनल शुगर मिल्स लि० अहमदपुर जिला बीरभूम (पश्चिमी बंगाल) के मामलों की जांच करने के लिए औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत समिति की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बीज के फार्म

889. **श्री कृष्णपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री 8 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित विभिन्न प्रकार के फार्मों के सम्बन्ध में उसमें पूछी गई जानकारी अब एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अधिकतर राज्यों तथा केन्द्रीय संगठनों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी कर ली गई है। अभी तक आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीज फार्मों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें स्मरण करा दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3950/65]**

गेहूं और चावल के दाम

890. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच गेहूं और चावल के दामों के बारेमें गम्भीर मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). गेहूं और साधारण चावल के भावों के बारे में कोई मत-भेद नहीं है। केन्द्रीय सरकार के स्टाक से दिये जाने वाले बढ़िया किस्मों के चावल के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार ने कम भाव सुझाए थे। इस मामले पर केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार की बातचीत हुई थी और एक निर्णय हो गया था।

डेयरी विकास परिषद्

891. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसवन्त :
श्री दे० जी० नायक :

क्या क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद् की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिषद् के कार्य और उन कार्यों की योजना क्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास मण्डल की स्थापना पर विचार हो रहा है । उसके मुख्य उद्देश्य ये हैं :—डेरी विज्ञान तथा कार्य-प्रणाली को उन्नत करना और तकनीकी ज्ञान का विस्तार करना, केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये किसी डेरी संयंत्र को परामर्श देना, किसी डेरी की रूपरेखा बनाने में भारत सरकार, राज्य सरकारों, निगम अथवा स्थानीय निकाय को परामर्श देना, मूल्य निर्धारण, मूल्य नीति, सार्वजनिक सम्बन्धों पर परामर्श देना, दूध एवं दूध से बने पदार्थों के गुण सम्बन्धी नियन्त्रण को बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी कार्यक्रम का आयोजन करना, दूध का उत्पादन और/या भारवाही क्षमता की वृद्धि के लिए पशुओं को सुरक्षित रखना और उनमें सुधार करना, डेरी प्रबन्ध, डेरी उद्योग को उन्नत करना और देश में डेरी विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये ऐसे ही अन्य कार्य करना ।

भारतीय नौवहन टन-भार

892. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन टन भार और इसके द्वारा संचालित व्यापार (समुद्रपार व्यापार को मिला कर) के परिमाण की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) अगली योजना में विकास का क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पहली मार्च, 1965 को भारतीय जहाजों का टनभार कुल 14,16,770 रजिस्टर्ड टन था । 1963 के केलेन्डर वर्ष में भारतीय जहाजी कंपनियों ने 82.70 लाख मीटरी टन माल चढ़ाया-उतारा । 1964 की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 5 लाख कुल रजिस्ट्री टनभार के अतिरिक्त जहाजों के, जो बन रहे हैं, मिलने पर यह आशा की जाती है कि चालू आयोजना के अन्त तक भारतीय जहाजों का परिचालन टनभार 15 लाख कुल रजिस्ट्री टनों तक पहुंच जायेगा । आगामी आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परंतु वर्तमान विचारधारा के अनुसार पांचवीं आयोजना के शुरू में कुल 5 लाख रजिस्ट्री टन भार के और जहाजों के प्राप्त होने पर टनभार का लक्ष्य 30 लाख कुल रजिस्ट्री टन (परिचालिनीय) हो जायेगा ।

Scarcity Areas in Rajasthan

893. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri P. L. Barupal :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Y.D. Singh :
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that almost 200 Villages in the districts of Alwar and Jaisalmer in Rajasthan have been declared by the State Government as 'scarcity areas' ; and

(b) if so, whether the Union Government have provided any help or assistance to the inhabitants of these Villages ?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (ri Shah Nawaz Khan) : (a) The State Government of Rajasthan have declared 41 villages in Alwar District and 165 villages in Jaisalmer District as 'scarcity areas'. The villages in Alwar are reported to have been affected by floods and those in Jaisalmer by drought.

(b) Two grants, one of Rs. 49,000/- and another of Rs. 28,000/- have been sanctioned out of the 'Indian People's Trust Fund' for relief in areas affected by drought in 1964.

अगरतला-कलकत्ता विमान किराया

894. **श्री दशरथ देब :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा सरकार से 1964 और 1965 में कलकत्ता से अगरतला का विमान किराया (यात्री) कम करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन विशेष रूप से घटाये हुए किराये पर कलकत्ता/अगरतला/खोवाई/कमालपुर/कैलाशहर की एक मितव्ययी सेवा चला रहा है । 1958 से इस सेवा के किराये में कोई तबदीली नहीं हुई है । ईंधन पर बढ़ी हुइ लेवी और चालान खर्चों में बढ़ोतरी के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों के कुछ हिस्से की पूर्ति के लिए जून, 1963 में आई०ए०सी० के किराये की दरों में संशोधन किया गया । कलकत्ता और अगरतला के बीच डकोटा सेवाओं पर किराये, दूसरे क्षेत्रों की तरह उसी मात्रा में नहीं बढ़ाये गये । पाकिस्तान की सीमा के ऊपर उड़ते समय वायुयानों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले मार्गों में कुछ तबदीलियों के कारण, जिससे कि कलकत्ता और अगरतला के बीच के मार्ग की लम्बाई 196 मील से बढ़कर 224 मील हो गयी, कलकत्ता और अगरतला के बीच किराये और माल भाड़े की दरें मालभाड़ा चार्टरों के लिए 15-8-64 से और अनुसूचित सेवाओं के लिए 15-9-64 से बढ़ानी पड़ीं । इस संबंध में स्थिति त्रिपुरा प्रशासन को बता दी गयी थी ।

कृषि वर्ग की संग्रह क्षमता

895. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि देश के कृषि वर्ग के पास खाद्यान्नों के संग्रह करने की कितनी क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस बात के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि कृषिकों के पास से खाद्यान्न बाजार में बराबर आते रहें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है परन्तु बाजार में कम आमद होने से यह स्पष्ट है कि उत्पादक की अपने पास स्टाक रखने की क्षमता बढ़ गयी थी और उनमें से कुछ फसल के बाद के समय में ऊंचे भावों पर बेचने की आशा में अपने पास स्टाक रखे हुए थे ।

(ग) सरकार ने प्रमुख खाद्यान्नों के सहारा देने के भाव घोषित कर दिए हैं और घोषित संग्रहण स्थलों पर अनाजों की जितनी मात्रा दी जाएगी सरकार उन भावों पर खरीदने के लिए तैयार रहेगी । कुछ खाद्यान्नों के नियन्त्रित भाव भी घोषित किए गए हैं ।

देहाती जनसंख्या

896. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहाती जनसंख्या और उस के आर्थिक विकास संबंधी आवश्यकताओं के बारे में हाल ही में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) बढ़ती हुई जनसंख्या को, जो कहा जाता है कि 1961--71 की दशाब्दी में 23 प्रतिशत बढ़ जायेगी, रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ग्रामीण जनसंख्या का देशवार सर्वेक्षण नहीं किया गया है । लेकिन कार्यकारी ग्रुप जो कृषि तथा उद्योग के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्ताव बनाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, ने 1960-61 की तुलना में 1970-71 तक तेहाती क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकताओं में जो वृद्धि होने की संभावना है उसके विषय में अनुमान तैयार कर लिए हैं ।

(ख) खपत की आठ श्रेणियों की मदों के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं की वृद्धि-दर के बारे में कुछ बताने वाला एक विवरण नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०--3951/65]**

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया है :—

1. परिवार नियोजन के शिक्षात्मक पहलू को दृढ़ और विस्तृत करना ।
2. गर्भरोधक वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में सम्भरण ।
3. गर्भरोधक वस्तुओं का देश में उत्पादन ।
4. समस्त स्तरों पर प्रशासकीय मशीनरी को सुदृढ़ करना ।
5. कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवश्यक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण ।
6. जन-विद्या, औषध और जीव विज्ञानीय पहलुओं एवं संचार में अनुसन्धान ।
7. मूल्यांकन ।

उड़ीसा में पैकेज प्रोग्राम

897. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1965–66 में उड़ीसा में कोई पैकेज प्रोग्राम चालू करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या उड़ीसा में 1965–66 में पैकेज प्रोग्राम के लिए कोई अनुदान या ऋण मंजूर किया गया है या किये जाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) उड़ीसा के संबलपुर जिले में सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) पहले से ही चालू है । यह कार्यक्रम 1962–63 में शुरू किया गया था और 1965–66 में भी चलता रहेगा । इसके अतिरिक्त धान तथा अन्य प्रमुख फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कटक, गंजम, बालासार तथा भोलंगीर के जिलों में एक सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया है । यह कार्यक्रम 1964–65 के खरीद के मौसम से शुरू किया गया है और यह 1965–66 में भी चलता रहेगा ।

(ख) और (ग) अनुमान है कि 1965–66 की अवधि में सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा 30 लाख रुपए होगी । इसमें वह अल्पकालिक ऋण शामिल नहीं है जो कि विभिन्न कृषि आदानों की खरीद के लिए सहकारी तथा अन्य निकायों के माध्यम से कृषकों को दिया जावेगा ।

Gir Lions in Gujarat Forest

898. Shri Baswant : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the multiplication of the Gir Lion species has gone down in the Gir Forest; and

(b) whether any steps have been or are proposed to be taken to check this; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No Sir. In the census carried out by Forest officials in 1963 the number of lions counted was 286. This was exclusive of 18 lions that had been suppied to others within the preceding eight years.

(b) Since there has been no decrease in the number of lions, the steps already taken by the State Government of Gujarat for affording complete protection to lions are considered sufficient.

धान की खेती

899. **श्री परमशिवन :**
श्री म० प० स्वामी :
श्री अरूणाचलम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के एक कृषक ने धान की खेती का एक सुधरा हुआ तरीका निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे लोक प्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बताया गया है कि उड़ीसा राज्य के एक कृषक ने सुधरे हुए तरीकों से धान की खेती करके 1480 किलोग्राम प्रति एकड़ की उपज प्राप्त की जब कि इससे पहले वह केवल 370 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपज प्राप्त कर सका था ।

(ख) कृषक द्वारा अपनाई गई पद्धति को लोकप्रिय बनाने से पहले उड़ीसा का कृषि विभाग तथा केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, कटक इस पद्धति के बारे में जांच-पड़ताल कर रहे हैं ।

उर्वरक की मांग

900. **श्री तन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1963-64 में ऐमोनियम सल्फेट, डबल साल्ट, युरिया और कैल्सियम नाइट्रेट की कितनी-कितनी मात्रा में मांग की ;

(ख) केन्द्रीय उर्वरक पूल से इन वस्तुओं की किस मात्रा तक पूर्ति की गई ; और

(ग) यदि इस में कोई कमी रही तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी निम्न विवरण में दी गई है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

उर्वरक की किस्म	1963–64 में मांगी गई मात्रा	31–3–64 तक केन्द्रीय उर्वरक पूल से जितनी वास्तविक मात्रा दी गई ।	कमी के कारण
अमोनियम सल्फेट	17,000	7,568	संभरण की कमी के कारण मांग की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं हो सकी। इस से अतिरिक्त अलाट हुई मात्रा में से लगभग 3,600 मीटरी टन को राज्य सरकार ने उठाया ही नहीं और इसलिए यह मात्रा रद्द कर दी गई ।
डबल साल्ट (ए०एस० एन०)	6,000	456	सिन्दरी कारखाने में सीमित उत्पादन होने के कारण अलाट-मेंट कम हुई ।
यूरिया	8,000	1,653	यद्यपि राज्य सरकार को 71,000 मीटरी टन यूरिया अलाट किया गया था , परन्तु वह केवल 1,920 मीटरी टन के लिए ही प्रेषण निर्देश जारी कर सकी ।
कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट	10,500	15,114	अलाटमेंट मांग से अधिक थी और यह सल्फेट आफ अमोनिया तथा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के कम सम्भरण की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया था ।

कृषि के आधुनिक औजारों को लोक प्रिय बनाना

901. **श्री तन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के हेतु आधुनिक औज़ारों को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र की ओर से कितनी सहायता दी गई ;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को कितने-कितने प्रतिशत राज सहायता दी गई ; और

(ग) सब को समान प्रतिशतता के आधार पर राज सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शानहवाज खां) : (क) केन्द्रीय सरकार उन्नत औज़ारों के खर्च पर 25 प्रतिशत तक उपदान देती है ।

(ख) संघ क्षेत्रों की विशेष विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्हें मिलने वाले केन्द्रीय उपदान की मात्रा को 10 जून, 1963 से एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था । दिल्ली, मनीपुर तथा अन्डेमान निकोबार द्वीपों की प्रार्थनाओं पर इन संघ क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय उपदान की मात्रा को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है । यह बढ़ोतरी तीसरी योजना की अवधि तक की गई है ।

(ग) असाधारण स्थिति वाले संघ राज्यों के अतिरिक्त, बाकी समस्त संघ क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय आधार पर पहले से ही उपदान की एक जैसी पद्धति अपनाली गई है ।

चुकन्दर

902. **श्री तन सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के पचपदरा, फलोदी और पोकरण क्षेत्रों की लोनी भूमि में चुकन्दर को उगाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब मामला किस अवस्था में है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि चुकन्दर उगाने के लिए इन क्षेत्रों में अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री आर० नारायण स्वामी का, जो दूसरी लोक-सभा (वर्ष 1957 से 1962 तक) के सदस्य थे, की 71 वर्ष की अवस्था में पावरम् में 6, मार्च 1965 को देहान्त हो गया है ।

सदस्य गण शोक प्रकट करने के लिए थोड़ी देर तक मौन खड़े हो जायें ।

इस के पश्चात् सदस्यगण कुछ समय के लिये मौन खड़े रहें ।

Members then stood in silence for a short while.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने केरल में साम्यवादियों के निरोध पर एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी है किन्तु ऐसा विदित हुआ है कि इसे कुछ दिनों के लिए रोक लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कल एक वक्तव्य दिया जा रहा है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान के डाकुओं द्वारा पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित राजस्थान के गांवों में हरिजनों की बड़ी संख्या में हत्या तथा उन पर हमले क समाचार ।

श्री बूटा सिंह (मोगा): अध्यक्ष महोदय , मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान के डाकुओं द्वारा पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित राजस्थान के गांवों में हरिजनों की बड़ी संख्या मे हत्या तथा उन पर हमले के समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमन्, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा पर हरिजनों की बड़े पैमाने पर हत्या की कोई घटना नहीं हुई । जनवरी, 1964 से 15–2–1965 तक की अवधि में एक भारतीय नागरिक की हत्या हुई । 7 मामलों में भारतीय नागरिकों को चोटें भी आईं । इस क्षेत्र में डाकू दल थे । जो हत्या, डाकेजनी, आक्रमण आदि जैसे भयंकर अपराध करते थे। राजस्थान पुलिस तथा पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा चलाये गए संयुक्त अभियान के फलस्वरूप बहादुर सिंह के गरोह को छोड़कर सीमा के इधर-उधर डाका डालने वाले डाकू-दल समाप्त हो गए । बहादुर सिंह का गिरोह अभी तक सक्रिय है और बड़े अपराध, सम्पत्ति और मवेशियों की चोरी आदि करता रहता है । सूचना मिली है कि यह गिरोह सीमा पर पाकिस्तानी क्षेत्र में शरण लेता है ।

पाकिस्तान पुलिस के सहयोग से इस गिरोह को समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आर० ए० सी० और पुलिस को नियुक्त कर के राजस्थान-पाकिस्तान सीमा को व्यावहारिक रूप से बन्द कर दिया गया है। पुलिस की गश्त भी तेज कर दी गई है। इस के परिणामस्वरूप स्थिति बहुत सुधर गई है।

Shri Buta Singh : From the statement it appears that one person was killed and some were injured. It has also appeared in the newspapers that certain crimes were committed by this gang such as cutting of noses, arms etc. May I know whether the Government of India have written to the Government of Pakistan to take this gang of Bahadur Singh in their custody; and whether the Government contemplate to give arms or pieces of advice to those Harijans so that they may protect themselves ?

श्री हाथी : मैंने बहादुर सिंह के डाकुओं को गिरोह द्वारा किये गये सभी प्रकार के अपराधों के बारे में अपने वक्तव्य में बताया है। राजस्थान पुलिस पाकिस्तान सरकार के सहयोग से इस गिरोह को समाप्त करने के लिए कदम उठा रही है। जहां तक हथियार अथवा सलाह देने का सवाल है, यह राजस्थान सरकार का विषय है, हम इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से बातचीत कर रहे। **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The main reason for harassing of and the the attrocities committed against those Harijans by this Bahadur Singh gang, as reported in the 'Nav Bharat Times' is that the Harijans of this area supported the Congress which won the electons there. May I know whether the Central Government propose to take up this matter in their hand and take stringent measures in regard to their arrest ?

Shri Hathi : As I said that whatever information is available with me has been furnished by the Rajasthan Government I cannot have the detailed information regarding each and every incident taking place in Rajasthan State.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether an adequate border force has not been stationed there as these decoits are operating in that area at their own will ?

Shri Hathi : The Government are taking all necessary measures to arrest them.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सीमान्त क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों को हथियारों के लाइसेंस उदारता से मंजूर करने की कोई योजना है जिस से कि वे लोग पाकिस्तानी डाकुओं का मुकाबला कर सकें ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा यह विषय राजस्थान सरकार का है और हम इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत कर रहे हैं।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, decoits loot the rich and crimes. such as chopping of nose, arms etc. are committed by them to extract money. May I, therefore, know the motive of the attrocities being committed against those poor Harijans by this gang ?

श्री सोलंकी (कैरा) : यह सीमान्त क्षेत्र हिन्दुस्तान और पाकिस्तान क बीच में है। क्या केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है ।

श्री हाथी : राजस्थान सरकार ने पहिले भी अन्य दस्यु-दलों को, जो कि वहां डाका डालते थे, समाप्त किया है और वह अब भी प्रयत्नशील है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : (जालोर) : केन्द्रीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व है ;

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य के बारे में वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य के बारे में वर्ष 1963–64 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3945/65 ।]

भारतीय विमान (पहला संशोधन) नियम

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत दिनांक 23 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 129 में प्रकाशित भारतीय विमान (पहला संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3946/65 ।]

उर्वरक (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 9 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 74 में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3947/65 ।]

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने एक अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी हुई है, और नियमों के अनुसार उसे सभा का कार्य प्रारम्भ करने से पहिले लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि नियम 198 के अन्तर्गत मुझे मंत्रि-परिषद् अविश्वास-प्रस्तावों की चार सूचनायें मिली हैं।

पहली सूचना श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने दी है। उनका प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।"

जो सदस्य इस प्रस्ताव पर अनमति देने के पक्ष में हों, वे कृपया अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

मैं देखता हूं कि 50 से अधिक सदस्य खड़े हुये हैं। अतः अनुमति दे दी गई है। सभा को प्रस्ताव को लेने की तारीख तथा समय के बारे में निश्चय करके बाद में सूचित कर दिया जायेगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप उन अन्य सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दें, जिन्होंने इस प्रकार की सूचनायें दी हुई थीं।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। यदि यह प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होता, तो मैं दूसरा प्रस्ताव को ले लेता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप समय बाद में निर्धारित कर सकते हैं, किन्तु क्या आप तिथि को अभी निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री भी सदन में उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रधान मंत्री जी और विरोधी दलों को परामर्श करना है, अतः मैं परामर्श करने के पश्चात् ही घोषणा करूंगा।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : यदि सदन सरकार में अविश्वास करे, तो सरकार आगे काम कैसे कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे आय-व्ययक को लेंगे ....

श्री नाथ पाई : मैंने आपको अपने प्रस्ताव की एक सूचना दी है ....

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में अपना निर्णय उनके पास भेज दूंगा।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET-GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वर्ष 1965-66 के लिए रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी। श्री गो० ना० दिक्षित अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

Shri G.N. Dixit (Itarsi): Mr Speaker, Sir, the successful operation of our railways is very essential for the security of our social life and the defence of our country. In our country, both in the Public and the Private Sectors,

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr.Deputy Speaker *in the Chair*]

the Railways are a biggest industry, Half of our total funds is invested in the Railways and experienced people are working in this organisation. Thus if there is no profit or almost a negligible profit, it will be a blow to the Public Sector and the socialistic pattern of our society. So far the successful operation of the railways, it should be run or commerical basis and not like a Government Department and it should allocate more fund for the Central Budget.

Recently we have solved the problem of shortage of coal by introducing the diesel and electric locomotives. There is a scope for effecting economy in the various wings of the railways. The difficulties of the passengers travelling in the third class still persistently continue and are yet to be looked into. I may suggest that the Railway authorities should take steps to check overcrowding in the said class by way of introducing Reservation System for all the seats. I further suggest that so far the seating capacity is concerned the rules and regulation applicable to the First class compartments of Railways and buses throughout India may also be extended to the third class compartments.

I would like to point out the running allowance which is admissible to the Guard and the Brake-man is not given to the Condctor and the Trave Ticket Checker. This is possibly because of the fact that these persons may be having some illegal income from passengers. This is possibly a false assumption andeverybody connot be dishonest, hence this allowance may also be given to them.

In spite of the fact that there are a number of experienced, efficient and honest officers in the Railways. but the required standard of discipline lac s among them, hence there is also a need to develop morale and discipline in the railway personnel.

I learn it from the Annual Report of the Railway Ministry that they are creating a new Zone in Secunderabad and a large sum of 3 crores of rupees is being spent for its set-up. I think that it would not be economical to spend such a huge amount to set-up this new Zone. On the contrasy.this very amount can be utilised for more useful purposes if the funds allocated for the purpose could be diverted to the Central Budget.

In the end, I would like to invite your attention to one more point about my constituency. The revines of the Jamuna and the Chambal are infested with decoits and thus for purposes of security bridges are being constrcuted across the Jamuna and the Chambal. In this very area a distance of near about, 20 miles remains without railway-line. If it is connected by railways, it would be of great use to the Government and the public as well.

श्री सोनावाने (पेंढरपुर) : मैं रेलवे मंत्री तथा उपमंत्री को उनकी दूरदर्शिता, योग्यता तथा बुद्धिमत्ता पर बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि मालूम नहीं वे क्यों एक ऐसी बात करने को तैयार हो गये हैं जो कि रेलवे के हित में नहीं है । दक्षिण केन्द्रीय ज़ोन के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । 1952 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने रेलवे कर्मचारियों को

[श्री सोनावने]

आश्वासन दिया था कि जब भी पुनर्गठन किया जायेगा अथवा नया ज़ोन बनाया जायेगा तो रेलवे कर्मचारियों तथा कर्मिक संघों से परामर्श किया जायेगा परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और विभिन्न समितियों को सिफारिशों का रद्द करके यह ज़ोन बनाया गया है। विशेष रूप से कुंजरू समिति ने सिफारिश की थी कि कम से कम दो और ज़ोन बनाये जायें। इन सभी विशेषज्ञ समितियों ने यह कहा है कि पुनर्गठन सम्बन्धी संचालन कार्यक्षमता, कार्य भार, लाईनों की लम्बाई और अन्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। इससे भविष्य में पुनर्गठन पर प्रभाव पड़ेगा। मामले के इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस नये खंड के बनाने से प्रशासनिक व्यय पर पहले से पड़े बोझ में और वृद्धि होगी मेरे विचार में सब से अच्छा यह होता यदि सभी विभागों का डिवीज़न स्तर पर अथवा ज़ोनों के स्तर पर पुनर्गठन किया जाता। केन्द्रीय रेलवे का शोलापुर डिवीज़न एक बहुत छोटा डिवीज़न है। यदि रेलवे मंत्रालय इस प्रकार के पुनर्गठन से पीछे नहीं हटना चाहता तो उसे कम से कम कुछ परिवर्तन तो करने चाहिये। शोलापुर डिवीज़न में परिवर्तन किया जाना चाहिये और पुनर्गठिन सम्बन्धी कुछ विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिये।

छोटी लाईन सम्बन्धी यह नीति निश्चित की गई थी कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़ कर छोटी लाइन समाप्त कर दी जायेगी परन्तु 1950 से लेकर अब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मैं इस सदन का 1950 से सदस्य हूं और मैंने इस मामले को कई बार उठाया है।

ऐसी ही एक महत्वपूर्ण छोटी लाइन मेरे निर्वाचन क्षेत्र हाकर बरास्ता कुरदुवादी लातूर से भिराज जाने वाली बरसी लाईट रेलवे की लाइन है। पेंढरपुर तीर्थ यात्रा का एक केन्द्र है और वहां वर्ष में पांच बार लाखों लोग यात्रा के लिए जाते हैं। लोक छत पर बैठ कर और पायदान पर खड़े हो कर जाते हैं। स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म नहीं है और यात्रियों के लिए कोई सुविधायें नहीं हैं। इस लाइन को शीघ्र ही बड़ी लाइन अथवा मीटर गेज में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित स्थानों पर उन्हें नहीं रखा जाता है। पदौन्नति का भी ध्यान नहीं रखा जाता है।

मैं विभागीय भोजन व्यवस्था का समर्थन करता हूं। यह अच्छी बात है कि इस से लाभ हो रहा है। अनुसूचित जातियों के अधिक लोगों को इस काम पर लगाया जाना चाहिये।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Mr. Deputy-speaker, Sir, this Railway budget leads us towards development and expension since it provides for introduction of new lines, electrification and dieselisation.

Third class passengers constitute 97 per cent of total passengers and a large portion of the income of the railways comes from them, but the amenities provided for themare distressing. No facility is available at way side stations near the villages.

Enhancement of fares in other classes may be justified but a majority of the members of this House have rightly opposed the in crease in the third class fares. Almost double the number of passengers travel in a third class compartment more than its normal capacity. When the train stops at a station it seems as if a crowd has attached the train. Dehra Dun Express going from Dehra Dun to Calcutta is fully packed. There is a particularly heavy rush on Tuesdays and Fridays of the passengers going towards Calcutta. To cope with overcrowding the number of Janta trains on long routes and local trains on short routes should be increased. I would request the Minister not to increase the fare upto fiftykilometers because that would affect the lower classes.

The number of Railway hospitals and health units is inadequate. Health units should be opened even at small stations. No doctor should be posted in the same hospital for more than three years. A doctor in the Banaras hospital is working there since nine years. A number of complaints have been made against him but no action has so far been taken. Such a step would help in the eradication of corruption. Detailed recommendations have been made in the report of Kripalani Committee in this connection.

Store Controllers are working in the stores of Zonal railways. Their maximum tenure is three years. It has been complained that they are allowed to continue for a longer period. A similar complaint has been made against the controller of Northern Railway stores at Baroda House. There is a general complaint that high railway officers stationed at Delhi are not transfered from here.

Casual labourers have been working for over twelve years but they have not been Confirned. These people also do an important service to the Railways. Gangmen belong to this class . Attention should e paid to thier case.

Allotment of the quarters should be made without any delay. It some time happens that a number of quarters remain vacant for want of allotment for over a period of six months which results in a major loss to the railways and the staff. There is a shortage of quarters in Delhi.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The Railway Minister has presented his Budget withgreat care and cleverness, but I have to say that a poor man travelling in third class has not been properly treated.

I have also to congratulate him for making provision from the stoppage of Janta train at Lakheri Indergarh stations in Kotah with effect from 1-4-65 and also for providing a sum of Rs. 31,000/- in the Budget for the survey work from Kotah to Chittorgarh.

It has been stated that the fare has been increased only beyond 6 kms., it would have been better if this distance could be raised to 50 kms to avoid hardship to the poor.

In Railways, corruptiont, negligent, floods, fires etc. accounted for lakhs of rupees and this loss has been tried to be made good by raising the fare of thrid class journey. True that the Railway Minister tries hard to avoid such happenings but his subordinate need pulling up.

[Shri Onkar Lal Berwa]

The Vigilance Department in the Railways also needs attention, in one case they have caught innocent persons and let off the guilty on the charge of drinking in the canteen. After spending thousands of rupees the innocent ones were reinstated in Service. Rs. 60,000 are spent every month on this Department and this is how they work.

Rajasthan is the most backward area in India and unfortunately no new line is proposed to be laid in the Budget. I suggest that Kotah-Chittorgarh line for which I had requested may be laid connecting Taloda, Bundi, Devli, Tonk, Nasriabad and Ajmer. Survey work may also be started simultaneously for the earlier the line is ready the better for the Railways because of the fact that stone from this region is sent to all parts of the country and Railways will earn a lot thereby.

Now speaking about Kotah region and Dehradun Express which runs through this region, there are only two third class compartments which are not sufficient to cope up with the number of passengers there therefore the train coming from Bina to Kotah should be extended upto Gangapur and another train should be run between Nagda & Mathura for the convenience of the public. The Dinning car attached to Dehradun Express should not be detached to Kotah but at Savai Madhopur.

Great injustice is being done to 44,000 Commercial Clerks in respect of their grades etc. The reservation list is handed over to Guards at Delhi only five minute before the train starts and therefore they are unable to guide the passengers to their seats in time. A Conductor Guard should be posted for this purpose. There should be token system for the luggage kept in the sleeper coach for which the Conductor is responsible. At the Kotah Railway Station, there are 20,000 Railway Employees but there is no school for there children. Even no proper Police Station is there. In the hospital there are Kamal & Co. have their monopoly there. Same is the condition at Ratlam, Kotah, Ajmer etc. This should be stopped. These days doctors in these hospitals do not issue Fitness Certificate unless one pays them Rs. 400/- or so. Corruption is rampant at Kotah and other stations, this should be stopped.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): The Railway Budget has been praised by many hon-members and the two Ministers are experienced and deserve praise for the Budget, but I have noticed that since 1962 every year the Minister changes, I think for better working the Ministers will not be changed so frequently.

Railways are 112 years old in our country and the total length of railway lines is 57,000 kms. There are about 6,000 railway stations. It is hoped that where there are no railway lines, there need will be looked into. In 1925-26 Budget for railways was separated from the General Budget for the sake of integrated arrangements. Still there is 607 km. narrow gauge line which are privately operated. I would request the Government to take over these lines also and convert them into Broad-gauge lines.

I have to invite the attention of the hon. Railway Minister to the stepmotherly treatment being meted out to S.E. becauseRailway whereas the Budget mentions opening of new lines in other regions,no provision exists for S.E. Railways during 1965-66. One train *via*. Assam Express has been provided for this region but unfortunately it does not stop at Devaria, which has a population

of 25 lakhs, has 15 sugar Mills and it is the winter headquarter of the District and therefore the proposed Assam Express should stop at Devaria. No new train has been provided on Allahabad-Gorakhpur branch line. The amount set apart for the hopspital and School for Employees of N.E. Railways is insufficient. The Railways Employees who go to Gorakhpur for work from Devaria Janpad have been issued passes only upto Chaura-Chauri, these passes should be extended upto Bhatni. Instructions may kindly be issued to the General Manager to this effect.

No grant is given to Subhash Higher Secondary School, Bhatni where 200 to 300 children receive education. I request that a grant of Rs. 10,000 should be granted for this School.

The people of Banaras (Varanasi) have demanded a direct train to start from there for Madras. There is neither an Express nor a Mail train starting from here for Calcutta, Delhi etc. There should be at least one train starting from Banaras.

Many accidents occur on N.E. and S.E. Railways and this is because of faulty tracks and employees, negligence. Though it is claimed that accidents are on a decline but the fact is that about 7,000 accident have been on record so far. I, therefore, request that more attention should be paid towards N.E. Railways to improve it.

We had asked for a double line between Lucknow and Siliguri but the hon. Minister has promised to give C.T.C. But it will result in collision from behind. To avoid this double line could be provided by spending a little more.

Speaking about my own constituency, the bridge at Bhagalpur should be converted into a rail-cum-road bridge to avoid hardship to passengers using the road. Many trains used to stop at various stations but now these stops have been abolished *e.g.* Kanpur Express used to stop at Bhatpur but now it does not stop there. This should be made a stop again. No train runs during day time for Allahabad on Allahabad-Gorakhpur Division. Kushinagar is a place of international importance but there is no means of reading there by rail. I want Burhej to be connected to Khadda via Rudrapur, Gauri Bazar and Kushinagar.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): The speech delivered by the Railway Minister while presenting the Railway Budget was on the whole satisfactory. But this satisfaction was not seen throughout. The hon. Minister stated that there is an increase in the speed and the number of railway trains. Generally the speed of railway train is much less as compared with other countries. This is also the general complaint that trains run late.

I would like to say something regarding the railway fare. It has been stated that it is being increased in order to meet the expenditure. But it will effect the general economy. According to the Railway Convention railways are giving 4 to 5 percent of dividend. But if it had been in private sector, it would have made much more. We must know that the increase of railway fare is not the only way of raising money, it can be raised by cutting down the expenditure. We must adopt economic measures. In these days of democracy and Socialism this disparity of facilities to the different categories of employees should also be eradicated. There are hundreds of saloons which

[Shri Sinhasan Singh]

could be done away with. It is not at all necessary for the high officers to travel in saloons. This also does not create an healthy effect even on other employees.

In the same way the age limit also has been raised. from 55, it has been raised to 58. I would request that no extension of Service beyond the age of 58 should be granted under any circumstances. I would also request that the threetier coaches have very inconveneitnt and should be converted into two-tier Coaches. I draw the attention of the Railway Minister to the fact that there should be railway line between Barharaganj and Bahraich. The Bridge at Barharganj should be concverted into rail-cum-road bridge. This area is very wide and there is no railway line here. This railway line will link Gorakhpur, Bahraich and Gonda together this will also facilitate going to Nepal.

श्री राजा राम (कृष्णागिरि) : मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जहां कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी रेलगाड़ी देखी ही नहीं। वहां यदि किसी को रेलगाड़ी देखने की इच्छा होती है तो उसे पचास मील की बस यात्रा करनी पड़ती है। बहुत से वक्ता रेलवे प्रणाली के विकाश की बातें करते हैं परन्तु मुझे तो यह निवेदन करना है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में नयी रेलवे लाइन बनायी जाय। इस मांग से पूर्व मैं रेलवे बजट के बारे में कुछ निवेदन करना चहता हूं ।

रेलवे मंत्री महोदय ने यात्री भाड़े के बा रे में कुछ वृद्धि की है। मेरा निवेदन यह है कि वस्तु भाड़े में वृद्धि से न केवल माल भेजने वालों को प्रत्युत अन्य लोगों की भी कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। बात यह है कि वस्तु भाड़े में वृद्धि वास्तव में आम मूल्यों में वृद्धि होती है। यदि अधिक धन की आवश्यकता सरकार को हो तो उसे अन्य उपायों की तलाश करनी चाहिये। तीसरे दर्जे के यात्रियों का भाड़ा बढ़ा कर यह कभी पूरी नहीं करनी चाहिये।

रेलवे के मामले में उत्तर और दक्षिण में भेद भाव किया गया है। यदि हम सारे देश की जनसंख्या और रेलवे के कुछ भाग की लम्बाई को देखे तो मालूम होगा कि केरल राज्य की बहुत उपेक्षा की गई है। गत 10 या 11 वर्षों में तीन करोड़ रुपये की राशि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए रखी गई। वैसे रेलवे समिति की सिफारिश यह थी कि इस कार्य के लिए तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष रखा जाना चाहिये। गत पांच वर्षों में हमने इस मद को छुआ तक नहीं परन्तु अब न्यूनतम को अधिकतम बना कर इस प्रयोजन के लिए केवल तीन करोड़ रुपये रख गये हैं। परन्तु वास्तव में इस दिशा में बहुत कम व्यय किया गया है। मामला बड़ा महत्वपूर्ण है अतः इसकी जांच की जानी चाहिये।

एक तीसरे दर्जे के यात्री को पेशाब करने के लिए उसे दो फर्लांग चलना पड़ता है परन्तु मंत्रालय को यह राशि व्यय करने में बड़ी कठिनाई पेश आ रही है। इस सदन के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर मंत्रालय समुचित ध्यान नहीं दे रहा। यदि योजनायें पूछी जायें तो ऐसी योजनाय प्रस्तुत की जाती हैं जिनपर एक सौ करोड़ रुपये का खर्च भी कम पड़ेगा। परन्तु फिर भी निर्धारित राशि खर्च नहीं की जाती दिखाई यह देता है कि मंत्रालय की सहानुभूति तीसरे दर्जे के यात्रियों के साथ नहीं है। यही कारण है कि इस मद में रखी गई राशि भी व्यय नहीं की जातीं।

हम दक्षिण में नयी लाइनों के निर्माण की बात कर रहे हैं। देखा यह गया है कि बड़ी लाइने अधिक लाभप्रद हैं। सलेम-बंगलौर लाइन बड़ी लाइन होनी चाहिये। मद्रास—विलिपुरम लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये। विद्युतकरण की गति में वृद्धि होनी चाहिये। धनुषकोड़ी गाड़ी दुघटना पूणत: प्राकृतिक प्रकार की दिखाई नहीं देती। अफसरों की लापरवाही भी इसकी जिम्मेवार है। 23 दिसम्बर, को आधी रात के बाद तूफान धनुषकोड़ी की भमि पर आया। थोड़ी सी दूरदर्शिता और आम बुद्धि प्रयोग से गाड़ी का यह फेरा रद्द किया जा सकता था। यह कहा जाता है कि गाड़ी का ड्राईवर गाड़ी चलाने में हिचकिचा रहा था। पूरे पम्बन पुल का बिनाश भी कपटपूर्ण है। इसका निर्माण 1914 में किया गया था इस बात के चिंताजनक समाचार हैं कि पुल की कई वर्षों से तकनीकी जांच नहीं की गई थी। कोई तकनीकी सर्वेक्षण भी नहीं किया गया। चार वर्ष हुए भूतपूर्व रेलवे मंत्री श्री से. वे. रामस्वामी ने इसे मजबूत करने की बात कही थी, परन्तु उसके बाद इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। यदि इसे ठीक कर लिया जाता तो हजारों जानें बच जाती।

Shri Pratap Singh (Sirmur): We are discussing the Rialway Budget for the last four days. If we want that Railway should do some work then the increase in fares is inevitable. No Scheme can be implemented without income. For the welfare of staff good work has been done by the railways. Last year 14704 staff quarters were constructed, and this year also the staff quarters are Constructed. The number is 17530. With this it is hoped that accommodation will be provided to all the employees. Arrangements for labour welfare and medical aid have also been made. The provision of double lines and faster trains for big cities have been done. The express goods trains are also very commendable.

I am of the opinion that the progress of the country is not possible without the development of under-developed areas. We can very clearly see that Himachal Pradesh, which is otherwise quite rich in mineral resources, has remained backward for want of transportation facilities. I would impress upon the Railway Ministry the urgent need of railway lines in Himachal Pradesh. Survey has been undertaken for a railway line from Jamuna Nagar upto Kisan Dam via Paonta. This line should be undertaken without any delay. This will cover the area of five thousand square miles and about fifteen lakhs of people will be benefitted by this. This is also very necessary that Giri Project should also be undertaken. Himachal Government has a scheme of setting up Cement, paper, pulp and timber industry at Paonta. Therefore it should be linked with the railway line. The construction of those lines will help in getting the good advantage of gypsum, in line-stone and many other minerals there. Whatever investment will be done this direction, will be recovered very soon.

I shall also state that the line from Kalka to Simla should be extended upto the border passing through Matyane and Narkonda, keeping in view the importance of the export of patatoes as also the defence consideration. A passenger train should be started from Simla to Kalka in the morning. Barotwala should also be linked with a railway line. Railway Ministry should see if the faster trains could be provided to run between Pathankot and Joginder Nagar. The trains which are running now take more than double the time by Motor vehicles.

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रूगढ़) : हमारे देश के सरकारी उपक्रमों में से रेलवे सब से बड़ा उपक्रम है । इसलिए हम इस बात की आशा करते हैं कि रेलवे लोक राजस्व में अधिक अंशदान देंगी ।

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि रेलवे ने केन्द्रीय राजस्व में लगभग 100 करोड़ रुपया दिया है । अब जब कि बैंक दर बढ़ गया है रेलवे के अंशदान में भी वृद्धि होनी चाहिए । इसके साथ ही यात्री भाड़ा कर के बदले में दिये जा रहे अंशदान में भी और वृद्धि होनी चाहिये । इसका राज्यों में वितरण जनसंख्या तथा राज्यों के यातायात तथा संचार में पिछड़े होने के आधार पर किया जाना चाहिये ।

पिछले तीन या चार वर्षों में रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया काम प्रशंसनीय है । इन कामों में 2,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बड़े बड़े नगरों के बीच रेलवे लाईन को दोहरा करना, उत्तर पूर्वी सीमा खंडों में नई लाईनों का निर्माण तथा मीटर गेज लाईनों का बड़ी लाईनों में परिवर्तन शामिल है । इन कारणों से रेलवे मंत्री का किराया तथा वस्तु भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव उचित है ।

मेरा सुझाव यह भी है कि रेलवे को, यथा सम्भव, हर मामले में आत्म-निर्भर होना चाहिये । बहुत सी वस्तुओं का निर्माण रेलवे स्वयं कर रही है । बहुत सी अन्य वस्तुओं का निर्माण भी रेलवे द्वारा किया जाना चाहिये । इस से भ्रष्टाचार कम से कम आधा दूर हो जायेगा ।

मुझे इस बात पर खेद है कि बड़ी लाईनों और मीटर लाईनों में कुछ असमानता है । बड़ी लाईनों और मीटर लाईनों की लम्बाई लगभग समान है । इसलिए उन पर किया जाने वाला व्यय लगभग समान होना चाहिये । मीटर गेज पर सुविधायें बड़ी लाइन जैसी नहीं हैं । स्टेशनों, स्नान-गृहों और डिब्बों के अलाटमेंट आदि के बारे में भी असमानता है । उत्तर-पूर्वी सीमा रेलवे में टैंक वैगनों की कमी है परन्तु बरौनी में इस प्रकार के डिब्बे बेकार पड़े हैं ।

इंजिनों, डिब्बों आदि के लिए अन्य रेलों की तुलना में उत्तर-पूर्वी सीमा खंड को बहुत कम राशि दी गई है । इसी प्रकार, कई अन्य मामलों में मीटर गेज रेलों की और विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी सीमा खंड की अवहेलना की गई है ।

बड़ी लाइन का विस्तार गोहाटी तक और डिब्रूगढ़ तक किया जाना चाहिये । नई दिल्ली से मद्रास जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रैस जैसी गाड़ी दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक चलाई जानी चाहिये । तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इसे गोहाटी तक और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डिब्रूगढ़ तक इस गाड़ी का विस्तार किया जाना चाहिये ।

डिब्रूगढ़ में एक छोटी सी कर्मशाला है जिस में डिब्बों आदि की मुरम्मत की जाती है । लगभग तीन चार वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के खतरे के कारण उस की सारी मशीनरी वहां से हटा ली गई थी । इस समय वहां केवल इंजनों की मुरम्मत होती है । इस कर्मशाला में पूरा काम होना चाहिये ।

असम के बड़े नगरों के बीच कोई द्रुत गति वाली गाड़ी चलाई जानी चाहिये : गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए कम से कम एक डीजल गाड़ी डिब्रूगढ़ और गोहाटी के बीच तथा शीलांग तक चलाई जानी चाहिये ।

असम के महत्वपूर्ण नगरों में ऊपरी पुल बनाये जाने चाहियें । मैं विभागीय भोजन व्यवस्था का समर्थन करता हूं । असम मेल के साथ एक डाईनिंग कार लगाई जानी चाहिये ।

Shri Naval Prahakar (Delhi-Karol Bagh) : Mr. Sir, Railway system in Delhi continues to be the same as it was at a time when the population of Delhi was two and a half lakhs. There has been little addition or alteration in the railways stations which existed then in Delhi.

The Municipal Corporation of Delhi has been endeavouring to cope will the traffic and communications problem which has arisen as a consequence of the continued increase in population since 1947, but I feel this problem cannot be solved by the corporation alone. The length of railway lines and the number of local trains has been constantly increasing in Bombay along with the increase in population.

There has been a constant demand to solve this problem. The corporation of Delhi passed a resolution to that effect while Shri Sham Lal was the mayor of Delhi. I have also been pleading for the solution of the problem of transport and communications for Delhi for the last thirteen years. It has been said very often that a ring railway will be provided for Delhi. Even the rail from New Delhi to Vinay Nagar has been started but the whole thing has been set at rest thereafter.

This matter was again raised in the Advisory Committee for Delhi. The late Pandit Pant was the chairman of that committee. He helped in solving the problem of the land of the cantonment through which the railway line had to pass. But in the last two or three budgets avoiding line is being mentioned instead of ring railway. I do not know how this change has been effected. While S. Swaran Singh was the Minister of Railways has assured that attention will be given towards the construction of ring railway.

Recently, the Municipal Corporation passed a resolution in which it was stated that even the ring railway will not solve the purpose. Instead of it underground railway is needed for Delhi.

There is no approach road or exit gate at the new Railway station of Patel Nagar. Passengers leave the railway station by walking along the railway lines, many of whom may be ticketless. It has been learnt that land has been acquired near the railway station. The construction of a good and modern station should be completed as soon as possible.

The matter of providing an overbridge at the Patel Road Crossing is still pending. It seems that it will not be taken up during the Third Five Year Plan The hon. Minister should look into the matter.

The platforms at Sarai Rohilla station are very small. Many trains stop there. There is no shed over the platform. That platform should be extended and sheds should be provided.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(*Mr. Speaker in the Chair*)

[Shri Naval Prabhakar]

The quality of food served in the Railways is very poor. Attention should be given to this matter and arrangements should be made for providing better quality of food.

परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव–जारी

MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : आज प्रातः जो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उस पर 15 तारीख, सोमवार को चर्चा होगी और इस पर पूरे दिन का समय लगेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : आपकी घोषणा का स्वागत है परन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए तीन दिन से कम का समय न दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि सभा को अपना सारा काम एक पूर्वनिश्चित समय तक पूरा करना है और हम इस समय वित्तीय मामलों पर विचार कर रहे हैं इसलिये एक ही दिन काफी है । हां हम देर तक बैठ कर इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री ० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-मध्य) : कितने ही सदस्यों ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । वह सभी इस पर बोलेंगे इसलिये जैसा श्री कामत ने कहा तीन दिन नहीं तो दो दिन तो अवश्य ही निश्चित होने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी के अनुसार यदि दो दिन दिये जाएं तो 8 घंटे का समय बनता है और मैं भी यही कह रहा हूं कि उस दिन देर तक बैठ कर हम उतना ही समय इस पर लगा सकते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आधी रात तक बैठ कर हम गंभीरतापूर्वक चर्चा नहीं कर सकते ।

Shri Sheo Narain (Bansi) : No member would like to sit beyond five, therefore I would request that the House should not sit beyond five on that day.

Mr. Speaker : Then I would have to allot two days. I will, anyhow ngly.

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा सुझाव है कि यद्यपि आप के निर्णयानुसार सभा शनिवार के दिन सभा की बैठक नहीं होगी परन्तु फिर भी कार्य समाप्त करने के लिए सभा 2 शनिवार बैठ कर अपना कार्य करे—(**अन्तरबाधायें**) ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

हरि विष्णु कामत : अन्यथा मैं अनुरोध करूंगा कि सभा चर्चा पूरी करने लिये आधी रात तक भी चाहे बैठे ।

रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा—जारी

BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

रेलवे मंत्री (श्री स० का०पाटिल) : किसी सीमा तक रेलवे आय-व्ययक का स्वागत किया गया है और कई सुझाव व्यक्तिगत क्षेत्रों में सुविधाएं, नई रेलवे लाइनें आदि बिछाने के बारे में मिले हैं। मेरा मंत्रालय उन पर पूरा ध्यान देगा ।

एक आरोप बार बार दोहराया गया है कि जबकि सामान्य बजट में कई राहतें दी गई हैं रेलवे आय-व्ययक में इनका अभाव है। मेरी उनसे कोई प्रतियोगिता नहीं है। जब कर बढ़ाए जाते हैं तब रेलवे तो ऐसा नहीं करती। परन्तु इस बार यदि भाड़े बढ़ाए गए हैं तोउसका भी एक कारण है जिस पर मैं अब प्रकाश डाल रहा हूं। यदि हम समय समय पर ऐसा न करें तो हमारा राजस्व घटता जाएगा जिस से विदेशों में हमारी साख जाती रहेगी। इसलिये हमें अपनी साख, ऋण अदा करने की क्षमता तथा स्थिरता बनाए रखने के लिये भाड़े आदि बढ़ाने पड़ते हैं।

कई सदस्यों का सुझाव है कि भाड़े बढ़ाने से पहले सुविधाएं दी जानी चाहिये। परन्तु मेरा कहना यह है कि बिना धन अधिक सुविधाएं भी कहां से जुटाई जाएं।

हमने राजस्व में काफी वृद्धि की है और वित्त मंत्री जी ने भी इसके लिये हमारा धन्यवाद किया है और इसी कारण 30–40 करोड़ रुपये की राहत सम्भव हो सकी है। इसलिये यदि वित्त मंत्री 29 करोड़ रुपये की राहत अप्रत्यक्ष रूप में दे सकें हैं तो अवश्य ही रेलवे ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह 30–40 करोड़ रुपये हमने कोई उपहार रूप में नहीं दिये हैं परन्तु बात यह है कि सरकार रेलवे के लिये साहूकार का कार्य करती है। रेलवे सरकार के पास कई प्रकार की निधियां जमा करती है जैसे तोड़-फोड़ निधि, रक्षित निधि, विकास निधि आदि। इसके विपरीत यदि हम संचित निधि से अधिक धन निकाल लें तो सरकार की संसाधन स्थिति पर दबाब बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त हम रेलवे की पूंजी आवश्यकताओं के लिये सामान्य राजस्व का आश्रय लेते हैं।

1964–65 के पूंजी कार्यक्रम में हम 15 करोड़ रुपये कम ले रहे हैं। अगले वर्ष हम इससे भी कम धन लेंगे। इसी कारण अप्रत्यक्ष करों में राहत दी जा सकी है।

सभा को पूंजी व्यय में कटौती के कारण यह भय नहीं होना चाहिये कि इससे प्रगति में धीमापन आ जाएगा। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। परन्तु यह इसलिये सम्भव है कि कुछ कार्य जो इस समय हाथ में नहीं लिये गए और जो कुछ अन्य होने वाले कार्यों पर निर्भर हैं तुरन्त हाथ में नहीं लिये जा सकते इससे बचत हो सकी है और यही कारण है कि रेलवे को कोई हानि हुए बिना सामान्य राजस्व को राहत मिल सकी है।

अतिरिक्त सीमा तथा उत्पादन शुल्कों के लग जाने से रेलवे को 6 से 7 करोड़ रुपये तक देना होगा क्योंकि हमें कई उपकरण जैसे इन्जनों, डिब्बों आदि के कुछ भाग, संकेत तथा बिजली के उपकरण, तांबा आदि विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। देश में निर्मित वस्तुएं जैसे इस्पात तथा लाइनों का सामान जैसे प्लेटें, शीट्स, पटरियां, पहिये आदि पर भी 1 करोड़ 13 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। डीजल तेल पर भी हमें 25 लाख रुपये खर्च करने होंगे जिससे अगले वर्ष कुलमिला कर अतिरिक्त खर्च 798 लाख अर्थात 8 करोड़ रुपये होगा।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि दास आयोग के निर्णय के अनुसार जो 29 करोड़ रुपया था यदि उसमें यह 8 करोड़ रुपया और जोड़ दिया जाये तो बाकी रकम केवल 5 करोड़ रुपया रह जावेगी। यही मेरी आपत्ति है।

जहां तक रेलों के सामान्य रूप का सम्बन्ध है मैं यह कहूंगा कि इस समय 57,000 किलोमीटर से कुछ ही कम हमारे पास रेल की पटरी है जोकि ब्राडगेज, मीटर गेज तथा नेरो गेज की है। वैसे तो ब्राड गेज और मीटर गेज की पटरियों की लम्बाई में अधिक अन्तर नहीं है किन्तु जहां तक इनके बोझ ले जाने का सम्बन्ध है उसमें बड़ा अन्तर है। ब्राड गेज सारे यातायात का लगभग 93 प्रतिशत

[श्री स० का० पाटिल]

भाग ले जाता है और मीटर गेज केवल 16 प्रतिशत ले जाता है । नेरो गेज का भाग तो आधे प्रतिशत से भी कम है । इससे आपको इन लाइनों के यातायात का पता चल जावेगा ।

खर्च के बारे में कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह बढ़ता ही जा रहा है और इस समय यह 2700 करोड़ रुपया है । आगे इसके 3000 करोड़ रुपया तक पहुंचने की सम्भावना है । कुछ सदस्यों ने कहा कि हम सरकार को इस में से बहुत भाग दे रहे हैं । मैं यह बता दूं कि हम सरकार को कोई दान नहीं दे रहे हैं । यह तो लाभांश है और यह वह है जिसे इस सदन से पास किया है । यदि हम गैर सरकारी क्षेत्र से रुपया लेते तो हमें उसका ब्याज देना पड़ता और यह वही है जो हम दे रहे हैं ।

इसलिये यू कहिये कि हम तो अपना ऋणभार दे रहे हैं और इससे हमारी साख ठीक रहती है । जब मैं कुछ ऋण लेने गया तो मुझे सब ने यही कहा कि इसमें चिन्ता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबको पता है कि हम अपना ऋण लौटाने में बहुत समर्थ हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने कहा है कि खाता पूंजी इस समय 1950–51 के मुकाबले तीन गुना बढ़ गई है और आय में कमी होनी शुरू हो गई है । मैंने अपने भाषण में पहले ही कह दिया था कि इस वर्ष अन्न के यातायात पर कुछ राज्यों और जिलों में पाबन्दी लगने के कारण रेलों द्वारा अन्न कम ले जाया गया और इससे हमारी आय पर भी प्रभाव पड़ा । परन्तु ऐसा हमेशा तो होने से रहा और अगले वर्ष हम एक करोड़ टन अधिक सामान ले जाने की आशा है जिससे हमारी आय भी बढ़ेगी ।

इस्पात उत्पादन की संस्थापित क्षमता भी बढ़ती जा रही है और यह रेलों के लिये आवश्यक है और रेलवे उनके लिये आवश्यक हैं । इनमें यदि कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई तो यह सदा नहीं रहेगी ।

एक सदस्य ने तो यह भी कहा है कि किराये आदि बढ़ाने की बजाय अवमूल्यन निधि को कम कर दिया जाये । शायद वह समझते हैं कि यह रुपया हम यूंही फूंक रहे हैं । वैसे इसमें से पिछले 14 वर्षों में $75\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया हम इसमें से निकाल चुके हैं । परन्तु यह कोई अच्छा बजट बनाने का उचित तरीका नहीं है ।

कुछ सदस्यों ने तो यह भी सुझाव दिया है कि इसमें से मैं 5 करोड़ रुपया वह कम कर दूं जो रेलवे का सामान चोरी हो जाता है और 5 करोड़ रुपया वह कम कर दूं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं । इससे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मेरे पास कोई जादू का डंडा हो और मैं यह काम एकदम बन्द कर सकूं या वे व्यक्ति मेरे ऊपर तरस खा कर रेल में बिना टिक्ट यात्रा करना बन्द कर दें । इसलिये किराया बढ़ाने से मुझे कोई आनन्द नहीं मिलता । यदि अगले वर्ष स्थिति ठीक हो गई तो मैं किराये कम भी कर सकता हूं ।

जहां तक हमारी रेलों का मुकाबला दूसरे देशों से करने का है मैं कहूंगा कि हमें उन देशों से कुछ बातें सीखनी हैं । परन्तु यदि कोई कहे कि हमारी रेलों पर उनसे अधिक व्यय हो रहा है तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं ।

यात्रियों को अधिक सुविधायें देने की बात भी कही गई है । जिस दिन से मैंने रेलवे मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला है उसी दिन से मैं इस विचार में हूं कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें । ऐसा करना मेरा प्रयत्न भी होगा ।

यह भी कहा गया है कि जो 3 करोड़ रुपया सुविधाओं पर खर्च करने को निर्धारित किया था वह नहीं किया गया । सरकार पर आप जो चाहें आरोप लगायें परन्तु व्यय करने में कसर छोड़ने का आरोप नहीं लगा सकते । इसलिये यदि किसी वर्ष कोई रुपया जो सुविधाओं के लिये छोड़ा था वह व्यय नहीं किया गया तो वह समाप्त नहीं हो गया परन्तु अगले वर्ष के लिये हमारे पास जमा हो गया ।

भीड़ कम करने का भी प्रश्न है । मैं तो समझता हूं कि यात्रियों को सुविधा देने का यह भी एक बड़ा कार्य है । हमने तो वास्तव में यात्रियों से अधिक रेल के डिब्बे पिछले वर्षों में बढ़ा दिये हैं । क्योंकि 1963–64 में रेल के डिब्बों में 1951–52 के मुकाबले 42 प्रतिशत बढ़े और यात्री उसी अवधि में 32 प्रतिशत बढ़े ।

डीज़ल और बिजली से चलने वाली गाड़ियों का भी उल्लेख किया गया है । मैं भी सहमत हूं इस बात से और समझता हूं कि इससे भीड़ कम होने में सहायता मिलेगी । इस वर्ष पहली अप्रैल से कोई 15 से 30 प्रतिशत गाड़ियों में हम ऐसा करना प्रारम्भ कर देंगे ।

रेल और सड़क द्वारा यातायात में संघर्ष की बात कही गई है । मैं परिवहन मंत्री भी रह चुका हूं और अब रेलवे मंत्री हूं । इसलिये मुझे रेलवे तथा सड़क दोनों में संघर्ष का पता है । मैं आप को बता दूं कि ऐसा कोई संघर्ष नहीं है बल्कि आपस में बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं ।

टिकटों में चोर बाजारी की बात भी यहां कही है और मैं मानता हूं कि ऐसा है । इसकी रोक थाम के लिये भारतीय रेलवे अधिनियम में मई 1964 जो संशोधन किया गया था वह इसीलिये था । मई से दिसम्बर 1964 तक 110 इस प्रकार के मामले पकड़े गये और उन पर उचित कार्यवाही की गई । हमारा प्रयत्न यह होगा कि इसे समाप्त किया जावे ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि सोने की सीटें छोटी हैं और उनकी लम्बाई बढ़ाई जावे । पहले वे छोटी थी परन्तु अब उनकी लम्बाई बढ़ाकर 6 फुट 3 इंच कर दी गई है ।

महिलाओं के लिये तीसरे दर्जे के डिब्बों में अलग स्थान सुरक्षित करने की मांग भी की गई है और मैं उनसे सहमत हूं । रेलों को यह निर्देश दिया गया है कि तीसरे दर्जे के डिब्बों में एक अलग स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित रखा जावे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

महिलाओं के डिब्बे गाड़ियों के बीच में रखे जाने की बात भी कही गई है और मैं यह बता दूं कि सिवाय एक दो को छोड़कर के बाकी गाड़ियों में यह पहले से ही बीच में हैं । दूसरी गाड़ियों में भी यह प्रयत्न किया जावेगा कि महिलाओं के डिब्बे बीच में ही हों ।

कहा गया है कि विद्यार्थियों को रियायती टिकट लेने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । अब आसान तरीका इस काम के लिये कर दिया है और वे अपने स्कूल से प्रमाणपत्र प्राप्त कर के ऐसे टिकट स्टेशन मास्टरों से भी प्राप्त कर सकते हैं ।

[श्री स० का० पाटिल]

कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि रेलों को अधिक स्टेशनों पर रुकना चाहिये। दूसरी ओर कहा जाता है कि गाड़ियां तेज़ नहीं चलती हैं। छोटे-छोटे स्थानों पर गाड़ियां रुकने से बहुत व्यय होता है और मैं समझता हूं कि यह मांग भी उचित नहीं है ।

श्री सोलंकी ने यह आरोप लगाया है कि 24 दिसम्बर, को इस्पात मंत्री के देर से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने के कारण रेल गाड़ी को एक घंटा देर से चलाया गया। यह आरोप निराधार है । वास्तव में एक गाड़ी में एक टूटा हुआ डिब्बा गलती से लग जाने के कारण गाड़ी को तब चलाया गया जब वह डिब्बा हटा दिया गया और इस कारण देर हो गई ।

रेलवे दुर्घटना समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया और मैं सदन को यह बता दूं कि इस रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशें मान ली गई हैं।

समिति की सिफारिशों में से एक का सम्बन्ध सुरक्षा शिविरों से है और इसका लाभ रेलवे ड्राईवर, स्टेशन मास्टर आदि उठा रहे हैं। वैसे मैं यह बता दूं कि रेलवे सुरक्षितता आयुक्त रेलवे मंत्रालय से बिल्कुल स्वतंत्र है और वह इनका नौकर नहीं है । दुर्घटना समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी ।

सतर्कता के बारे में यह बता है कि गृह-मंत्रालय ने अथवा अपना अलग सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर दिया है । वैसे सन्थानम समिति भी इस बात से सहमत थी कि प्रत्येक मंत्रालय अपना अलग सतर्कता विभाग रखे। हमने भी अपना एक सदस्य इस काम के लिये नियुक्त कर दिया है और वह किसी भी तरह से रेलवे बोर्ड से आदेश नहीं लेता है । वह किसी भी व्यक्ति के बारे में जांच कर सकते हैं। और तो और रेलवे बोर्ड भी सतर्कता आयुक्त को अपने कार्य करने से नहीं रोक सकता । माननीय सदस्य को पता होगा कि अभी अमृतसर में एक बड़ी भारी चोरी पकड़ी गई है । इसी प्रकार और भी ऐसी बातों का पता लग जावेगा और हमारा यह प्रयत्न होगा कि ऐसी घटनाओं में कमी हो जाये ।

कोयला, अन्न आदि ले जाने का कार्य विशेष ऋतुओं पर आधारित है । रेलवे ने अपनी इस दिशा में क्षमता बढ़ा ली थी है और वह जन से नवम्बर तक 4200 वेगन प्रति दिन तथा नवम्बर से मई तक 4000 वेगन प्रतिदिन है । परन्तु जब लोग इन वस्तुओं का भंडार अपने पास करना आरम्भ करते हैं तो हमारे पास इनका बोझ भी कम आता है । परन्तु हमें आशा है कि सदा लोग ऐसा नहीं करेंगे और रेलवे को ले जाने के लिये सामान मिलता रहेगा और रेलवे की आय बढ़ती रहेगी ।

आधुनिक रेलवे के निर्माण से ही आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है । क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा अथवा छोटा उद्योग नहीं है जिसका रेलवे से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इसलिये रेलों को डीजल और बिजली से चलाने की योजना में काफी प्रगति हो रही है ।

कुछ सदस्यों ने डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों की देश में निर्माण की मांग की है और सरकार की भी यही नीति है । हम उनका आयात तब तक करेंगे जब तक हमारा अपना उत्पादन पर्याप्त नहीं हो जाता । अभी हम 18 इंजन प्रति वर्ष बना रहे हैं। और तीन वर्ष के भीतर हमारा 150 इंजन प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य है । बिजली से चलने वाले इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाये जाते हैं। अभी प्रति मास दो से तीन इंजन बनाये जाते हैं। परन्तु 1966 तक प्रति मास 6 इंजन बन जाया करेंगे । स्वयं चालित सिगनल पद्धति से भी रेलवे को कार्य क्षमता में बहुत सुधार हुआ है ।

अब पटरी को दोहरा बनाने की आवश्यकता नहीं है । एन० एफ० रेलवे में इस पद्धति को हम सब से पहले लागू कर रहे हैं क्योंकि वहां पटरी को दोहरा नहीं किया जा सकता । आधुनिकीकरण के कुछ कदमों में एक यह भी कदम है । यदि माननीय सदस्य दस वर्ष धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें तो वह देखेंगे कि इन दस वर्षों में काफी प्रगति होगी ।

श्री भागवत झा आजाद ने शिकायत की है कि महा-प्रबन्धकों को लिखे गये पत्रों का उत्तर शीघ्र नहीं मिलता और यदि मिलता भी है तो उस पर उन के अपने हस्ताक्षर नहीं होते । इसके लिये मैं क्षमा याचना करता हूं क्योंकि संसद् सदस्य देश के प्रतिनिधि हैं और महा-प्रबन्धक को स्वयं उत्तर देना चाहिये। इसलिये मैंने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि महा-प्रबन्धक ऐसे पत्र-व्यवहार को स्वयं देखा करें । मेरे पास हजारों पत्र आते हैं परन्तु जब भी किसी संसद्-सदस्य का पत्र आता है तो मेरा ध्यान तुरन्त उसकी ओर आकर्षित हो जाता है । इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम संसद्-सदस्य की सद्भावना का कितना आदर करते हैं।

एक संसद्-सदस्य ने यह भी कहा कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में दोहरी और अधिक पथ वाली लाइनें बहुत कम हैं। परन्तु मैं उनको यह बता दूं कि अब विचारधारा दोहरी पटरी के विरुद्ध है । दोहरी पटरी के लिये अधिक भूमि की आवश्रयकता पड़ती है और अधिक धन भी व्यय होता है, इसलिये अच्छा यही है कि संकेतन पद्धति में सुधार किया जाये। परन्तु जहां यातायात बहुत अधिक है वहां पटरी को दोहरा बनाया जायेगा । रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के लिये हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं और क्योंकि पटरी को दोहरा बनाने पर बहुत अधिक व्यय होता है इसलिये पटरी को उन्हीं भागों पर दोहरा किया जायेगा जहां गाड़ियां इतनी अधिक चलती हैं कि उनका एक पटरी पर चलना सम्भव नहीं है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने अपने भाषण में कहा है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर-लाइसेंस प्राप्त कुली भरती किये गये थे और प्रत्येक से 700 से 800 रुपये तक घूस लिया गया था । उनको इस सम्बन्ध में सब कुछ मालूम होगा तभी उन्होंने इसका यहां उल्लेख किया है । परन्तु ऐसे अपराधों का संख्या इतनी अधिक है कि इनको पकड़ना सम्भव नहीं है । हम सतर्कता को अधिक बढ़ा रहे हैं जिस से इन लोगों की कार्यवाहियों को रोका जा सके।

[श्री स० क० पाटिल]

श्री रामानन्द शास्त्री ने श्री रिछपाल, शंटर को क्वार्टर देने के मामले का निर्देशन किया है । उन्होंने इसका इतना भावनापूर्ण तरीके से वर्णन किया है कि मैंने समझा जरूर कोई गलत बात हुई है । मैंने उसकी जांच तुरन्त की और मामले के तथ्य अब मेरे पास हैं ।

अत: मैंने झट से इसके बारे में पूछताछ की और अब इस मामले के तथ्य मेरे पास हैं । इस मामले के तथ्य, जो वह कहते हैं, उन से भिन्न हैं । जब श्री रिछपाल द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज़ को दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षक को दिखाया गया तो उन्होंने इसे जाली बतलाया । उसने न केवल एक कठिनाई उत्पन्न की परन्तु रेलवे प्रशासन को भी बदनाम किया और इस सभा के एक सदस्य से धोखा भी किया । इसलिये रेलवे प्रशासन उसको नौकरी से निकालने की कार्यवाही कर रहा है ।

कई सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि यात्री गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब गाड़ियां 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे लेट होती हैं तो लोगों को गुस्सा आ ही जाता है । हमने वह भी समय देखा है जब गत दिवस चलने वाली गाड़ियां दूसरे दिन चला करती थीं । परन्तु अब ऐसी बात नहीं है । अब इस बारे में काफी सुधार हुआ है । देश भर में प्रत्येक दिन चलने वाली हज़ारों यात्री गाड़ियों के कुल मिलाकर, समयपालन के आंकने का एक ही तरीका है और वह यह है कि गाड़ियों के समय पर अपने ठिकाने पर पहुंचने की प्रतिशतता के आंकड़ों से, जिनको हम तैयार करते हैं, पता लगाया जाये । 1964 में यह प्रतिशतता 85.8 थी जिसमें गत वर्ष की तुलना में कुछ सुधार हुआ है। लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिये उन पर जो इंजीनियरिंग कार्य होता रहता है उससे समयपालन में कठिनाई होती है । यह सच है कि यह कोई मान्य स्पष्टीकरण नहीं है और माननीय सदस्यों को यह कहने का पूरा अधिकार है कि गाड़ियों के समयपालन में सुधार किया जाये यदि महत्वपूर्ण गाड़ियां, जो बड़ी लाइनों पर चलती हैं, समय पर चलने लग जायें तो समयपालन की आदर्श स्थिति हो जायेगी । हम इस सफलता को पाने के लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं । ऐसा करने के लिये सब से पहले हमें गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा । जापान, टोकियो और ओसाका के बीच चलने वाली गाड़ी की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे इस रफ्तार को 250 किलोमीटर प्रतिघंटा तक बढ़ाना चाहते हैं जब कि भारतीय रेलगाड़ियों की बड़ी लाइनों पर अधिकतम रफ्तार 60 मील प्रति घंटा है और छोटी लाइन पर 45 मील प्रति घंटा है । हम पहली अप्रैल से सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों के चलन-समय में कमी कर रहे हैं क्योंकि लगभग सभी यात्री गाड़ियां अभी भाप इंजनों से चलाई जा रही हैं और इनसे रफ्तार अधिकतम-अनुमत चाल से कुछ कम ही रहती है । धीरे-धीरे भाप इंजनों के स्थान पर डीज़ल इंजन और विद्युत इंजनों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है परन्तु ऐसे इंजन अभी एक अथवा दो प्रतिशत ही होंगे क्योंकि अभी हमारे पास कई हज़ार भाप इंजन हैं । इसके अतिरिक्त गाड़ियों की रफ्तार तभी बढ़ाई जा सकती है जब रेलपथ सुदृढ़ हों । इसलिये हमें यह सब कार्य करने हैं ।

कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सभी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल देना चाहिये । इस बारे में हमारा भी अन्तिम उद्देश्य यही है । परन्तु यह एक दिन में नहीं किया जा सकता । संयुक्त राज्य अमरीका को भी ऐसा करने में 40 से 50 वर्ष लगे हैं । छोटी लाइन में अब वृद्धि नहीं होनी चाहिये । जहां तक मीटर लाइन का सम्बन्ध है यह लगभग 25,000 किलोमीटर

है । जैसे जैसे यातायात बढ़ता जायेगा इसको बड़ी लाइन में बदलते जायेंगे । यह अब हो भी रहा है । ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सामान्य नीति निर्धारित की जाये कि शेष छोटी लाइनों को बन्द कर दिया जाये । इनको बदलने के लिये काफी पूंजी चाहिये और दूसरे यह भी देखना है कि उनकी परिचालन आवश्यकता भी है कि नहीं । जहां तक पर्वतीय लाइनों का सम्बन्ध है उनको बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वहां पर स्थान ही नहीं है ।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : उनमें सुधार लाने के बारे में क्या विचार है ?

श्री स० का० पाटिल : जिस चीज़ को हम मिटाना चाहते हैं उस में कहां तक सुधार करते चले जायें । अलबत्ता पर्वतीय सेक्शनों में सुधार लाना ही पड़ेगा ।

लगभग सभी सदस्यों ने नई लाइनों को बनाने के सुझाव दिये हैं । हमें रेल संचार का विस्तार करना है और आगामी 50 वर्षों तक हमें इन सुविधाओं में वृद्धि करते रहना है जब तक हम इष्टतम स्तर तक नहीं पहुंच जाते । चौथी योजना में नई लाइनों के लिये 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । जिसमें से पुरानी परियोजना को पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि को छोड़ कर लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपये नई परियोजना पर खर्च किये जा सकेंगे । इससे 500 मील लम्बी लाइन बन सकेगी । आसाम में रेल संचार का विस्तार करना वित्तीय दृष्टि से आपत्तिजनक है क्योंकि वहां लाइनें लाभप्रद नहीं हैं । परन्तु प्रतिरक्षा की दृष्टि से हमें यह सुविधाएं देनी पड़ेंगी और तभी वहां पर यातायात बढ़ेगा । हम आसाम को इस बारे में उच्चतर प्राथमिकता देने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री लिमये ने भाप इंजनों में प्रयोग होने वाले कोयले के बारे में आपत्ति करते हुए सुझाव दिया कि हमें अब विद्युत और डीज़ल इंजनों से गाड़ियां चलानी चाहियें । वास्तव में हमें कोयले की आवश्यकता नहीं है हम तो इसका प्रयोग केवल इसलिये कर रहे हैं क्योंकि यह फालतू है, हालांकि हमें इसके लिये कुछ अधिक पैसे देने पड़ते हैं । हम बहुत जल्दी विद्युत और डीज़ल इंजनों के प्रयोग को बढ़ा रहे हैं और तत्पश्चात् उनका यह प्रश्न भी नहीं उठेगा ।

जहां तक उपरिगामी पुलों (ओवर ब्रिजेज़) का सम्बन्ध है, हम इनके बनाने के लिये तैयार रहते हैं, जब भी राज्य सरकारें ऐसा करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत करते हैं और व अथवा सड़क प्राधिकारी पहुंच-मार्गों के लिये निर्माण व्यय देने के लिये तैयार होते हैं । गोदावरी पर रेल एवं सड़क पुल के बारे में कठिनाई यह है कि इसके लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार जितना खर्चा करना चाहती है, लागत उस से भी एक करोड़ अधिक है । मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हो सकेगा हम उनकी इस कठिनाई को दूर करने के अर्थोपाय करेंगे ।

जहां तक रेलवे फाटकों पर कर्मचारी रखने का प्रश्न है, यहां पर 30,000 फाटक हैं। इन में से 8,000 फाटकों पर कर्मचारी रखे गये हैं । कुछ अन्य फाटकों पर भी रखे जा रहे हैं। लेकिन सभी फाटकों पर कर्मचारी नहीं रखे जा सकते और न ही ऐसा कहीं और है । संयुक्त राज्य अमरीका में तो नगरों में भी फाटकों पर कर्मचारी नहीं होते और जनता संकेतों द्वारा अपनी सुरक्षा स्वयं करती है ।

बिजली के सामान की चोरी के बारे में एक मामला अमृतसर में पकड़ा गया है वह न्यायाधीन है । हमने उस मामले को विशेष पुलिस स्थापना को सौंप दिया है और बहुत जल्दी परिणामों का पता चल जाएगा ।

[श्री स० का० पाटिल]

मैं रेलवे कर्मचारी संघों को बधाई देता हूं कि वे सहयोग कर रहे हैं। कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हों हम उन सब को मिल कर हल कर लेते हैं। जहां तक मजूरी बोर्ड की स्थापना का प्रश्न है मैं उनको मंत्रणा दूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने अपने कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधायें जैसे परिवार सम्बन्धी उदार पेंशन, उनके बच्चों के माध्यमिक स्कूल तक के शुल्क की प्रतिपूर्ति, अवकाश के अधिक उदार नियम आदि दे रखी हैं जो और कहीं भी नहीं हैं।

हम उनकी और भी सहायता करना चाहते हैं। रेलवे एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है और इसकी सारी आय समस्त जनता पर खर्च की जाती है। अतः उनको मजूरी बोर्ड की मांग नहीं करनी चाहिये ।

कुछ सदस्यों ने विज्ञान कर्मचारियों की 58 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवावधि में विस्तार के बारे में शिकायतें की हैं। सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष कर दी गई है। परन्तु मंत्रि-मण्डल अथवा सरकार द्वारा किये गये किसी अन्य निर्णय के अनुसार एक विज्ञान कर्मचारी की, जिसको सेवा के लिये बहुत ही आवश्यक समझा जाये, सेवावधि में विस्तार 60 वर्ष की आयु तक किया जा सकता है। अतः यह निर्णय केवल उन पर लागू होता है जो विशेष रूप से योग्य और तकनीकी कर्मचारी हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। एक सौ अथवा एक हज़ार में से एक कर्मचारी होता है जिसको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। भविष्य में हम ऐसा केवल तभी करेंगे जब हम देखेंगे कि ऐसा करना युक्तियुक्त है।

जहां तक कुछ सदस्यों के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि सभी सहायक शल्य-चिकित्सकों को राजपत्रित पद दिये जाने चाहिये इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इन में से 790 सहायक शल्य-चिकित्सकों को राजपत्रित पद दिये गये हैं। सहायक चिकित्सा अधिकारियों के नियमित राजपत्रित पदाली में 300 अधिक पद निकाल कर उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की गई है। उनको वेतन के 20 प्रतिशत की दर से सीमित प्रैक्टिस भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों के भत्ते से 5 प्रतिशत कम है। यह अन्तर इसलिये है कि जहां रेलवे चिकित्सकों को सीमित प्रैक्टिस करने की आज्ञा है, वहां केन्द्रीय चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। रेलवे कर्मचारियों की कोई भी ऐसी श्रेणी नहीं है जिन की स्थिति और भविष्य में पदोन्नति के अवसरों में इतना सुधार किया गया है जितना कि सहायक शल्य-चिकित्सकों की स्थिति में सुधार किया गया। फिर भी यदि वे कोई मामला मेरे सामने रखेंगे जिससे उन की स्थिति में कोई सुधार हो सकता होगा, तो मैं उसकी अवश्य जांच करूंगा।

अनुसूचित जातियों के भर्ती के बारे में कहा गया है कि नीति में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं हुई। जिससे कहा जाये कि नीति में परिवर्तन किया गया है। उन के लिये कोटा निर्धारित किया हुआ है और उस के अनुसार उनकी भर्ती की जा रही है। यदि कोई सदस्य यह अनुभव करता है कि इस में कुछ और करना चाहिये तो मैं अवश्य उस की ओर ध्यान दूंगा।

विधानचन्द्र स्टेशन के निर्माण पर 7.94 लाख रुपये खर्च किये गये थे। इस को गिराने से जो सामान मिला, उस को बेचने से 3.30 लाख रुपये प्राप्त हुए और इस प्रकार कुल खर्च 4.60 लाख हुआ था। इस स्टेशन को रखने की आवश्यकता इसलिये

नहीं समझी गई क्योंकि एक मील से भी कम दूरी पर दुर्गापुर स्टेशन है । इस को केवल कांग्रेस अधिवेशन के लिये ही बनाया गया था और अधिवेशन की समाप्ति पर इसे गिरा दिया गया ।

चिकित्सा कालेज खोलने के सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिया था कि यदि सम्भव हो तो हम अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिये कुछ कालेज खोलें क्योंकि उनको अन्य कालेजों में दाखिला मिलने में कठिनाई होती है । इस से हम किसी अन्य मंत्रालय से मुकाबला नहीं कर रहे क्योंकि रेलवे कर्मचारियों के लिये हम ने पहले भी कई संस्थायें, कालेज और स्कूल खोल रखे हैं। यह अभी केवल सुझाव ही है । इस पर अभी अग्रेतर जांच की जायेगी कि हम आदर्श संस्थायें कैसे स्थापित कर सकते हैं ।

कई माननीय सदस्यों ने उचित मूल्य वाली दुकानों को खोलने का उल्लेख किया है । मैं तो चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों को अनाज सस्ते दामों पर मिले, चाहे हमें उस में कुछ हानि भी क्यों न उठानी पड़े । परन्तु प्रश्न यह है कि अन्न मिलेगा कहां से ? राशन की व्यवस्था करने में रेलवे कर्मचारियों के लिये कोई अलग तरीका नहीं अपनाया जा सकता । यदि कोई ऐसा अवसर मिला, जिस से कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता हो तो, मुझे ऐसा करने में हर्ष ही होगा ।

वातानुकूलित (एयरकंडिशंड) रेलगाड़ियों में भी वृद्धि की जा रही है । हालांकि इस में पुर्ज़ों को आयात करना पड़ता है जिस के लिये विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ती है । फिर भी हम ऐसी गाड़ियों की संख्या बढ़ा रहे हैं ।

कलकत्ता में यातायात सम्बन्धी समस्या को भी किसी न किसी प्रकार सुलझाना है । यह अभी विचाररधीन है कि वहां सर्कुलर रेलवे बनाई जाये अथवा भूमिगत रेलवे बनाई जाये । मेरे विचार में इस समस्या को भूमिगत रेलवे से ही हल किया जा सकता है । निर्णय करने में भले ही कुछ समय लग जाये, परन्तु यह सही निर्णय होना चाहिये । दिल्ली में भी जनसंख्या में काफी वृद्धि हो रही है । यहां पर भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा । इस समस्या को हल करने के लिये कोई योजना बनानी पड़ेगी ।

कुछ सदस्यों ने एक बहुत रोचक सुझाव यह दिया है कि रेलवे बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि यह कई झगड़ों की जड़ है । परन्तु यदि हम रेलवे प्रशासन की अन्य प्रशासनों से तुलना करें तो हम पायेंगे कि रेलवे प्रशासन कहीं अच्छा है क्योंकि रेलवे बोर्ड में केवल रेलवे के ही कर्मचारी होते हैं जिन को काफी अनुभव होता है । वे किसी अन्य मंत्रालय से नहीं आते जैसा कि दूसरे मंत्रालयों में अधिकारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेज दिया जाता है । अतः वे अपने कार्य में दक्ष होते हैं और इसके फलस्वरूप वहां का प्रशासन बड़े अच्छे ढंग से चलता है । रेलवे बोर्ड बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है, ऐसा मेरा अनुभव है ।

राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है । इस परिषद द्वारा दिये गये सुझावों को हम बहुत महत्व देते हैं । इस के प्रयत्नों के फलस्वरूप हमने प्रशासनकि ढांचे में कई परिवर्तन किये हैं ।

[श्री स० का० पाटिल]

भोजन-व्यवस्था के बारे में दो राय है । कुछ कहते हैं कि सरकारी भोजन व्यवस्था अच्छी है और कुछ कहते हैं कि गैर-सरकारी भोजन व्यवस्था अच्छी है क्योंकि इस में मुकाबले की भावना होती है । मेरे विचार में जिस अर्थव्यवस्था में मुकाबला हो वह अर्थव्यवस्था ही प्रगति कर सकती है । मेरा तो सुझाव यह है कि गैर-सरकारी भोजन व्यवस्था के मुकाबले में वैभागिक भोजन व्यवस्था की श्रेष्टता दिखाई जाये । ऐसा कदम उठाने के सम्बन्ध में प्रयोक्ताओं तथा अन्य लोगों ने मुझे बहुत अच्छी मंत्रणा दी है और मैं इस में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं ।

एक बार हम ने रेलवे कर्मचारियों को विशेष प्रकार के कपड़े की वर्दियां पहनने का आदेश दिया था; परन्तु वर्दियां काफी देर तक नहीं चलीं हालांकि कपड़ा अच्छा था । उन को देर तक चलने वाले कपड़े की वर्दियां दी जायेंगी जिससे वे चुस्त दिखाई दें ।

हम केवल रेलगाड़ियां और मालगाड़ियां ही नहीं चलाते अपितु इसके अतिरिक्त हमारी अन्य भी ज़िम्मेदारियां हैं। स्कूल कालेज और अस्पताल चलाने के अलावा खेलों को प्रोत्साहन देना और खेल-स्टेडियम बनाना ये सब कार्य भी करते हैं। टोक्यो में जो खेल हुए थे उसमें स्वर्ण-पदक को जीतने का श्रेय रेलवे कर्मचारियों को ही है । हम इन गतिविधियों को और भी बढ़ा रहे हैं और खेलों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को और भी अच्छी सुविधायें दे रहे हैं जिस से वे और भी अच्छी प्रकार से कार्य करें।

श्री सोनावाने ने नये ज़ोन के प्रश्न का उल्लेख किया है । इन ज़ोनों के कारण से अभी डरने की कोई बात नहीं है । परन्तु उनका विचार है कि यदि यह डिवीज़न कहीं और स्थापित की जायेंगी तो शोलापुर नष्ट हो जायेगा । ऐसा संचालन कार्यपटुता को सुधारने की दृष्टि से किया जाता है और किसी विशेष क्षेत्र की दृष्टि से नहीं । क्योंकि यदि क्षेत्रीय आधार पर ऐसा करने लगें तो प्रत्येक राज्य चाहेगा कि वहां ज़ोन होना चाहिये, जिसके लिये मैं तैयार नहीं क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता और न ही इसमें संचालन-कार्य कुशलता का ही प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है । सर्वश्री बासप्पा और सोनावाने के बीच हुई झड़प बड़ी विचित्र थी । उनमें से एक ने कहा "आप दें" और दूसरे ने कहा कि "मैं लूंगा" जैसे रेलवे मंत्रालय इस मामले में कहीं है ही नहीं । यदि हम इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर की गईं मांगों को पूरा करने लगें तो दक्षिण रेलवे का सब कार्य अस्तव्यस्त हो जायेगा । यदि बम्बई में दूर दूर से लोग आ सकते थे तो क्या शोलापुर के लोग हैदराबाद नहीं जा सकते । मैं नहीं समझता कि यदि वे ऐसा करेंगे तो कोई अनर्थ हो जायेगा । जहां तक भर्ती के अवसरों पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे सेवा-आयोग बम्बई में ही रहेगा अतः भर्ती संबंधी सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फिर शोलापुर का सारा ज़ोन तो नहीं जा रहा है । उसका थोड़ा भाग ही नये ज़ोन में जा रहा है । शेष भाग इसी ज़ोन में ही रहेगा । मैं माननीय सदस्य को पुनःविश्वास दिलाता हूं कि इससे भर्ती तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा । मेरे माननीय मित्र श्री सोनावाने ने कहा कि 1952 में विश्वास दिलाया गया था कि मज़दूर संघों के परामर्श के बिना कोई पुनर्गठन नहीं किया जायेगा । जो कुछ उस समय कहा गया था वह मुझे रिकार्ड में मिल गया है ।

श्री सोनावाने : (पेंढ़रपुर) : ऐसा वचन हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने आयव्ययक पर चर्चा के दौरान दिया था ।

श्री स० का० पाटिल : ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था । ऐसा कहा गया था कि ज़ोनों के बनाने के फलस्वरूप छंटनी नहीं करने दी जायेगी और सेवा शर्तों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा । इसके लिये मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं होने दिया जायेगा । परन्तु क्षेत्रीय आधार पर ज़ोन बनाना खतरे से खाली नहीं है । हमारा विचार एक और ज़ोन बनाने का भी है और अन्ततः 10 ज़ोन हो जायेंगे । परन्तु यह ज़ोन केवल संचलन कार्यपटुता में सुधार लाने के लिये बनाया जायेगा ।

श्री सोनावाने : परन्तु इस मामले का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने में डर क्यों लगता है ?

श्री स० का० पाटिल : उन सभी समितियों से, जिनका मेरे माननीय मित्र सुझाव देना चाहते हैं, रेलवे वाले कहीं अधिक विशेषज्ञ हैं । अतः वे हम सब से अधिक जानते हैं कि कौनसा जोन बनाया जाये ।

श्री बासप्पा (तितुर) : पश्चिमी तट का विकास करने के लिये हुबली में मुख्यालय स्थापित करना बहुत ही अच्छा रहेगा, यदि माननीय मंत्री इस मामले को सही रूप में देखें ;

श्री स० का० पाटिल : यह माननीय मित्र द्वारा दिये गये पहले सुझाव से मेल नहीं खाता ।

श्री शिकरे : (मरमागावा) : मुल प्रस्ताव गुंतकल्ल के बारे मेंवश न कि हुबली के बारे में?

श्री स० का० पाटिल : पहले कि मैं अपना भाषण खतम करूं । मैं पम्बन पुल का उल्लेख करना चाहता हूं । यह एक प्राकृतिक विपत्ति थी और इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं था । इंजीनियरों ने जिस कार्यकुशलता से इस पुल को पुनःस्थापित किया है उसकी सभी ने सरहना की है । यह कहा गया है कि ड्राइवर रेलगाड़ी नहीं ले जाना चाहता था । पता नहीं यह जानकारी कहां से प्राप्त की गई है । रेलगाड़ी जो नष्ट हो गई थी उसका पुल से कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तव में रेलगाड़ी पुल पर नहीं थी ।

श्री प्रिय गुप्त : माननीय मंत्री गलत कह रहे हैं । इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिये ।

श्री स० का० पाटिल : कृपया माननीय सदस्य वह सुनें जो मैं आगे कहने वाला हूं ।

श्री प्रिय गुप्त : (कटिहार) : न्यायिक जांच होनी चाहिये ।

श्री स० का० पाटिल : इस मामले में पुल और रेलगाड़ी में कोई सम्बन्ध नहीं था । व रेलगाड़ी पुल पर नहीं थी । किसी ने ऐसा जान बूझकर नहीं किया था कि कोई व्यक्ति ज्वार-भाटकीय तरंगों की लपेट में आ जाये । मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से महाप्रबन्धक तथा उसके कर्मचारीवृन्द का, जिन्होंने इस असाधारण कार्य को जिसमें पुल पुनः स्थापित करने की सम्भावना थी 6 मास की बजाये 44 दिन के बहुत थोड़े ही समय में पूर्ण कर लिया, बहुत धन्यवाद करता हूं । मुझे पूर्ण आशा है कि रेलवे प्रशासन के अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी ऐसी भावना और लग्न से कार्य करेंगे और हमें रेलवे में पूर्ण सफलता मिलेगी जिस पर हम गर्व कर सकेंगे ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965-66

DMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1965-66

वर्ष 1965-66 के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,18,64,000
2	विविध व्यय	3, 63,63,000
3	चालू तथा अन्य लाइनों के लिए भुगतान	34,13,000
4	कार्यवहन व्यय--प्रशासन	52,68,93,000
5	कार्यवहन व्यय--मरम्मत और सधारण	167,73,90,000
6	कार्यवहन व्यय--संचालक कर्मचारी	106,78,34,000
7	कार्यवहन व्यय--संचालन (ईंधन)	107,76,66,000
8	कार्यवहन व्यय--कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त संचालन	32,00,17,000
9	कार्यवहन व्यय--विविध व्यय	29,97,17,000
10	कार्यवहन व्यय--श्रम कल्याण	20,17,16,000
11	कार्यवहन व्यय--अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग	85,00,00,000
11-क	कार्यवहन व्यय--पेंशन निधि में विनियोग	12,10,00,000
12	सामान्य राजस्व को भुगतान	115,90,17,000
13	चाल लाइन के काम (राजस्व)	11,00,00,000
14	नई लाइनों का निर्माण	65,82,32,000
15	चालू लाइन निर्माण-कार्य--पूंजी, अवक्षयण रक्षित निधि तथा विकास निधि	519,01,64,000
16	पेंशन सम्बन्धी प्रभार--पेंशन निधि	3,12,40,000
18	वि ास निधि में विनियोग	29,23,67,000

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा: (आनन्द) : माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि बम्बई और दिल्ली के बीच चलने वाली वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी को दैनिक कर दिया जाये क्योंकि ऐसा करने से यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी । इस गाड़ी में डाइनिंग कार को भी बड़ा कर दिया जाना चाहिये क्योंकि इस समय इसमें बैठने का स्थान बड़ी प्रतीक्षा करने के बाद मिलता है ।

बड़ोदा से नई दिल्ली के लिये 37.25 रु० किराया लगता है और नई दिल्ली से बड़ोदा के लिये 37.40 रु० किराया लिया जाता है। इन दोनों किरायों में 15 पैसे का अन्तर है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

पुरानी बी० बी० सी० आई० और जी० आई० पी० रेलवे लाइनों पर रेलवे बाड़ बिलकुल साफ हो गई है। रेलवे की भूमि में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिये वहां बाड़ लगाई जानी चाहिये ।

कई स्टेशनों के नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे कि बड़ौदा को अंग्रेजी में बरोदा, हिन्दी में बड़ौदा और गुजराती में बड़ोहदा कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। एक स्टेशन का नाम एक ही तरीके से बोला जाना चाहिये। मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की ओर ध्यान दे।

पुर्वी अफ्रीका से अनेक भारतीय भारत में आ रहे हैं जो कि पहले रेलवे कर्मचारी थे। मंत्रालय को उन को नौकरी देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। वे लोग प्रशिक्षत हैं और उनको रेलवे के काम का अनुभव भी है।

कर्मचारियों द्वारा रेलगाड़ियों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये सुझाव देने के लिये नकद इनाम देने का सुझाव है। अनेक विदेशी और भारतीय फर्मों ने भी इसकी सिफारिश की है। रेलवे प्रशासन को उपयोगी सुझाव देने के लिये कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और नकद इनाम दिये जाने चाहिये।

आजकल भी स्टेशनों पर पुरानी टिकटें दी जाती हैं। राजकोट नगर पालिका के प्रधान को शापुर रेलवे स्टेशन से टिकट दी गई। जिसपर स्टेशन का नाम था जूनागढ़ और किराया लिखा हुआ था 5 रु० 12 आने। और रेलवे का नाम दिया हुआ था जूनागढ़ स्टेट रेलवे। अभी तक भी ये अनियमितताएं चल रही हैं। इस स्टेशन का नाम 1948 में ही बदल दिया गया था। यह समाचार 2–3–64 के एक अखबार में था।

[श्री सोनावाने पीठासीन हुए]

[**Shri Sonavane** *in the chair*]

हमारे देश में नैरो गाज की लम्बाई 4320 किलोमीटर है। फरवरी, 1965 को भारतीय रेल पत्रिका में एक भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी ने सुझाव दिया है कि यदि ये लाइनें अलाभप्रद हैं तो इनके स्थान पर बसों को चलने दिया जाये। बम्बई में भी पुरानी ट्राम गाड़ियों को हटा कर बसें चलाई गई थीं और वे बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। रेलवे मंत्रालय को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये।

नई लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में हमें गुजरात की विभिन्न पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

रेलवे भारिकों के साथ इनसानों जैसा सलूक किया जाना चाहिये। उनके लिये की गई चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। एक भारिक 70 वर्ष की आयु के बाद काम नहीं कर सकता है। उनको सहकारी समितियों में संगठित किया जाना चाहिये। उनके लिये भविष्य निधि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मंत्रालय को किसान विशेष गाड़ियों की संख्या भी बढ़ानी चाहिये और इस में पहले से अधिक रियायतें दी जानी चाहिये।

यह ठीक है कि विदेशी पर्यटकों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिये। विदेशी पर्यटक गाड़ियों में 4–5 संवाहक चलते हैं। परन्तु भारतीय पर्यटकगाड़ियों में एक भी संवाहक नहीं चलत है। ऐसा नहीं होना चाहिये। किसान विशेष गाड़ियों के साथ भी संवाहक चलने चाहिये। उनमें अच्छे डिब्बे लगने चाहिये और उनमें बिजली पानी का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये।

[श्री नरेन्द्र सिंह महाडा]

कुछ समय पहले भारतीय रेलवे ने ताज एक्सप्रेस द्वारा 200 गूंगे और बहरे लड़कों के लिये मुफ्त दौरे का प्रबन्ध किया था। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्रालय हमारी गरीब पीड़ित जनसंख्या के लिये इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाता रहेगा।

सरकार को बिना टिकट यात्रा को रोकना चाहिये और इस प्रकार के राजस्व में घाटे को होने से रोकना चाहिये। खासकर विद्यार्थियों से इस मामले में होशयारी से काम लेना चाहिये।

तीसरी श्रेणी के यात्रियों को सुविधाएं देने के लिये संसद् की प्राक्कलन समिति ने अनेक सुझाव दिये हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। परन्तु उन को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गाड़ियों में इतनी भीड़ चलती है कि लोगों को पायदानों पर खड़ा होना पड़ता है और छतों पर बैठना पड़ता है। यदि सरकार अधिक गाड़ियां और डिब्बे नहीं दे सकती है तो उसे चाहिये कि माल डिब्बों को सवारी गाड़ियों में जोड़ दे और उनमें बैठने के लिये बैंचें रख दी जानी चाहियें। सरकार को स्थान आरक्षण के यंत्रीकरण की जापानी पद्धति पर विचार करना चाहिये।

भोजन व्यवस्था के मामले में मेरा यह सुझाव है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को होने दिया जाये ताकि हमें अच्छा भोजन मिल सके।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये रूस के तरीके लागू करने का भी सुझाव है। यह तरीका ऐसा है कि प्रत्येक डिब्बे में एक टिकट निरीक्षक होता है नाकि सारी गाड़ी में एक निरीक्षक। इससे बिना टिकट यात्रा की काफी कम संभावना रह जायेगी।

प्राक्कलन समिति ने और भी अनेक सुझाव दिये हैं जिनके ब्यौरे में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इनकी जांच करेंगे।

श्री म० ला० जाधव (मालेगांव): सभा के सामने जो मांग हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और मंत्रालय के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मध्य रेलवे पर भारी यातायात के दबाव को दूर करने के लिये एक दैनिक जनता गाड़ी चलाई जानी चाहिये। इस समय उस लाइन पर कोई जनता गाड़ी नहीं चलती है।

भूसावल और इगतपुरी के बीच गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को दूर करने के लिये एक शटल गाड़ी चलाने की जरूरत है।

इस समय बम्बई से माल लेकर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलती हैं और कलकत्ता दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों पर माल उतारती हैं। यह आवश्यक है कि अन्य बड़ी मण्डियों से भी ऐसी गाड़ियां चलाई जानी चाहियें। इस समय सड़क परिवहन द्वारा सब्जियां और अन्य खराब होने वाली वस्तुएं ले जाई जाती हैं।

यदि रेलवे माल को तेजी से ले जाने की सुविधा दे दे तो वह काफी आय अर्जित कर सकती है।

मेरे क्षेत्र में माल डिब्बों की कमी नहीं है, परन्तु फिर भी प्याज के ले जाने के लिये माल डिब्बे नहीं दिये जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि डिब्बे देने के लिये पैसे मांगे जाते हैं। यह एक बुरी चीज है और इसको दूर किया जाना चाहिये।

अब मैं जल व्यवस्था को लेता हूं। मनमाद एक बड़ा जंकशन है, परन्तु वहां पर पीने के पानी की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है। कई बार अभ्यावेदन दिये गये हैं। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कासलागांव की भी यही हालत है। रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को गर्मियों में पानी नहीं मिलता। इन स्टशनों पर स्थायी जल व्यवस्था की जानी चाहिये।

इगतपूरी एक पहाड़ी स्थान है। परन्तु वहां के रेलवे मजदूरों को पहाड़ी स्टेशन का भत्ता नहीं दिया जाता है जब कि लोनावाला और माथरोन और अन्य स्थानों पर यह भत्ता दिया जाता है। उन मजदूरों ने अनेक बार अभ्यावेदन दिये हैं। इनको यह भत्ता दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार के मजदूरों को भी पानी की कमी के कारण पानी का भत्ता मिलता है।

नासिक एक तीर्थ स्थान है और वहां पर काफी यात्री आते हैं। उस समय वहां पर स्टेशन के दक्षिण की ओर एक ही पुल है। या तो उत्तर को और भी एक पुल होना चाहिये या इस पुल को बीच में भर दिया जाना चाहिये ताकि यात्रियों को स्टेशन पार करने में सुविधा मिले। इस स्टेशन पर खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं हैं। यहां पर जो लोग आते हैं वे प्लेटफार्म पर खाना बनाते हैं और वहीं खाते हैं। रेलवे को यात्रियों को खाना बनाने का एक सामूहिक स्थान देना चाहिये उस स्टेंशन पर जल व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिये।

Shri Radhey Lal Vyas (Ujjain): I rise to support the demands relating to Railway. The Madhya Pradesh is the only state which has been effected most adversley by the reorgnisation of the states from the point of view of means of communications.

The States Reorganisation Commission had recommended in thier report at page 130.

हमें बताया गया है कि उज्जैन अथवा इन्दोर ग्वालियर के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। तथापि, हम समझते हैं कि रेलवे बोर्ड ग्वालियर से उज्जैन तक एक नई लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

It is true that construction of this line has been taken up but I have one complaint and that is that even this amount granted in the budget this year has not so far been spent. That money is being spent on some other construction works. Why it is so ?

The States Reorganisation Commission in their report further says.

हम खासतौर से यह कहना चाहते हैं कि जबलपुर को ललितपुर अथवा झांसी से मिला दिया जाना चाहिये।

The States Reorganisation Commission have given recommendations for improving the means of Communication only with respect to Madhya Pradesh and no other state. But these recommendations have not been implemented so far. There is no mail train in our state for coming from Bilaspur, Raipur, Ujjain, Ratlam, In dore etc or for going to Gujarat.

[Shri Radhey Lal Vyas]

A part from mail trains, whether passenger traines are there, they move very solwly. Thier speed should be increased.

The Railway Board should be instructed to accelerate the work on Guna Maksi line. The Railway line from Guna should be extended upto Gwalior.

The distance between Bhind and Gwalior is about 25 miles which is linked by narrow gauge. This narrow gauge should be replaced by broad guage. It will bring more profits to railway.

The present narrow gauge line between Gwalior and Shiva Puri should also be replaced by broad gauge and better, extended up to Swai Madhopur or Kotah. This will make the travelling easy for the passengers.

One narrow gauge line between Ujjain and Agara is running into deficit. Serveral times it has been brought to the notice of the Government but it has not been looked into. This line can be made profitable it is extended upto Jhalawar Road, Katni or Shyamgarh.

Panna, Chhatarpur etc are the three districts which are not touched by railway at any place. Harpalpur, Chhatarpur, Khujraho, Panna should be lined with Katni Allahabad Section at Satna, Katni or Damoh so that it can cover all the three districts. This will be in consonance with the recommendations of the States Reorganisation Commission. The construction of a railway line from East to West in Vindhya Pradesh is very much necessitated.

The work on the Delhi Rajura Bhillai line is in progress. Will it not be more profitable to extend this line upto Jagdalpur ? Baster Distt. which is rich in mineral wealth is also in Jagdalpur. These minerals cannot be exploited in the absence of good means of communications.

A Railway line should be constructed from Khandwar to Dohad or from Indore to Dohad for the transportation of fruits, vegetables, cotton oilseeds and other products from the areas fulling between the said two points.

The area between Chhindwara and Paasia is rich in coal. The narrow gauge at present there should be converted into broad gauge and extended up to Nagpur.

The eighty mile narrow gauge track between Nagpur and Chhindwara and Nayanpur should also be replaced by broad gauge. It is very important to do so to help farmers to sell their produce at better rates.

Raipur Chhindwara narrow gauge should also be converted into broad gauge

One additional Janta Express should be started on Central Railway to relieve passengers of overcrowding in traines and if it is not possible one additional train from Atarsi to Agra must atleast be started.

The question of starting one more train between Baroda and Mathura should also be considered as at present there are only traines on this route, the Froniter Mail and Dehradun Express. There is no third class in the Frontier Mail and Dehradun Express. There only two bogies which are not sufficient to cope with the traffic needs.

There is need to start a Express Train from Allahabad to Ahmedabad *via* Naga, Bhopal, Veena, Katni. The present passenger train running between Ahmedabad and Bhopal should be made an express train.

Similarly a new train should be started from Durgapur, Raipur, Bilaspur to Bhopal. One train should also be started from Durg, Raipur, Bilaspur Katni to Delhi *via* Allahabad, Kanpur Tundla, Agra so that the passengers coming from distant places can catch a direct train.

One Devas-Indore shuttle has been introduced. I am surprised to note that it takes passengers only from one side and while returns back empty. Why there is no booking on the other side.

The direct train running from Ratlam to Bhopal should be connected with Pathankot. In the absence of this connection people are experiencing great difficulty.

The Indore Bilaspur Express Sleeper coach should be extended upto Indore or at least upto Ujjain so that people can make use of the sleeper coach.

The Raipur Vishakhapatnam passenger train should leave Raipur Station at 6 A.M. and not at 3 A.M. as at present since there are no passengers there at 3·00 A.M. It should leave after the Nagpur Jharsujuda train and Howrah Bombay Express have left.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराये में 80 किलोमीटर तक के लिये 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और प्रथम श्रेणी और वातानकुलित श्रेणी के किरायों में 1000 किलोमीटर तक के फासले के लिये 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि अमीर लोगों पर इस वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रथम श्रेणी में चलने वाले लोगों को कम्पनियों अथवा सरकार से यात्रा भत्ता मिल जाता है और उनको अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ता है। बेचारे गरीब लोगों को अपने घरों से काम की जगह तक ही गाड़ियों में जाना पड़ता है और उनके लिये यह 10 प्रतिशत की वृद्धि भी सहन करना बहुत कठिन है। उनपर इस वृद्धि का काफी बोझ पड़ेगा। इसलिये माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि वह अब भी इस पर विचार करे।

कलकत्ता और बम्बई के मासिक टिकटों के किरायों में भी वृद्धि की गई। इन दोनों शहरों में बहुत बड़ा उपनगरीय क्षेत्र है और बड़ी संख्या में लोग इन शहरों में प्रति दिन आते हैं। प्रत्येक परिवार में लगभग 4–5 मासिक टिकट वाले होते हैं, जिनमें स्कूल और कालिज जाने वाले विद्यार्थी भी आ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परिवार पर लगभग 2–3 रु० महीने का अतिरिक्त बोझ पड़ जायेगा इन लोगों के लिये इस अतिरिक्त भार को सहन करना बहुत कठिन है। उनकी ओर से मैं निवेदन करती हूं कि किरायों में ये दरें न बढ़ाई जायें। माननीय मंत्री ने इसके लिये यह दलील दी है कि ऐसा इसलिये किया जा रहा है कि वहां की दरें मद्रास के बराबर हो जायें। मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि दरें बराबर ही करनी हैं तो कृपया मद्रास की दरें कम करके बराबर कर दीजिये।

कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे बनाने की बात काफी समय हो चल रही है। परन्तु अभी तक कोई निश्यय नहीं किया गया। कलकत्ता एक राष्ट्रीय महत्व का शहर है और

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

उसकी समस्या हमारे देश की समस्या है। कलकत्ता भारत का सब से बड़ा शहर है और एक बड़ा पत्तन भी है। मेरी अपनी राय तो यह है कि वहां पर भूमिगत रेलवे होनी चाहिये क्योंकि यह आधुनिक तरीका है। सरकार को वित्तीय जिम्मेवारी लेने का वायदा करना चाहिये और शीघ्र इस काम को करना चाहिये।

रेलवे बिजली लगाने के कार्य में काम करने वाले सारे कर्मचारी नैमित्तिक अस्थायी कर्मचारी हैं। उन सबको स्थायी कर देना चाहिये। जब बिजली लगाने का काम समाप्त हो जाय तो इनको अन्य क्षेत्रों में काम पर लगा दिया जाये।

अदक्ष और अर्धदक्ष मजदूरों की भी बड़ी संख्या है। मैं समझती हूं कि सभी ऐसे मजदूरों को, जिन्होंने 6 मास तक सेवा कर ली हो, स्वास्थ्य, अवकाश आदि की वे सब सुविधाएं दी जायें जो स्थायी मजदूरों को दी जाती हैं। फिर अस्थायी मजदूरों को वरिष्ठता के आधार पर स्थायी पदों पर लगाने के लिये एक तालिका होनी चाहिये। नई भर्तियों और पदोन्नतियों के प्रश्न की जांच करने के लिये एक संयुक्त समिति होनी चाहिये।

नैमित्तिक मजदूरों को मजूरी निम्नतम मजूरी के आधार पर दी जाती है। वास्तव में यह निम्नतम मजूरी वह है जो आज से 10 वर्ष पहले एक कृषि मजदूर की थी। नैमित्तिक मजदूरों के लिये इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। खड़गपुर में एक पुरुष मजदूर को 45 रु० महीना दिया जाता है और स्त्री को 37.50 रु० मास। इतने थोड़े से पैसों में उनका गजारा कैसे हो सकता है? बिजली लगाने के काम में लगे मजदूरों पर केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रम शीघ्र लागू कर दिये जाने चाहियें।

बेलफोरिया एक बहुत बड़ा स्टेशन है जहां से कि बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन कलकत्ता आते हैं। रेलवे लाइन इस नगर को दो भागों में बांटती है। वर्तमान रेलवे फाटक को हटा कर सड़क का पुल बनाने का सुझाव था। इस फाटक पर यातायात को कभी-कभी घंटे भर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब हमें बताया जाता है कि यह पुल नहीं बनाया जा रहा है। यह पुल बनाना अत्यावश्यक है। इसके बिना यातायात को काफी कष्ट उठाना पड़ता है।

बेल्गफोरीया नगरपालिका के लोगों के लिये बड़ानगर रेलवे स्टेशन जाने के लिये कोई उपागमन सड़क नहीं है और इसके लिये नगरपालिका का एक छोटे मार्ग से सडक बनाने का प्रस्ताव है इसके लिये स्टेशन के उत्तरी और पूर्वी और कुछ रेलवे भूमि आवश्यक है। इससे बड़ानगर रेलवे स्टेशन की आय काफी बढ़ जायेगी।

दमदम जंकशन स्टेशन पर एक ऊपरी पुल और प्लेटफर्म पर एक प्रतीक्षालय एंव टिकटघर बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है लेकिन अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। पूर्वी क्षेत्र को मिलाने के लिये वहां एक ऊपरी पुल बनाया जाए।

दमदम छावनी में ऊपरी पुल को बढ़ाया जाए जो प्लेटफर्म संख्या 3 को प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 से मिलाये जिस पर स्टेशन के बाहार जाने का रास्ता हो।

जगतदल में एक 'हाल्ट' बनाने की आवश्यकता है। अब यह क्षेत्र बहुत विकसित हो गया है वहां पर नीतागढ़, श्यामनगर आदि से बड़ी संख्या में जूट मिलों में काम करने वाले कर्मचारी आते हैं। इससे उन्हें बड़ी सहयता मिलेगी।

जहां तक न्यू बैरकपुर हाल्ट का सम्बन्ध है, वहां पर एक लेवल क्रासिंग अथवा ऊपरी पुल बनाया जाय और इस स्टेशन का स्तर बढ़ा कर इससे पूर्णांग स्टेशन बनाया जाए।

हसनाबाद–बारासात स्टेशन पर गाड़ियां, डिब्बे और इंजन बड़े पुराने है। वहां पर काफी-काफी समय तक गाड़ी के लिए इंतजार करना पड़ता है। वहां पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, उनकी रफ्तार में वृद्धि की जाए और समय में सुधार किए जाए। हसनाबाद–सियालदह मार्ग पर डीजल के इंजिन चलाए जाएं।

रेलवे कर्मचारियों की नौकरी में कई अनियमिततायें हैं। स्थायी और अस्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों के सभी मामलों पर विचार के लिए एक मजूरी बोर्ड बनाया जाए।

श्रमिकों के लिए सस्ते अनाज की दुकानें खोली जाएं। श्रमिक परामर्शदाता समिति ने यह सुझाव दिया था कि जिस किसी उद्योग में 300 से अधिक कर्मचारी हों वहां मालिक सस्ते अनाज की दुकानों की व्यवस्था करें।

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :–

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	18	श्री दशरथ देव	रेल किराये और माल भाड़े की दरों में की जाने वाली वृद्धि	100 रुपये
1	19	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	भाड़े की दरों में वृद्धि .	100 रुपये
1	20	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	दुर्गापुर कांग्रेस अधिवेशन के लिए विधान राय स्टेशन बनाना और उसे नष्ट करना	100 रुपये
1	21	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	सम्मेलनों और कांग्रसों के आयोजन के लिए दी गई रियायतें	100 रुपये
1	22	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	रेल कर्मचारियों के लिए अनाज की सस्ती दुकानें खोलने की आवश्यकता	100 रुपये
1	23	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	बिजली से रेलें चलाने वाले कर्मचारियों को छः महीने की सेवा पूरी हो जाने के बाद स्थायी बनाने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	24	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	पूर्व रेलवे में बेलघरिया स्टेशन के फाटक 1 पर ऊपर से सड़क वाली क्रासिंग बनाने की आवश्यकता·	100 रुपये
1	25	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	जगतसाल में श्यामनगर और कांकिनाडा स्टेशन के बीच विराम स्थान बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
1	26	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	कलकत्ता के लिए एक वृत्ताकार अथवा भूमिगत रेलवे बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
1	27	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	पूर्व रेलवे में डमडम जंक्शन स्टेशन के दक्षिण की ओर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
1	28	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	डमडम जंकशन स्टेशन पर रेलवे पुल से गुज़रने वाले लोगों का चलती हुई गाड़ियों के कोयले और चिनगारियों से संरक्षण	100 रुपये
1	29	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	यात्री-किराये में खास कर तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि	100 रुपये
1	30	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	कलकत्ता और बम्बई में माहवार मौसमी टिकटों में वृद्धि	100 रुपये
1	31	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	गंगा के दूसरी ओर उत्तर सीमा रेलवे की गाड़ियों को जोड़ने के लिए बी० बी० लूप से होकर हावड़ा से फरक्का तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता	100 रुपये
1	32	श्री यशपाल सिंह	सभी राष्ट्रीय राजपथों पर लेवल क्रासिंग बनाने में असफलता	100 रुपये
14	33	श्री यशपाल सिंह	रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा करने में असफलता	100 रुपये
14	34	श्री यशपाल सिंह	सवारी गाड़ियों की समय अनसूची का पालन करने में असफलता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
14	35	श्री यशपाल सिंह	वाणिज्यिक लिपिकों की नौकरी की हालतों में सुधार की आवश्यकता	100 रुपये
14	36	श्री यशपाल सिंह	तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं देने में असफलता	100 रुपये
14	37	श्री यशपाल सिंह	तीसरे दर्जे के डिब्बों के ठीक रख-रखाव और सफाई की आवश्यकता	100 रुपये
14	38	श्री यशपाल सिंह	रुड़की रेलवे स्टेशन पर मुख्य प्लेट-फार्म को गोदाम से जोड़ने वाला एक ऊपरी पुल बनाने में असफलता	100 रुपये
1	39	श्री यशपाल सिंह	स्टेशनों पर छत (शेड) बनाने में असफलता	100 रुपये
1	40	श्री यशपाल सिंह	स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधाएं देने में असफलता	100 रुपये
1	41	श्री यशपाल सिंह	रेल कर्मचारियों के लिए अनाज की दुकानें खोलने में असफलता	100 रुपये
1	42	श्री यशपाल सिंह	भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफा-रिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	100 रुपये
1	43	श्री यशपाल सिंह .	उत्तर रेलवे के रुड़की रेलवे स्टेशन पर टांगा शेड बनाने में असफलता	100 रुपये
1	44	श्री यशपाल सिंह	देहरादून और रुड़की के रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष बनाने की आव-श्यकता	100 रुपये
4	49	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
8	52	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	पूर्व रेलवे के बन्देल/कटवा सबर्बन सेक्शन में बिजली से रेल चलाना	100 रुपये
8	53	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	बारासेट-बसिरहाट सेक्शन में अधिक रेलगाड़ियां चलाना और इसे लाइन पर डीज़ल से गाड़ियां चलाना	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
10	54	श्री दशरथ देव	खड़गपुर डिविजन, दक्षिण पूर्व रेलवे, में अस्थायी और आकस्मिक श्रमिकों की भारी छंटनी	100 रुपये
10	55	श्री दशरथ देव	खड़गपुर डिविजन, दक्षिण पूर्व रेलवे के उन आकस्मिक और अस्थायी श्रमिकों को जिनकी छंटनी की गई है, मुआवजे की अदायगी न करना	100 रुपये
10	56	श्री दशरथ देव	स्थायी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के आकस्मिक श्रमिकों को मजूरी की दर में तदनुरूप वृद्धि की आवश्यकता	100 रुपये
10	57	श्री दशरथ देव	दक्षिण पूर्व रेलव के स्टोर्स और लोको शेड जैसे विभागों में स्थायी रूप के काम के लिये ठेके के मजदूर रखने की प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता	100 रुपये
10	58	श्री दशरथ देव	रेलों में शंकरसरन पंचाट की क्रियान्विति	100 रुपये
14	59	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	पश्चिम बंगाल में बलूरघाट से सम्बन्ध जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	60	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे के हरिपाल और हिन्द मोटर स्टेशनों पर अप प्लेटफार्मों पर छत बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	61	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे की एच० बी० कॉर्ड लाइन और मेन लाइन के जंक्शन पर बल्ली के पास एक स्टेशन बनाने की आवश्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	62	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	पूर्व रेलवे के सीरामपुर स्टेशनके उत्तर की ओर पैदल चलने वालों के लिए एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	63	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	पूर्व रेलवे में रिशडा, सीरामपुर, उत्तर-पाड़ा, कोन्नागोर, बेगमपुर, हरि-पाल और भद्रेश्वर स्टेशनों पर नल कूप लगाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	64	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	हावड़ा-बर्दवान लाइन के सबर्बन स्टेशन के अप और डाउन प्लेटफार्मों पर शौचालय बनाने की आव-श्यकता	100 रुपये
15	65	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	पूर्व रेलवे के सीरामपुर स्टेशन के उपमार्ग तक 51 प्लेटफार्म का विस्तार करने की आवश्यकता	100 रुपये
15	66	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	पूर्व रेलवे के तारकेश्वर स्टेशन पर तीसरे दर्जे का अधिक बड़ा विश्रामकक्ष बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	67	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	सीरामपुर और विद्यावती लेवल क्रासिंग पर जी० टी० रोड पर सड़क के ऊपरी पुल बनाने की आव-श्यकता	100 रुपये
15	68	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	पूर्व रेलवे के उत्तरापाड़ा स्टेशन के अप-प्लेटफार्म के दक्षिणी सिरे से हिन्द मोटर के पास हरनाथपुर रोड सब-वे तक एक पक्का रास्ता बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	69	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	दक्षिण पूर्व रेलवे के पुरुलिया स्टेशन पर दिन भर पीने का और नहाने का पानी मुहैया करने के लिए उचित व्यवस्था करने की आव-श्यकता	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	70	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	हावड़ा-बन्देल सेक्शन के स्टेशनों पर पेशाबघरों और शौचालयों की नियमित सफाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता	100 रुपये
15	71	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	हावडा के उपनगरीय सेक्शन के लिए और अधिक काउन्टर खोलने की आवश्यकता	100 रुपये
15	72	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे के एच० बी० कार्ड लाइन पर बेगमपुर, बलरामबटी, बरुह-पुर, जंकशन और जनाह रोड के दोनों ही अप और डाउन प्लेट-फार्मों पर छत बनाने और प्लेट-फार्मों को ऊंचा करने की आव-श्यकता	100 रुपये
15	73	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	हावड़ा से बम्बई बरास्ता नागपुर एक जनता एक्सप्रैस और वाल्टेयर से दिल्ली बरास्ता रायपुर, कटनी और बीना एक एक्सप्रैस गाड़ी चालू करने की आवश्यकता	100 रुपये
15	74	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	कलकत्ता में एक वृत्त रेलवे बनाने की आवश्यकता	100 रुपये
15	75	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	पूर्व रेलवे के हावड़ा-बन्देल सेक्शन के सबर्बन सेक्शन में और अधिक ई० एम० यू० चालू करने की आवश्यकता	100 रुपये
15	76	श्री दीनेन भट्टाचार्य .	दक्षिण-पूर्व रेलवे में बांकुड़ा होते हुए हावड़ा से पुरुलिया तक कम से कम एक और सवारी गाड़ी चालू करने की आवश्यकता	100 रुपये
15	77	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे के तारकेश्वर स्टेशन पर विश्राम कक्ष बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	78	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्वोत्तर रेलवे के पुराना माल्दा, सिग-बाद स्टेशनों पर प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	79	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे के प्लासी स्टेशन पर प्लेटफार्म और पैदल चलने वालों के लिए एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	80	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे के ठकुरिया स्टेशन के दक्षिणी सिरे पर दोनों सड़कों को मिलाने वाला पैदल चलने वालों के लिए एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	81	श्री दीनेन भट्टाचार्य	पूर्व रेलवे के बालीगंज स्टेशन के पास, कलकत्ता कसबा और बालीगंज क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	82	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कौकुलिया बस्ती के निवासियों का पूर्व रेलवे द्वारा प्रस्तावित निष्कासन और उन्हें समीपवर्ती क्षेत्रों में बसाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	83	श्री दीनेन भट्टाचार्य	टालीगंज में रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठने वालों का प्रस्तावित निष्कासन और उन्हें समीपवर्ती क्षेत्रों में बसाने की की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	139	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	दिल्ली से बम्बई तक दैनिक डीलक्स रेलगाड़ी चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	140	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	रेलों के प्रशासनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि ।	100 रुपये
1	141	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	लेवल क्रौसिंगों पर अधिक ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	142	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	बड़ौदा में और अधिक विश्राम-गृह बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	143	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	तीसरे दर्जे की सवारी गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ को कम करने और यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	144	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	माल-वाहकों को चिकित्सा-सुविधायें देकर उनकी हालत सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	145	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	अधिक किसान स्पेशल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	159	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	गुजरात में भावनगर को तारापुर जोड़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	160	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	खदाप्पे और रायाचोटी से होकर नंद्याल से तदनपल्ले तक रेलवे लाइन बिछाने में जिसकी 30 साल पहिले छानबीन की गई थी असफलता ।	100 रुपये
14	161	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	समनी को मियागाम कर्जन से छोटी लाइन पश्चिम रेलवे के बड़ौदा सेक्शन से जोड़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	162	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	छोटा रायपुर. पश्चिम रेलवे को जोड़ने वाली अधिक लाइनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	163	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	छोटी लाइन के विकास की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	164	श्री प्रिय गुप्त	रेलवे में सतकता संगठन और सुरक्षा संगठन की कार्यप्रणाली ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
1	165	श्री प्रिय गुप्त	वर्ग 3 और वर्ग 4 के सभी कर्मचारियों को दो कमरों वाली रिहायशी जगह का न दिया जाना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	166	श्री दीनेन भट्टाचार्य	इमारत बढ़ाने के लिए नजदीक की खाली जमीन देने की आवश्यकता और स्वतः रेलवे द्वारा चलाया जा रहा खड़गपुर ट्राफिक स्कूल का विकास ।	100 रुपये
1	167	श्री प्रिय गुप्त	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में राजपत्र घोषित पदों के कर्मचारियों की तरह वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को तीन पेशगी बढ़ोतरियां देने के लिये मंजूरी की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	168	श्री प्रिय गुप्त	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मचारियों को सीमा-भत्ता देने के लिए मंजूरी की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	169	श्री प्रिय गुप्त	रेल कर्मचारियों को अनाज और अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए सहायता-प्राप्त अनाज की दूकानें खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	170	श्री प्रिय गुप्त	रेलवे में आकस्मिक श्रमिक रखने की प्रणाली समाप्त न करना और निर्माण अथवा परियोजना कार्य के बावजूद उन्हें नियमित रेल कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रम देना ।	100 रुपये
1	171	श्री प्रिय गुप्त	वर्ग 4 के कर्मचारियों से जो अन्यथा किराया-माफ क्वार्टरों के अधिकारी हैं, बिजली के किराये और बिजली लगाने के खर्च की कटौती बन्द करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	172	श्री प्रिय गुप्त	वर्ग 2 के राजपत्र घोषित पदों के लिये चुनाव में उपस्थित होने की पात्रता के सम्बन्ध में वर्ग 3 के कर्मचारियों के साथ भेदभाव और सहायक भंडार-नियंत्रक (असिस्टेंट कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स) के पद को गैर-शिल्पिक घोषित करना ।	100 रुपये
1	173	श्री प्रिय गुप्त	मरियानी और बंगई गांव स्कूलों को रेलवे द्वारा अपने अधिकार में न लिया जाना और अलीपुर द्वार जंक्शन और पांडु रेलवे स्कूलों में बहु-प्रयोजनी पाठ्यक्रम का चालू न किया जाना ।	100 रुपये
1	174	श्री प्रिय गुप्त	पूर्व रेलवे में हावड़ा और सियालदा डिवीजनों में और अन्य रेलों में रेलवे लाइसेंस शुदा कुलियों (पोर्टर्स) के सम्बन्ध में रहन-सहन की लागत में बढ़ती हुई वृद्धि को देखते हुए माल ढोने के पारिश्रमिक में वृद्धि न करना ।	100 रुपये
1	175	श्री प्रिय गुप्त	तीसरे दर्जे के डिब्बों में बहुत ज्यादा भीड़ होने की स्थिति को न रोकना और मौसम के दौरान आसाम जाने वाले बिहार के श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधायें ।	100 रुपये
3	176	श्री प्रिय गुप्त	यात्री सुविधाओं और सुधार की व्यवस्था न करना और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के छपरमुख-सिलहट सेक्शन और कटखल-लालाबजार सेक्शन में मानक सुविधाओं वाले क्वार्टर न देना और कम्पनी के प्रबन्ध के अधीन सभी रेलों का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना । ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	177	श्री प्रिय गुप्त	रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता मंजूर न करना ।	100 रुपये
4	178	श्री प्रिय गुप्त	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में मनिहारी घाट और पूर्व रेलवे में सकरीगली के बीच दूसरी स्टीमर फेरी पैसेन्जर क्रासिंग को, तेजनारायणपुर से मनिहारीघाट तक 22 डाउन ट्रेन बढ़ा कर और साहिब गंज, पूर्व रेलवे, तक शटल गाड़ी की व्यवस्था करते हुए सम्बन्ध जोड़ने वाली गाड़ियों के साथ पुनः चालू न करना ।	100 रुपये
5	179	श्री प्रिय गुप्त	कटिहार बड़ी लाइन स्टेशन को मुख्य कटिहार स्टेशन के साथ न जोड़ना ।	100 रुपये
5	180	श्री प्रिय गुप्त	बढ़ते हुए यातायात की व्यवस्था करने के लिए कटिहार जंकशन स्टेशन पर स्टेशन की इमारत को फिर से बनाने और कटिहार स्टेशन पर रिक्शाओं के लिए शेड बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
6	181	श्री प्रिय गुप्त	यातायात में वृद्धि और काम के बोझ में वृद्धि की दर के अनुपात में वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाना ।	100 रुपये
14	182	श्री प्रिय गुप्त	जोगीगोपा, आसाम को महानन्दा नदी पर पुल के साथ गौहाटी, गोलाघाट होते हुए अधिक नजदीकी मार्ग से ऊपरी आसाम को जोड़ने वाली बड़ी लाइनों का न बनाया जाना ।	100 रुपये
14	183	श्री प्रिय गुप्त	त्रिपुरा राज्य को शेष भारत से मिलाने के लिए अगरतला को धरमनगर से मिलाने वाली छोटी लाइनों का न बनाया जाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
14	184	श्री प्रिय गुप्त	. पश्चिम दीनाजपुर जिला मुख्य कार्यालय को रायगंज से मिलाने वाली बड़ी लाइनों का न बनाय जाना ।	100 रुपये
1	189	श्री दीनेन भट्टाचार्य	. साहागंज से बनारसी तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	190	श्री प्रिय गुप्त	. "कॉमन कैरियर" तरीकों की वर्तमान पद्धति में काम करने के लिए वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या और सुविधाओं और वेतन-क्रमों में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	191	श्री प्रिय गुप्त	. वेतन-क्रम, कार्य-विश्लेषण और सेवा की समुन्नत परिस्थितियों के सम्बन्ध में, जिनमें क्रमोन्नति (अपग्रेडिंग) तथा पदोन्नति के क्षेत्र शामिल हैं कैबिन और यार्ड कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतें दूर करके माल-डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	192	श्री प्रिय गुप्त	. वेतन-क्रमों में वृद्धि, क्रमोन्नति, पदोन्नति के मार्ग और कार्य-विश्लेषण और वर्गीकरण आदि के सम्बन्ध में पे-क्लर्कस, श्रॉफस्, सिग्नलर्स, फोरमेन, कैश पियनस्, ट्रेन-कलर्कस, सहायक स्टेशन मास्टर्स/स्टेशन मास्टर्स के ज्ञापनों पर विचार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	193	श्री प्रिय गुप्त	. कार्य-क्षमता बनाये रखने और कम खर्ची के लिए शोलापुर डिविजन को प्रस्तावित नये दक्षिण मध्य रेलवे खण्ड से निकालने की आवश्यकता और गुंटकल डिविजन को नये खण्ड में शामिल करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	194	श्री प्रिय गुप्त	. कार्य-क्षमता बनाये रखने केलिए विशेष पुलिस संस्थापना के अधीन रेलवे सेक्शनल ऑफिसर्स के पदों के लिए स्थायी पदालि बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	195	श्री प्रिय गुप्त	. कार्य-क्षमता बनाये रखने के लिए गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारी (रनिंग स्टाफ) अर्थात् गार्डस ड्राइवर्स, फायरमेन के लिए तीन वेतन-क्रमों में से प्रत्येक में एक तिहाई पद नियत करके क्रमोन्नति आरम्भ न करना और वेतन-क्रमों में वृद्धि न करना ।	100 रुपये
1	196	श्री प्रिय गुप्त	. यात्री टिकट परीक्षकों को गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारी-वर्ग में शामिल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	205	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. रेल कर्मचारियों के लिए एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	206	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. दास आयोग द्वारा महंगाई भत्ते के बारे में सुझाये गये वर्तमान सूत्र का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	207	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे में आकस्मिक श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छंटनी ।	100 रुपये
1	208	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिविजन के अधीन वर्कशाप और चालू लाइन के अस्थाई श्रमिकों की छंटनी ।	100 रुपये
1	209	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिकों की मजूरी की दरें बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	210	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. रेलों में स्थायी रुप से चलने वाले कार्यों के लिये ठेके के श्रमिकों का निरन्तर नियोजन ।	100 रुपये

नाम संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	211	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. दक्षिण पूर्व रेलवे में चीफ मेकेनिकल इंजीनियर के अधीन फोरमैन ग्रेड "सी" के पदों को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	212	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. बिजली से रेल चलाने से सम्बन्धित परियोजनाओं के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	213	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. बिजली से रेल चलाने की परियोजना (रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट) के कर्मचारियों के लिए ऊंची मजूरी तथा रोजगार की सुरक्षा की आवश्यकता ।	100 रुपये
1	214	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. दक्षिण-पूर्व रेल कर्मचारी-संघ के पदाधिकारियों और समिति-सदस्यों की अन्यायपूर्ण पदच्युति और स्थानान्तरण आदेश ।	100 रुपये
1	215	श्री इन्द्रजीत गुप्त	. दुर्गापुर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर विधाननगर रेलवे स्टेशन का अस्थायी निर्माण ।	100 रुपये
1	216	श्री इन्द्रजीत गुप्त	रेल कर्मचारियों के लिए सहायता-प्राप्त अनाज की दुकानें पुनः चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
5	219	श्री प्रिय गुप्त	. ब्रह्मपुत्र पुल के निर्माण के बाद मैरीन आर्गनाइजेशन के समापन की पूर्व कल्पना न करना और कर्मचारियों को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्य विभागों में काम पर रखने की व्यवस्था न करना :	100 रुपये
1	220	श्री प्रिय गुप्त	. रेलवे के मैरीन आर्गनाइजेशन कर्मचारी-वर्ग को परिवहन मंत्रालय के प्रस्तावित गंगा-ब्रह्मपुत्र आन्तरिक-नदी-परिवहन संगठन में अन्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : सभापति महोदय, दिल्ली का बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से पूरा सम्बन्ध बना हुआ है । इसी प्रकार बम्बई का कलकत्ता और मद्रास से सम्बन्ध बना हुआ है । मेरा सुझाव है कि हैदराबाद का, जहां आबादी 15 से 20 लाख है, बड़े नगरों से सम्बन्ध स्थापित किया जाए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

पहले मद्रास और दिल्ली के बीच की लाइन हैदराबाद में से ले जानी थी लेकिन तब निज़ाम ने ऐसा न करने दिया । इस प्रकार हैदराबाद अलग ही रह गया ।

मुझे आशा है कि इसकी स्थिति अब भी वैसी ही नहीं रहेगी और हैदराबाद और दिल्ली के बीच संचार व्यवस्था की जाएगी । अब जो व्यवस्था है उससे हैदराबाद से दिल्ली आने में, जो दूरी मुश्किल से 200 किलोमीटर है, 36 घण्टे लग जाते हैं ।

इस के पश्चात् लोक सभा 10 मार्च, 1965/19 फाल्गुन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 10, 1965/Phalguna 19, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—265 (Ai) LS—6-7-65—500.